• कुलीनों के कुल में कलह • वासनिक की असली परीक्षा

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

www.akshnews.com

प्रशासनिक जमावट

वर्ष 18, अंक-16 16 से 31 मई 2020 मूल्य 25 रूपये

R.N.I. No.HIN/2002/8718 M.P. BPL 642/2018-20

लॉकडाउन में लकडाउन

शराब, डीजल और पेट्रोल के भरोसे राज्य

PRISM
CEMENT
प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस
ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.
PRISM CHAMPION PLUS
PRISM
चैम्पियन प्लस
सीमेंट
HIGHER STRENGTH
DIGITAL PSD
BETTER WORKABILITY
SUPERIOR CONSTRUCTION
Portland Pozzolana Cement (Fly Ash Based)
PRISM JOHNSON LIMITED
Toll free: 1800-3000-1444
Email: cement.customerservice@prismjohnson.in
दूर की सोच®

इस अंक में

प्रशासनिक

9 | प्रशासनिक जमावट

मप्र में सत्ता परिवर्तन के बाद सरकार ने एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। दरअसल, शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री और इकबाल सिंह बैंस के मुख्य सचिव बनने के बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही सरकार...

राजपथ

10-11 | कुलीनों के कुल में कलह

15 माह पुरानी कांग्रेस की सरकार को गिराकर भाजपा ने सत्ता तो हासिल कर ली है, लेकिन कुलीनों के कुल में कलह के कैक्टस उगने लगे हैं। दरअसल, पार्टी का लगभग हर विधायक मंत्री बनना चाह रहा है।

स्वास्थ्य

13 | कैसे होगी कोरोना से जंग...?

मप्र सहित देशभर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उधर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) और स्वास्थ्य मंत्रालय ने आकलन के बाद संकेत दिया है कि जून-जुलाई में कोरोना का संक्रमण चरम पर...

समस्या

15 | राशन तो मिला पीने को पानी नहीं

फूस की झोपड़ी के नीचे हल को कुल्हाड़ी से मरम्मत कर रहे है 55 साल के सुंदर धुर्वे की एक चिंता कई पीढ़ियों से चली आ रही है। चिंता का नाम जल है। दरअसल, मप्र के आदिवासी बहुल जिलों में पीने के पानी की समस्या सबसे बड़ी है। यहां के लोगों का कहना है कि राशन तो आसानी से...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

भारत में इस वक्त अभूतपूर्व आर्थिक मंदी छाई है, जिसे कुछ लोग आर्थिक आपात भी करार दे रहे हैं। मुख्य आर्थिक क्षेत्रों में विकास पूरी तरह सिकुड़ गया है, साथ में घरेलू और ग्रामीण खपत भी कम हो गई है। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी लगभग न के बराबर ही आ रहा है। इसका ग्रामीण गरीबों, शहरी अनौपचारिक क्षेत्र और मध्यम वर्ग पर बहुत बुरा असर पड़ा है। आलम यह है कि राज्यों के पास आय के लिए शराब और डीजल-पेट्रोल ही साधन बचे हैं।

16-17

32-33

38

45

राजनीति

30-31 | भाजपाइयों की परफॉर्मेंस खराब

कोरोना की महामारी के बावजूद भाजपा के समर्थकों के लिए खुश होने के तीन-तीन कारण हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अपने चरम पर है, गृहमंत्री अमित शाह नेपथ्य से पार्टी को चला रहे हैं, और विपक्ष हमेशा की तरह बिखरा हुआ है। फिर भी भाजपा के समर्थक...

छत्तीसगढ़

34 | सपनों के सौदागर

छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत नाजुक बताई जा रही है और फिलहाल वह कोमा में हैं। गत दिनों उन्हें हार्टअटैक आया था, जिसके बाद वो कोमा में चले गए। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री तो रहे ही हैं, आज की तारीख में भी प्रदेश के...

राजस्थान

36 | फिर सुलगने लगी आग

राजस्थान में कोरोना वायरस के संक्रमणकाल में सत्तारूढ़ कांग्रेस में वर्चस्व की आग सुलगने लगी है। जानकारों का कहना है कि कोरोना की स्थिति सुधरने के बाद पार्टी में एक बार फिर से विरोध प्रबल हो जाएगा। दरअसल, उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट...

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

हमारे देश में मौत में भी उत्सवी रंग...

किसी ने ठीक ही कहा है...

मृत्यु दुःख, भय, मुश्किलों से छुटकारा है, जीवन के हर बंधन से, हर परेशानी से मुक्ति है,
मौत को इंसान का मुक्ति दिवस मनाना चाहिए, मौत का भय नहीं, मौत का उत्सव होना चाहिए।

आश्चर्यों से भरे हमारे देश में आजकल मृत्यु का उत्सव मनाया जा रहा है, कोरोना को भी उल्लास के साथ गाया जा रहा है, थालियां और तालियां दोनों बज रही हैं, दीये जल रहे हैं, पटाखे चल रहे हैं। लोग पटापट मर रहे हैं, फिर भी किसी के चेहरे पर भय नहीं दिख रहा है। इस महामारी के दौर में भी लोग दौड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विदेशों में मातम छाया हुआ है। कुछ दिन पहले तक जर्मनी, इटली, अमेरिका में स्थिति इतनी भयानक थी कि वहां की सड़कें लाशों से पटी थीं, लेकिन कोई उन्हें अपना कहने और उनका अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं आता था। जबकि भारत में भी इस दौरान मौतें हो रही हैं, लेकिन यहां चट मौत पट अंतिम संस्कार किया जा रहा है। दरअसल, यहां की संस्कृति में मृत्यु के बाद भी कई तरह के संस्कार होते हैं, जिसे निभाने की प्रथा सदियों पुरानी है। लोग इस प्रथा को निभाने के चक्कर में मौत को भूल जाते हैं और आयोजन को भव्य बनाने में जुट जाते हैं। वैसे देखा जाए तो इस कोरोना काल में भले ही भारत में अब तक 2293 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं लॉकडाउन के कारण 50 दिन में हमने सड़क दुर्घटना में होने वाली 20,700 मौतों को रोक दिया है। गौरतलब है कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार देश में रोजाना 414 लोग सड़क दुर्घटना में मरते हैं। यही नहीं देश में रोजाना विभिन्न बीमारियों और अन्य कारणों से होने वाली हजारों मौतों पर भी लगाम लगा है। हद तो यह देखने को मिलती है कि इस संकट की घड़ी में लोग संसाधनों के अभाव के बावजूद अपने घर पहुंचने के लिए पैदल निकल पड़े हैं। अगर माना जाए कि ये लोग बेबस, लाचार होकर हजारों मील की पैदल यात्रा करने को मजबूर हुए हैं, लेकिन घर पहुंचने का उत्साह इनके चेहरे पर साफ झलक रहा है। पैदल अपने गंतव्य तक जाने वाले लोगों को खाना, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक संगठनों ने सड़कों के किनारे व्यवस्था की है। इस पूरे माहौल को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे लोग तीर्थाटन करने जा रहे हैं। यह भले ही उत्सवी माहौल नहीं है, लेकिन लोगों में उत्सव जैसा उत्साह देखने को मिल रहा है। समाजसेवियों और सरकार के अनुनय-विनय के बाद भी कोई रुकने को तैयार नहीं है। हद तो यह भी देखने को मिल रही है कि इस दौरान कई ऐसे मामले आए हैं जहां लोग एक-दूसरे को भरपूर सहयोग भी कर रहे हैं। उदाहरणार्थ झाबुआ में बस से जा रहे श्रमिकों में से एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई तो लोगों ने बस रुकवाकर पूरी बस खाली करवाई और बस में ही महिलाओं ने उक्त महिला की डिलीवरी कराई। एक उदाहरण तो आगरा-मुंबई हाईवे पर सामने आया जहां महाराष्ट्र से पैदल आ रही एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई और उसने सड़क के किनारे ही एक बच्चे को जन्म दिया। कुछ घंटे रुकने के बाद वह नवजात को गोद में उठाकर चल पड़ी और 120 किलोमीटर का सफर तय कर अपने घर पहुंची। दरअसल, हम भारतीयों ने यह सिद्ध कर दिया है कि ईश्वर की सृष्टि में कुछ भी अमंगल नहीं होता, यहां जो होता है, मंगल ही होता है। यहां जन्म भी मंगल है तो मृत्यु भी मंगल है। इसलिए भारतीयों को कोई भी आपदा-विपदा कुछ देर, कुछ दिन ही प्रभावित करती है, उसके बाद हम उसके आदी हो जाते हैं।

-राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 18, अंक 16, 16 से 31 मई, 2020

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :

प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2015-17

ब्यूरो

मुंबई :- ऋतेन्द्र माथुर, **कोलकाता**:- इंद्रकुमार, **जयपुर**:- आर.के. बिन्नानी, **छत्तीसगढ़**:- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, टी.पी. सिंह, **लखनऊ** :- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता

094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
094259 85070, (मंदसौर) धर्मवीर रत्नावत
098934 77156, (विदिशा) ज्योत्सना अनूप यादव

क्षेत्रीय कार्यालय

नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी-
फोन : 011 25495021, 011 25494676
मुंबई : बी-1, 41 शिव पावर्ती चेम्बर प्लाट नंबर 106-110 सेक्टर-21 नेरूल, नवी मुंबई-400706 मो.-093211 54411
कोलकाता : 70/2 हजरा रोड कोलकाता
फोन-033 24763787, मोबाइल: 09331 033446
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)
फोन- 0141 2295805, मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : 39 श्रुत्रि सिंलटर निपानिया, इंदौर
मोबाइल - 094251 25096

स्वात्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

प्रवासियों के बारे में भी सोचें

केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में मनरेगा के काम शुरू करने की अनुमति देकर अच्छा कदम उठाया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही सरकार को प्रवासी मजदूरों के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। इससे ग्रामीण आजीविका के संकट से मुक्त हो पाएंगे।

● **रूपाली शर्मा,** रायसेन (म.प्र.)

किसानों की हालत खराब

प्रदेश में लॉकडाउन के चलते गेहूं खरीदी की प्रक्रिया में बदलाव कर दिए गए हैं, लेकिन इससे किसानों की हालत खराब हो रही है। जब किसान अपनी उपज लेकर उपार्जन केंद्र पहुंचता है तो उसकी थोड़ी उपज ही खरीदी जाती है। इससे किसानों में रोष है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

● **अनिल थापा,** सीहोर (म.प्र.)

घर चलाना मुश्किल

इन दिनों शहरों में कामकाज ठप पड़े हैं और अधिकांश मजदूर गांव पहुंच गए हैं। लेकिन गांवों में भी उनके लिए कोई काम नहीं है। इससे अब प्रवासी मजदूरों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। उनका घर चलाना मुश्किल हो गया है। दो जून की रोटी के लिए उन्हें काफी मशक्कत उठानी पड़ रही है।

● **निर्मल साहू,** भोपाल (म.प्र.)

भारत के पास बहुत अच्छा मौका है

महामारी के इस दौर में भारत के पास बहुत अच्छा मौका है कि वे अपने दुनिया में अपनी पहुंच बना सके। भारत में श्रमिक सस्ती दर पर मिलते हैं। यही एक बड़ी वजह है जिससे भारत दुनियाभर में अपनी पैठ बना सकता है। भारत अपने यहां निर्माण इकाईयां स्थापित कर उनमें सस्ते सामान का उत्पादन कर विश्व बाजार पर छा सकता है। अब तक चीन ने दुनियाभर में सस्से सामान बनाकर खूब कमाई की है, लेकिन अब चीन में वो ताकत नहीं रही। अब तो कोरोना वायरस ने भी बड़ी-बड़ी कंपनियों को चीन से बाहर देखने का एक और मौका दे दिया है और वो विकल्प की तलाश में हैं। अब वहां मजदूरी काफी बढ़ गई है। इसका फायदा भारत को उठाना चाहिए।

● **पंकज वर्मा,** इंदौर (म.प्र.)

बिक रही अवैध शराब

प्रदेशभर में पुलिस और आबकारी विभाग ने छापा मारकर करोड़ों रुपए की अवैध शराब तो जब्त की है, लेकिन लोगों को शराब की ऐसी लत लग चुकी है कि वे शराब न मिलने पर गलत कदम उठा रहे हैं। एक व्यक्ति बीयर के भ्रम में एसिड पी गया और एक शराब की लत में धतूरा खाने से मौत का शिकार हो गया। प्रदेशभर में लॉकडाउन होने के बावजूद अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहां अवैध शराब मनमाने दामों में बेची जा रही है। सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा।

● **दिनेश शर्मा,** राजगढ़ (म.प्र.)

महिलाओं को योग्यता में कम आंकते हैं लोग

देश सहित दुनियाभर में आज के समय में भी महिलाओं को समानता हासिल करने के मामले में अनगिनत बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया के हर हिस्से की महिलाओं ने हर क्षेत्र में चाहे वह राजनीतिक पटल हो या फिर कारोबार सभी में अपनी क्षमता और योग्यता को सिद्ध किया है। इसके बावजूद भी उनके प्रति लोगों की पूर्वाग्रही सोच कायम है। दुनियाभर के कई देशों में आज भी गैर-बराबरी कायम है। लोग आज भी महिलाओं को योग्यता में कम आंकते हैं। इस सोच को बदलना होगा।

● **घनश्याम मीणा,** होशंगाबाद (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

दांव-पेच

कांग्रेस से मोह भंग क्यों?

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कांग्रेस छोड़ने की अटकलों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि गॉसिप में ही सही लोग उनके नाम की चर्चा तो कर रहे हैं। असल में पिछले कई दिनों से इस बात की चर्चा थी कि सिंघवी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले हैं। यह भी कहा जा रहा था कि वे अभी कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अभी पार्टी छोड़ने पर राज्यसभा की सदस्यता भी छोड़नी होगी और अभी कहीं से चुनाव नहीं होना है। इसलिए वे साल के अंत तक इंतजार करेंगे, जब उत्तर प्रदेश की दस सीटों पर चुनाव हैं। अब जबकि उन्होंने इसका खंडन कर दिया है फिर भी अटकलों का दौर जारी है। कहा जा रहा है कि उनका परिवार भाजपा के करीब रहा है। उनके पति लक्ष्मीमल सिंघवी भाजपा के साथ थे। इसलिए वे भी भाजपा में चले जाएंगे। असल में पिछले दिनों यह खबर उड़ी कि कांग्रेस के एक वकील नेता भाजपा में जाएंगे। कांग्रेस के वकील नेताओं में कपिल सिब्बल, पी चिदंबरम, अभिषेक मनु सिंघवी, केटीएस तुलसी, आनंद शर्मा आदि हैं। इनमें से लोगों को सबसे कमजोर कड़ी सिंघवी ही दिखाई दिए। सो, उनके नाम की चर्चा औरों के मुकाबले ज्यादा जोर-शोर से होने लगी। अब भी कई जानकार नेता इंतजार करने को कह रहे हैं। उनका कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में भी कोई पहले यकीन नहीं कर रहा था।

पीएम केयर्स के चंदे का हिसाब

वैसे तो कांग्रेस और कई विपक्षी पार्टियों के नेता इस बात का हिसाब मांग रहे हैं कि पीएम केयर्स में अब तक कितना पैसा आया है और कितना खर्च हुआ है। वे चाहते हैं कि इसका सरकारी तरीके से ऑडिट किया जाए। पर राजनीति में रूचि रखने वाले अनेक लोग इस बात का हिसाब चाहते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पीएम केयर्स में कितना चंदा दिया। ध्यान रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं और सदस्यों से चंदा देने की अपील की थी। पार्टी के 40 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि पार्टी का हर कार्यकर्ता 40 लोगों को चंदा देने के लिए प्रेरित करे। सो, कायदे से इस रास्ते से पीएम केयर्स में भारी भरकम फंड आया हुआ होना चाहिए। आखिर देश में भाजपा के सदस्यों की संख्या 18 करोड़ बताई जाती है। अगर पार्टी का हर सदस्य एक सौ रुपया भी देता है तो 18 सौ करोड़ रुपए की रकम बनती है, जो किसी एक जगह से आया सबसे बड़ा चंदा हो जाएगा। अब तक टाटा समूह की ओर से दिया गया डेढ़ हजार करोड़ रुपए का चंदा सबसे बड़ा चंदा है। अगर सरकार की ओर से इसका खुलासा हो तो दूसरे लोगों को भी चंदा देने की प्रेरणा मिलेगी। दूसरी पार्टियां भी अपने लोगों से अपील करेंगी।

कन्फ्यूजन में दिल्ली सरकार

कोरोना वायरस से लड़ाई को व्यवस्थित तरीके से लड़ने की बजाय केजरीवाल सरकार ने इस लड़ाई में कई किस्म के कन्फ्यूजन पैदा किए हैं। ऐसा पहली बार लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को असल में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तभी किसी भी पूर्वी या उत्तर पूर्वी पिछड़े, गरीब राज्यों की तरह दिल्ली में भी कोरोना से मौत का आंकड़ा छिपाया जा रहा है। अस्पतालों से कुछ और आंकड़ा मिल रहा है और सरकार कुछ और बता रही है। इसी तरह सरकार ने लोकलुभावन घोषणा कर दी कि कोरोना वॉरियर्स के मरने पर एक करोड़ रुपए दिए जाएंगे लेकिन उन कोरोना वॉरियर्स के कामकाज को आसान बनाने के लिए कुछ नहीं किया गया। इस समय दिल्ली में पीपीई किट्स की भारी कमी है। कई जगह स्वास्थ्यकर्मी हाथ और पैर में पॉलिथीन बांधकर काम कर रहे हैं। यह कितना दुखद है कि दिल्ली पुलिस के जिस जवान की कोरोना वायरस से मौत हुई है उसे एक करोड़ मिलेंगे, लेकिन जीते जी उस जवान को इलाज नहीं मिला? उसके परिजन उसे लेकर अस्पताल-अस्पताल भटकते रहे। आखिर अरविंद केजरीवाल की सरकार इतनी कन्फ्यूज क्यों है? क्या यह केजरीवाल की नासमझी है या वे जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं।

यहां उलटा-पुलटा क्यों?

केंद्र सरकार कोरोना वायरस के साथ खिलवाड़ कर रही है। उसका यह खिलवाड़ कहीं खतरनाक न बन जाए। ऐसा कई कारणों से लग रहा है कि केंद्र सरकार कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हाथ खड़े कर रही है। इसे सरकार के दो फैसलों से समझा जा सकता है। पहले तो सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमितों को घरों में ही रखने का फैसला किया। दूसरा और बड़ा फैसला यह किया गया है कि सरकार अब कोरोना वायरस के संक्रमण से गंभीर रूप से बीमार मरीजों को छोड़कर बाकियों को अस्पताल से डिस्चार्ज करते समय उनकी जांच नहीं की जाएगी। यानी उन्हें अगर बुखार नहीं आता है तो बिना जांच के ही घर जाने को कहा जा सकता है। बहुत संभव है कि बुखार नहीं आने पर बिना जांच के अस्पताल से छूटा व्यक्ति कोरोना वायरस का कैरियर हो। लेकिन सरकार ने सबकुछ उलट-पुलट कर दिया है। जब ऐसा ही करना था तो लॉकडाउन की क्या जरूरत थी। दरअसल, सरकार अपनी ही नीति में फंसती जा रही है।

क्या बदलेगा मुख्यमंत्री?

विजय रूपाणी जबसे गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद उनके नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़कर एक बार जीत भी चुकी है पर पहले दिन से उनके मुख्यमंत्री पद से हटने की अटकलें भी चल रही हैं। कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच एक बार फिर विजय रूपाणी की जगह नया मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा शुरू हो गई है। असल में गुजरात में बड़ी तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अहमदाबाद नया इपीसेंटर बन गया है। तभी अहमदाबाद के सारे अधिकारियों को पिछले दिनों बदला गया और समूचा प्रशासन नया बनाया गया। तब से यह कहा जाने लगा कि राज्य का प्रशासन भी बदला जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि भाजपा के अंदर जोर-शोर से इस बात की चर्चा हुई है। इसका कारण यह बताया जा रहा है कि गुजरात मॉडल को लेकर देश भर में सवाल उठ रहे हैं। आखिर इसी मॉडल को दिखा कर नरेंद्र मोदी ने देशभर में अपने पक्ष में माहौल बनाया था। पर अब कोरोना वायरस के संकट के समय केरल एक मॉडल की तरह उभरा है।

भोपाल के हाथ में इंटेलीजेंस

शीर्षक पढ़कर आपको आश्चर्य लगेगा। लेकिन हकीकत भी कुछ ऐसी ही है। दरअसल, मप्र की खुफिया एजेंसियों की कमान उन अफसरों के हाथ में है जो कभी न कभी भोपाल जिला पुलिस में महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थ रहे हैं। प्रदेश की प्रशासनिक और राजनीतिक वीथिका में शुरू से यही माना जाता है कि राजधानी भोपाल में महत्वपूर्ण पदों पर उन्हीं अफसरों को पदस्थ किया जाता है जो तेज तर्रार और इंटेलीजेंट होते हैं। इस समय प्रदेश की खुफिया एजेंसी में ऐसे ही तीन अधिकारी पदस्थ हैं, जिन्होंने अलग-अलग समय में भोपाल पुलिस में सीएसपी से लेकर आईजी तक के पद पर पदस्थ रहे हैं।इसके पीछे सरकार की मंशा यह है कि इन काबिल अफसरों के हाथ में खुफिया विभाग की कमान आने से सरकार के पास हर उन गतिविधियों की खबर निरंतर पहुंचेगी जो शासन-प्रशासन और प्रदेश के हित में नहीं है। गौरतलब है कि वर्तमान सरकार के पूर्ववर्ती शासनकाल में खुफिया विभाग की कार्यप्रणाली हमेशा सवालों के घेरे में रही थी। सरकार की नाक के नीचे बड़ी-बड़ी घटनाएं हो जाती थीं और खुफिया विभाग को इसकी खबर तक नहीं रहती थी। इसलिए इस बार सरकार ने उन चुनिंदा अफसरों को विभाग में पदस्थ किया है जो हमेशा सजग, सक्रिय और समर्पित भाव से काम करते हैं। अब देखना यह है कि ये अफसर सरकार की आंख का तारा कब तक बने रहते हैं।

मंत्री बनते ही जलवा कायम

सत्ता का तो अपना जलवा होता ही है, ऐसे में अगर मंत्री पद मिल जाए तो बल्ले-बल्ले हो जाती है। ऐसी ही बल्ले-बल्ले इन दिनों एक नेताजी की हो गई है। दरअसल, उनके मंत्री बनने की संभावना नहीं थी, लेकिन उनका भाग्य ऐसा प्रबल हुआ कि वे मंत्री बन गए। मंत्री बनते ही उनमें सुरखाब के पंख लग गए हैं। मंत्रीजी अब हमेशा फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उनकी सक्रियता अन्य मंत्रियों से अधिक हो गई है। यही नहीं अपनी बेबाकी के लिए प्रसिद्ध मंत्रीजी अब इतने बेबाक हो गए हैं कि वे अफसरों को उनके मुंह पर ही खरी-खोटी सुनाने से भी नहीं चूकते हैं।यहां तक तो सबकुछ ठीक है, लेकिन मंत्रीजी के परिजन भी जलवेदार हो गए हैं। खासकर उनके बेटे का जलवा तो इस कदर छा गया है कि प्रशासन भी उसके आगे नतमस्तक रहता है। यहां बता दें कि मंत्रीजी का यह बेटा जिलाबदर रह चुका है लेकिन इन दिनों अपने गृह जिले में वह एक पुलिस अधिकारी के साथ गाड़ी में घूमते नजर आता है। मंत्रीजी के बेटे का यह जलवा देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। प्रशासनिक गलियारों में तो यह चर्चा भी हो रही है कि मंत्रीजी के बेटे की स्थिति एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़े वाली न हो जाए। अब देखना यह है कि सत्ता का गुरूर क्या गुल खिलाता है।

इतना पावरफुल कोई और नहीं...

प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों एक मंत्रीजी के पावर की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल, मंत्रीजी के पास दो महत्वपूर्ण विभाग हैं। एक विभाग की जिम्मेदारी तो इस समय सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि उक्त विभाग कोरोना संक्रमण को रोकने में लगा हुआ है। वहीं मंत्रीजी के पास जो दूसरा विभाग है वैसे ही वह पावरफुल विभाग माना जाता है लेकिन मंत्रीजी और पावरफुल होकर उभरे हैं। जानकारों का कहना है कि इस विभाग में अभी तक जितने भी मंत्री बने हैं वे इतने पावरफुल नहीं बन पाए हैं। इसलिए मंत्रीजी को राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिकाओं में सुपर एचएम कहा जा रहा है। जब इसकी पड़ताल की गई तो यह तथ्य सामने आया कि विभाग में मंत्रीजी की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। इससे पहले विभाग में जब भी बड़े अधिकारियों के तबादले होते थे, तो मुख्यमंत्री और मुख्यसचिव अपने मन से कर दिया करते थे। लेकिन अब मंत्रीजी को भी शामिल किया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि पिछले दिनों प्रदेश में आईपीएस अधिकारियों के जितने भी तबादले हुए हैं उसमें मंत्रीजी का भी दखल था। वैसे यहां यह भी बता दें कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का तख्ता पलट करने में भी उक्त मंत्रीजी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए अगर प्रदेश के इतिहास में वे सुपर एचएम बनकर उभरे हैं तो यह उनकी मेहनत का ही फल है। अब देखना यह है कि उनका यह पावर कब तक कायम रहता है।

इंदौर-भोपाल की बोली

प्रदेश में आईएएस अधिकारियों के तबादले के बाद अब आईपीएस अधिकारियों के तबादले की भी सुगबुगाहट जोरों पर है। सूत्र बताते हैं कि आईपीएस अधिकारियों के तबादले की सूची लगभग बनकर तैयार है, लेकिन राजधानी भोपाल के एक जाने-माने बिल्डर के कारण उक्त सूची फाइनल नहीं हो पा रही है। सूत्रों का कहना है कि उक्त बिल्डर ने सरकार के सामने इंदौर और भोपाल में अपनी पसंद के अधिकारी पदस्थ करने का प्रस्ताव रखा है। यहां बता दें कि उक्त बिल्डर सरकार के मुखिया के काफी करीबी हैं। ऐसे में उनकी मांग को पूरा करना सरकार के सामने भी मजबूरी है। जब इस बारे में पड़ताल की गई तो यह तथ्य सामने आया कि उक्त बिल्डर 1995 बैच के एक आईपीएस को इंदौर और 2006 बैच के एक आईपीएस को भोपाल में पदस्थ करवाना चाहते हैं। 2006 बैच वाले आईपीएस अधिकारी अपनी निष्ठा और ईमानदारी के लिए ख्यात हैं। ये साहब वर्तमान में पड़ोसी जिले में पदस्थ हैं। अब देखना यह है कि सरकारी उक्त बिल्डर की इच्छानुसार क्या इन अफसरों को पदस्थ कर सूची जारी करेगी।

कौन किसके साथ?

मप्र में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कब होंगे यह अभी तय नहीं है, लेकिन दावेदार अपनी-अपनी गोटियां बिछाने लगे हैं। भाजपा ने तो घोषणा कर दी है कि सिंधिया समर्थक जिन 22 नेताओं ने पार्टी का दामन थामा है, उन्हें हर हाल में टिकट दिया जाएगा। लेकिन उन सीटों पर पूर्व में भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ने वाले कई नेता उपचुनाव भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि इनमें से कई कांग्रेस के संपर्क में भी हैं। यानि अगर भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वे कांग्रेस की तरफ से मैदान में कूद सकते हैं। इस बात की घोषणा कांग्रेस ने भी कर दी है। लेकिन भाजपा इसे महज अफवाह मान रही है। उपचुनाव में कौन किसके साथ रहेगा यह तो चुनाव की घोषणा के बाद पता चलेगा लेकिन दांव-पेच का खेल लगातार जारी है। अब देखना यह है कि उपचुनाव की घोषणा के बाद किस पार्टी में भगदड़ मचती है। बताया जाता है कि कांग्रेस के भी कई नेता भाजपा में आने के लिए उतावले हो रहे हैं। ऐसे में आने वाला समय राजनीतिक शह-मात का समय रहेगा। कौन बाजीगर बनेगा यह तो भविष्य में पता लगेगा।

मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि घातक कोरोना वायरस चीन के वुहान की प्रयोगशाला में ही पैदा हुआ है। हमने इस संबंध में जो खुफिया जानकारी एकत्र की है मैं उसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन हमारे पास पर्याप्त जानकारी है।

● **माइक पोम्पियो**

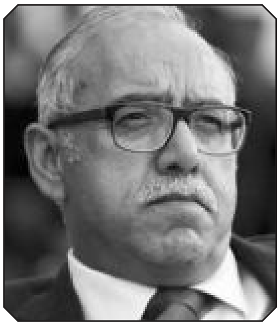

देश का लीगत सिस्टम अमीरों और ताकतवरों के पक्ष में हो गया है। जज ऑस्ट्रिच की तरह अपना सिर नहीं छिपा सकते, उन्हें ज्युडिशियरी की दिक्कतें समझकर इनसे निपटना चाहिए। जब अमीर सलाखों के पीछे होता है तो कानून अपना काम तेजी से करता है, लेकिन गरीबों के मुकदमों में देरी होती है। अदालतों को गरीबों की आवाज जरूर चाहिए।

● **दीपक गुप्ता**

भारत में महिला का खिलाड़ी बनना मुश्किलों भरा है। इसके बावजूद देश में कई खेलों में महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। दरअसल, जब कोई महिला खेल की इच्छा जताती है तो उसके सामने पाबंदियों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। इस कारण कई लड़कियां पीछे हट जाती हैं। इसलिए इस धारणा को बदलने की जरूरत है।

● **सानिया मिर्जा**

कोरोना वायरस के कारण विश्व में महामारी फैल रही है। ऐसे में मंदिर खोलने पर रोक है, लेकिन मदिरालय खोले जा रहे हैं। इस पर शासन-प्रशासन को विचार करना चाहिए। क्योंकि मुनाफे के लिए बड़ी जनहानि उठानी पड़ सकती है।

● **विराग सागर महाराज**

मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि मैं स्क्रीन पर महिला किरदारों को लोगों के सामने किस तरह प्रस्तुत करती हूं। सिनेमा में लोगों की सोच को बदलने की ताकत है और मुझे लगता है कि हम महिला किरदारों के जरिए समानता और स्वतंत्रता के संदेश को सभी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मैंने हमेशा ऐसे ही किरदारों की तलाश की है और इन किरदारों को पर्दे पर पूरे दिल से निभाया है। मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे ऐसे किरदारों को निभाने का मौका मिला, जो हटकर थे और जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई।

● **भूमि पेडनेकर**

वाक्युद्ध

कोरोना वायरस का संक्रमण आज देश को पूरी तरह चपेट में ले चुका है। अगर मोदी सरकार समय पर इंतजाम कर देती तो आज यह स्थिति नहीं होती। लेकिन जिस समय व्यवस्था करनी थी उस समय केंद्र सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की सेवा में लगी हुई थी। अब लॉकडाउन कर लोगों की रोजी रोटी छीन ली है।

● **राहुल गांधी**

कांग्रेस कोरोना के मुद्दे पर सियासत न करे। कांग्रेस की रूचि केवल सरकार को बदनाम करने और देशवासियों की एकता को कमजोर करने में है। विपक्ष में रहने का मतलब यह नहीं होता कि सरकार की हर बात की खिलाफत की जाए। यह समय लोगों का मनोबल बढ़ाने और देश को संगठित करने का है।

● **सैय्यद शाहनवाज हुसैन**

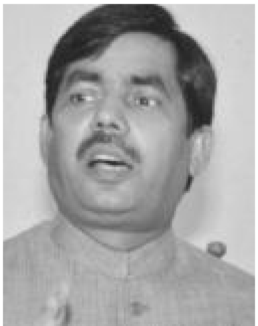

मप्र में सरकार ने पिछले दिनों एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करते हुए आधा सैकड़ा आईएएस अफसरों को इधर से उधर किया। इस तबादले में जहां कई अफसर मुख्य धारा में आ गए वहीं कई लूप लाइन में चले गए। माना जा रहा है कि शासन-प्रशासन को गति देने के लिए यह जमावट की गई है।

प्रशासनिक जमावट

मप्र में सत्ता परिवर्तन के बाद सरकार ने एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। दरअसल, शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री और इकबाल सिंह बैंस के मुख्य सचिव बनने के बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही सरकार प्रशासनिक बदलाव करेगी। लेकिन इतने बड़े स्तर पर तबादले होंगे, यह किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। इस तबादले में 50 आईएएस अफसरों को इधर से उधर किया गया। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ने अपनी सहूलियत के हिसाब से अफसरों को शतरंज की बिसात की तरह सेट किया है। दरअसल, परंपरा भी यही रही है कि हर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव अपने हिसाब से प्रशासनिक जमावट करते हैं ताकि वे अपनी योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन कर सकें। हालांकि इस प्रशासनिक जमावट को कांग्रेस ने तबादला उद्योग कहा है। लेकिन पहली नजर में ही **कांग्रेस के इस आरोप में दम नहीं है।** क्योंकि अधिकांश वे ही अफसर मुख्यधारा में हैं, जो पात्र हैं। कुछ को अपवाद मान सकते हैं। हालांकि, प्रशासनिक जमावट का एक चरण अभी बाकी है। यह लॉकडाउन खत्म होने और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अगले माह तक होगा। इसमें कलेक्टर से लेकर मंत्रालय स्तर तक जिम्मेदारियों में बदलाव किया जाएगा।

वहीं, मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी राधेश्याम जुलानिया की भूमिका भी अभी तय होना बाकी है। उन्हें केंद्र सरकार ने एकतरफा मध्य प्रदेश के लिए कार्यमुक्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक अभी जो प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, उसमें कोरोना के मद्देनजर मैदानी स्तर पर बदलाव नहीं किए गए हैं। जबकि कुछ कलेक्टरों को हटाया जाना प्रस्तावित है। कुछ अधिकारी, जो विभिन्न कार्यालयों में पदस्थ हैं, उन्हें मैदानी पदस्थापनाएं दी जानी हैं। इसके लिए उन्हें कुछ समय रुकने का आश्वासन सत्ता और संगठन के स्तर से मिला है।

ताजा फेरबदल में कुछ ऐसे अफसरों को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो कड़क मिजाज के माने जाते हैं। दरअसल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ने अपनी इस जमावट से यह संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार को अब दाम वाले नहीं, बल्कि काम और अच्छे नाम वाले अफसरों पर भरोसा है। उदाहरणार्थ वाणिज्य कर विभाग को ही ले लें। ईमानदार पहचान के साथ अब तक मुख्यधारा के पदों से बाहर रहे मनोज गोविल वाणिज्य कर में किसी अपवाद की तरह नजर आ रहे हैं। इस मलाईदार महकमे की कमान गोविल जैसे लो प्रोफाइल अफसर को देना यकीनन सकारात्मक बदलाव का संकेत है। इसी तरह महिला एवं बाल विकास जैसे **कमाऊ विभाग की कमान** अशोक शाह जैसे ईमानदार अफसर को देना इस बात का संकेत है कि इस बार मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हैं। इसी तरह नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव बनाए गए नीतेश व्यास, जनसंपर्क महकमे में दूसरी बार पदस्थ प्रमुख सचिव अनुपम राजन तथा आयुक्त सुदाम खाड़े भी ईमानदार अफसरों की श्रेणी में आते हैं। शिवराज ने अपने इस कार्यकाल में अपने प्रमुख सचिव के तौर पर मनीष रस्तोगी का चयन करके ही संकेत दे दिए थे कि सरकार को अच्छे काम वाले अफसरों पर भरोसा है। कोरोना वायरस के साथ ही प्रदेश में जल संकट का दौर भी शुरू होने वाला है। ऐसे में जल संसाधन विभाग में डीपी आहूजा को पदस्थ किया गया है। आहूजा की गिनती सुस्त अफसरों में की जाती है। ऐसे में वे प्रदेश को जल संकट से कैसे निकाल पाएंगे, यह सवाल प्रशासनिक वीथिका में बना हुआ है।

वहीं शिवराज सरकार ने जो प्रशासनिक बदलाव किया, उसमें अपर मुख्य सचिव जेएन कंसोटिया, प्रमुख सचिव पंकज राग, कल्पना श्रीवास्तव को कम महत्व के विभाग दिए गए हैं। कंसोटिया को सिर्फ पशुपालन विभाग दिया है, जिसमें बेहद सीमित काम है। वहीं, पंकज राग से संस्कृति लेकर संसदीय कार्य और खेल एवं युवा कल्याण विभाग दिया है। भोपाल कमिश्नर पद से हटाने के बाद उम्मीद थी कि प्रमुख सचिव कल्पना श्रीवास्तव को अच्छी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी पर उन्हें उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग दिया है, जो हमेशा कृषि पर आधारित रहते हैं। कोरोना संकट के दौरान बीमार पड़े स्वास्थ्य महकमे की प्रमुख सचिव डॉ. पल्लवी जैन गोविल को मुख्यधारा से दूर रहने वाले आदिम जाति और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में पदस्थ किया है। अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान से भी महत्वपूर्ण विभाग ऊर्जा ले लिया है। उनके पास स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, भोपाल गैस त्रासदी राहत और प्रवासी भारतीय जैसे विभाग हैं। भोपाल गैस त्रासदी राहत और प्रवासी भारतीय विभाग को छोड़कर सभी विभागों में प्रमुख सचिव और आयुक्त पदस्थ हैं। फैज अहमद किदवई को मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव और पर्यटन विभाग से हटाया गया है।

इसी तरह राजेश बहुगुणा को राजस्व मंडल, मोहनलाल मीना प्रबंध संचालक खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और रेनू तिवारी आयुक्त सामाजिक न्याय पर पदस्थ किया गया है। वहीं संजय दुबे को ऊर्जा विभाग देकर कद बरकरार रखा गया है। मलय श्रीवास्तव को उनकी मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है। उधर, अपनी ईमानदार छवि के लिए ख्यात संजय शुक्ला को उद्योग विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है। अमित राठौर को वित्त और दीपाली रस्तोगी को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग देकर भरोसा जताया है। राजीव चंद्र दुबे को आबकारी आयुक्त, अजीत कुमार को आयुक्त नगर तथा ग्राम निवेश, आशीष सक्सेना को आयुक्त सहकारिता, श्रीमन शुक्ला को प्रबंध संचालक सड़क विकास निगम, स्वाति मीणा नायक को संचालक महिला एवं बाल विकास, छवि भारद्वाज को मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में पदस्थ कर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार ने कई ऐसे अफसरों को महत्वपूर्ण विभाग इसलिए दिया है कि **वह भविष्य** के लिए उन्हें तैयार कर रही है।

● **सुनील सिंह**

छोटे विभागों को बड़े नाम

मुख्यमंत्री ने इस बदलाव में छोटे विभागों में बड़े नाम वाले अफसरों को पदस्थ किया है। माना जा रहा है कि सरकार द्वारा कमजोर विभागों को भी महत्वपूर्ण बनाने के लिए इन अफसरों को उन विभागों में पदस्थ किया गया है। इनमें डॉ. राजेश राजौरा, मनु श्रीवास्तव, पी. नरहरि जैसे अफसर भी शामिल हैं, जो पिछली शिवराज सरकार की आंखों के तारे रहे थे। अपर मुख्य सचिव आईसीपी केशरी, जेएन कंसोटिया, मलय श्रीवास्तव आदि अधिकारियों की लंबी फेहरिस्त है, जो दोनों सरकारों में काबिल माने गए। सबसे बड़ा उदाहरण प्रमुख सचिव अशोक बर्णवाल हैं। वे लंबे समय तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के प्रमुख सचिव रहे। लेकिन इस बार इन अफसरों को महत्वपूर्ण विभाग नहीं मिले हैं।

कुलीनों के कुल में कलह

15 माह पुरानी कांग्रेस की सरकार को गिराकर भाजपा ने सत्ता तो हासिल कर ली है, लेकिन कुलीनों के कुल में कलह के कैक्टस उगने लगे हैं। दरअसल, पार्टी का लगभग हर विधायक मंत्री बनना चाह रहा है। वहीं समझौते के अनुसार सिंधिया समर्थक 22 विधायकों में से कम से कम 8 को मंत्री तो बनाना ही है। ऐसे में भाजपाई विधायक पार्टी हाईकमान को यह दिखाने में जुटे हुए हैं कि अगर क्षेत्र, जाति के अनुसार मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया गया तो इसके परिणाम सुखद नहीं होंगे। कई क्षेत्रों में विधायकों ने बैठकें करके मंत्री बनने की मांग उठाई है।

राजनीतिक दलों में भाजपा को कुलीनों की पार्टी कहा जाता है। अब प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार है। शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरों के बीच इस पार्टी के दिग्गज और वरिष्ठ नेताओं को लेकर उनके कुल में जमकर कलह होने लगी है। हालात यह है कि पार्टी के ही वरिष्ठ से लेकर अपने-अपने वर्ग में मजबूत पकड़ रखने और लगातार जीत दर्ज करने वाले विधायक अब पार्टी के उन नेताओं के विरोध में आ गए हैं, जिन्हें लगातार पहुंच और पार्टी में रसूख के चलते मंत्री बनाया जाता रहा है। इन्हीं पूर्व मंत्रियों के नाम एक बार फिर से संभावित मंत्रियों की सूची में सामने आ रहे हैं। अब कैबिनेट के दूसरे विस्तार को लेकर हलचल तेज होने के साथ ही प्रदेश में इन कद्दावर नेताओं का भारी विरोध शुरू हो गया है। विरोध करने वाले कार्यकर्ता, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता ऐसे विधायकों के विरोध में लामबंद हो रहे हैं। यह लोग कैबिनेट में नए और अब तक मंत्री न बन पाने वाले वरिष्ठ विधायकों को शामिल करने की मांग कर रहे हैं। जिन दिग्गज नेताओं को **मंत्री बनाए जाने का विरोध हो रहा है** उनमें महाकौशल से अजय विश्नोई, गौरीशंकर बिसेन, विंध्य क्षेत्र से राजेंद्र शुक्ल, मालवा अंचल में विजय शाह का नाम शामिल है।

गौरतलब है कि फिलहाल शिवराज सरकार सिर्फ पांच मंत्रियों से ही काम चला रही है। इनमें भी दो सिंधिया समर्थक और तीन भाजपा के कोटे से हैं। भाजपा सूत्रों की माने तो शिवराज कैबिनेट के दूसरे विस्तार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसके तहत अलग-अलग स्तर पर मंथन का दौर चल रहा है। संभावना है कि इसी माह नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। फिलहाल माना जा रहा है कि लगभग 23 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। जिसमें सिंधिया समर्थक और कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने वाले 8 से 10 पूर्व विधायक हो सकते हैं। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के दस विधायकों को भी शपथ दिलाई जा सकती है। उधर, पार्टी सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट विस्तार राज्यसभा चुनाव होने तक टाला भी जा सकता है। इस पर विचार चल रहा है।

मध्य प्रदेश में 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बनने के 15 महीने बाद ही कुर्सी छोड़ने को मजबूर हो गई। जिसके लिए अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपनी ही पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की 1 मई को राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात के बाद से राज्य में एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। राज्यपाल से इस दौरान मुख्यमंत्री ने करीब 50 मिनट चर्चा की। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान राज्यपाल को प्रदेश में कोरोना की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही राजनीतिक हालात और विश्वविद्यालयों के सत्र को लेकर भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच चर्चा हुई। लेकिन मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच हुई इस मुलाकात ने राज्य में सियासी हलचल बढ़ा दी है।

सिंधिया को 8 मंत्री चाहिए

मंत्रिमंडल विस्तार में ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक कांग्रेस के 8 बागी और मंत्री बनाए जाने हैं। इसके अलावा कई मंत्री राष्ट्रीय नेतृत्व की पसंद के बनने हैं। ऐसे में भाजपा के लिए सिर्फ 21 मंत्री पद ही बचेंगे, जबकि इन पदों के लिए उसके पास दोगुने से ज्यादा दावेदार हैं। इसके बावजूद, मुख्यमंत्री सियासी समीकरणों को देखते हुए मंत्रिमंडल में तीन से चार स्थान खाली रखेंगे। 21 अप्रैल को हुए मंत्रिमंडल के गठन में जिस तरह भाजपा ने नरोत्तम मिश्रा के साथ कमल पटेल और मीना सिंह को शामिल किया है, उससे उन 9 पूर्व मंत्रियों में उम्मीद बढ़ गई है जो 2013 का चुनाव हारने के बाद अब 2018 में फिर जीते हैं। इन सबके बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव का यह कहना कि यदि हम नाराज हो गए यो क्या बचेगा। यह साफ करता है कि दूर से ही सही लेकिन गोपाल भार्गव इशारा कर रहे हैं कि वह नाराज हैं और अगर उनकी नाराजगी दूर ना हुई तो फिर पार्टी को दिक्कत हो सकती है।

पिछले माह 21 अप्रैल को भाजपा सरकार बनने के 29 दिन बाद शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया। इस दौरान शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल पांच मंत्रियों को राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में भाजपा के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल और महिला आदिवासी नेता मीना सिंह सहित हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामने वाले तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत शामिल है। इन पांचों मंत्रियों को पहले दिन कोरोना की रोकथाम के लिए संभाग बांटे गए और दूसरे दिन विभाग। मंत्री नरोत्तम मिश्रा के हिस्से गृह, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जैसे अहम विभाग आए तो कमल पटेल को किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग मिला। वहीं मीना सिंह को आदिम जाति कल्याण विभाग तो सिंधिया समर्थक तुलसी सिलावट को जल संसाधन और गोविंद सिंह राजपूत को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के साथ सहकारिता विभाग सौंपा गया। जबकि मंत्रिमंडल गठन के बाद प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव को मंत्रिमंडल में शामिल न करने को लेकर भाजपा पर तंज कसा और सिंधिया समर्थकों को लेकर निशाना साधा।

मध्य प्रदेश में 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बनने के 15 महीने बाद ही कुर्सी छोड़ने को मजबूर हो गई। जिसके लिए अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपनी ही पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि यह रायता फैलाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी आइसोलेशन में क्वारंटाइन हैं। वह भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद लगातार अपने समर्थकों जिन्होंने 15 महीने पुरानी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिराकर सत्ता की चाबी भाजपा के हाथों सौंप दी उनके लिए राजनीतिक भूमि तैयार करने में लगे हैं। ताकि आगामी उपचुनाव में उनके राजनीतिक समर्थकों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। जिसके लिए वह कोई भी जतन करने को तैयार हैं। इसकी बानगी शिवराज मंत्रिमंडल के गठन में दिख गई। जिसमें तीन-दो के फॉर्मूले पर भाजपा ने काम करते हुए पांच में से दो मंत्री सिंधिया समर्थक बनाए। लेकिन अपने ही नेताओं की अनदेखी कर रही भाजपा में अंदर ही अंदर असंतोष पनपने लगा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के सबसे वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव निराश बताए जा रहे हैं। पिछले दिनों उन्होनें अपनी ही सरकार को घेरते हुए टॉस्क फोर्स की मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से दो टूक यह कह दिया कि मजदूरों के खाते में एक हजार रुपए देना अच्छा है, लेकिन मैंने जो अपने क्षेत्र के मजदूरों की सूची सौंपी थी, **उनके खातों में अभी तक** यह पैसा नहीं पहुंचा है। जिसके बाद सियासी गलियारों में यह चर्चा का विषय बन गया और तभी से लगातार गोपाल भार्गव अपने गृह क्षेत्र में हैं और उन्होंने भोपाल से दूरियां बना ली हैं। जिसके बाद गत दिनों मंत्री गोविंद सिंह राजपूत गोपाल भार्गव से मिलने उनके घर गढ़ाकोटा पहुंचे। मुलाकात के बाद जब गोविंद सिंह राजपूत से यह सवाल किया गया कि क्या वह गोपाल भार्गव को मनाने आए हैं तो गोविंद राजपूत ने कहा कि मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं गोपाल भार्गव को मना सकूं। वहीं पीछे से एक आवाज आई जिसमें गोपाल भार्गव ने कहा कि यदि हम नाराज हो गए यो क्या बचेगा।

तो दूसरी ओर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मंत्रिमंडल में शामिल होने की बाट जोह रहे हैं। इसी को लेकर शिवराज सिंह चौहान खासे पसोपेश में नजर आ रहे हैं। मंत्री पद सीमित है और कई वरिष्ठ नेताओं को मंत्रिमंडल में समायोजित करना है यह ढेड़ी खीर बनता जा रहा है। सबसे ज्यादा समस्या आ रही है बुंदेलखंड क्षेत्र से जहां गोपाल भार्गव जैसे दिग्गज और वरिष्ठ नेता हैं, तो वहीं शिवराज के करीब पूर्व गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह भी मौजूद हैं। इस क्षेत्र से पहले ही सिंधिया खेमे से गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री बनाया जा चुका है। तो वहीं कई ऐसे विधायक भी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए बेताब हैं जो भाजपा के टिकट से लगातार जीतते आ रहे हैं जिसमें शैलेंद्र जैन और प्रदीप लारिया का नाम सबसे आगे हैं।

जबकि विंध्य क्षेत्र में भी इस बार सिर्फ राजेंद्र शुक्ला के नाम पर सहमति बनती नहीं दिख रही। पार्टी सूत्रों की माने तो विंध्य क्षेत्र के प्रमुख विधायकों ने बैठक करके संगठन से कहा है कि इस बार सिर्फ शुक्ला नहीं चलेंगे। विंध्य क्षेत्र में भाजपा ने इस बार अधिक सीटें जीती हैं, इसलिए अन्य को भी मौका मिले। रीवा संभाग की देवतालाब विधानसभा से भाजपा के वरिष्ठ विधायक गिरीश गौतम ने इस बैठक को लेकर कहा कि 'कोरोना समेत कई मामलों को लेकर हम पांच-छह विधायकों ने बैठक की है। हम राजेंद्र शुक्ला का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन विंध्य में 30 में से 24 सीटें जीतने के बाद प्रतिनिधित्व तो बढ़ना चाहिए।' यहां राजेंद्र शुक्ला के अलावा गिरीश गौतम, नागेंद्र सिंह गुढ़, जुगलकिशोर बागरी, नागेंद्र सिंह नागौद समेत कुछ और लोग भी मंत्रिमंडल में शामिल होने की आस रखते हैं।

● **कुमार राजेन्द्र**

मालवा-निमाड़ में दावेदारों की लंबी लाइन

कुछ यही हाल मालवा और निमाड़ क्षेत्र का भी है। जहां इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर और नीमच में मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए दावेदारों की लाइन लगी है। ओमप्रकाश सकलेचा, जगदीश देवड़ा, यशपाल सिंह सिसोदिया, मोहन यादव, चेतन कश्यप, ऊषा ठाकुर, मालिनी गौड़, महेंद्र हार्डिया और रमेश मेंदोला ने संगठन के सामने अपनी बात रख दी है। इसमें भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के खास रमेश मेंदोला को जगह मिल सकती है। जबकि ग्वालियर-चंबल क्षेत्र जहां सबसे अधिक 16 विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं यहां और मालवांचल में बिना सिंधिया की बिना राय के किसी का भी मंत्री बनना मुश्किल होगा। क्योंकि ग्वालियर-चंबल और मालवांचल के कुछ क्षेत्रों में सिंधिया की अच्छी पैठ मानी जाती है। लेकिन वहीं कांग्रेस सरकार को गिराने में अहम भूमिका अदा करने वाले भिंड जिले की अटेर विधानसभा से विधायक अरविंद भदौरिया मंत्रिमंडल में जगह पा सकते है।

वासनिक की असली परीक्षा

चुनौतियों का पहाड़ वासनिक के सामने

बतौर महामंत्री चुनौतियों का एक बड़ा पहाड़ वासनिक को उत्तराधिकार में मिला है, इन हालातों को चुस्त-दुरुस्त करने की जिम्मेदारी अब उन पर है। लॉकडाउन की परिस्थितियों के बीच मुकुल वासनिक को नई पारी की शुरुआत करना है और उपचुनाव की चुनौतियों के बीच तैयारियां करवाना एवं संगठन की गतिविधियों में जो शिथिलता आई उसे भी उन्हें प्राथमिकता से दूर करना होगा। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री कमलनाथ के त्यागपत्र के बाद दीपक बाबरिया ने हाईकमान को फीडबैक देते हुए यह सुझाव दिया कि कमलनाथ को नेता प्रतिपक्ष रखा जाए और प्रदेश अध्यक्ष नए व्यक्ति को बनाया जाए। जबकि अधिकांश लोगों की राय यह है कि कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहें और यदि वे तैयार हों तो नेता प्रतिपक्ष भी उन्हें ही रखा जाए अन्यथा नया नेता चुन लिया जाए। कमलनाथ स्वयं चाहते हैं कि विधायक दल का नेता अलग हो, इसीलिए डॉ. गोविंद सिंह का नाम इस पद के लिए आगे बढ़ा है। सिंधिया के साथ जो भी विधायक और मंत्री पार्टी छोड़कर गए हैं उनमें सबसे अधिक ग्वालियर-चंबल संभाग के हैं और नेता प्रतिपक्ष के रूप में डॉ. सिंह के अलावा कोई दूसरा चेहरा कांग्रेस के पास नहीं है जो उस अंचल से प्रभावी भूमिका सदन के अंदर निभा सके।

मप्र कांग्रेस में जान फूंकने की जिम्मेदारी आलाकमान ने मुकुल वासनिक को दी है। वासनिक की बतौर प्रदेश प्रभारी यह दूसरी पारी होगी, क्योंकि वे पूर्व में भी राज्य के प्रभारी रह चुके हैं हालांकि इस समय और उस समय के हालातों में जमीन आसमान का अंतर है। उनकी पहली और दूसरी पारी के बीच राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका है। इस दौरान 15 साल का राजनीतिक वनवास भोगने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में बनी कांग्रेस सरकार 15 महीने में ही दलबदल के कारण सत्ता से बाहर हो गई। वासनिक के सामने अब यही चुनौती होगी कि उपचुनाव के माध्यम से क्या फिर से कांग्रेस अपनी उस सत्ता को पा सकती है जो उसे मतदाताओं के जनादेश से मिली थी। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह भी होगी कि पहले वे नेताओं के बीच तालमेल बिठाएं और कार्यकर्ताओं में सरकार जाने से जो निराशा आ गई है उसे उत्साह में बदलें। इसके साथ ही उन्हें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और सेवादल के राष्ट्रीय मुख्य संगठक रहे महेंद्र जोशी को भी आगे लाकर पार्टी की स्थिति सुधारने के लिए सक्रिय करना चाहिए। देखने की बात यही होगी कि क्या कांग्रेस की अनायास ही जो राहें पथरीली हो गई हैं और उसकी राह में जो कांटे बिछ गए हैं उसे हटाने व सुगम बनाने में वासनिक सफल हो पाएंगे।

वासनिक एक अनुभवी कांग्रेस नेता और मध्यप्रदेश की अंदरूनी गुटबंदी की जड़ें कितनी गहरी हैं उसे भलीभांति जानते हैं। 1980 के दशक में सबसे युवा लोकसभा सदस्य बनने के साथ ही तीन साल तक वे एनएसयूआई और दो साल तक युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने के बाद कांग्रेस पार्टी में वे हमेशा एक अहम नेता रहे हैं, सोनिया गांधी के विश्वासपात्रों में उनकी गिनती होती है। वे अपनी दूसरी पारी की शुरुआत जब करने जा रहे हैं तो दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सुरेश पचौरी जैसे नेताओं से उनका दोस्ताना संबंध काफी काम आएगा और वैसे भी प्रदेश में पहले से ही उनकी अपनी टीम है। प्रदेश में कांग्रेस संगठन यदि देखा जाए तो विजिटिंग कार्डधारी पदाधिकारियों से अटा पड़ा है, संगठन के नाम पर आज प्रदेशभर में प्रदेश व जिला स्तर के डेढ़ हजार से ज्यादा महासचिव और सचिव हैं।

प्रदेश कांग्रेस से लेकर जिला कांग्रेस तक कार्यकारी अध्यक्षों की भरमार है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशी नहीं बन पाए उन्हें संतुष्ट करने का ही यह नतीजा है कि दिन दूनी रात चौगुनी इनकी संख्या बढ़ती गई, यहां तक कि यदि प्रदेश कांग्रेस से रिकार्ड तलब किया जाए तो उनके पास भी इसकी पूरी जानकारी मिलेगी, क्योंकि कई लोगों को दिल्ली से तत्कालीन महासचिव बाबरिया ने सीधे पत्र लिख दिए। कई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों व मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में प्रदेश कांग्रेस में महत्वपूर्ण पदों पर रहे मानक अग्रवाल को भरोसा है कि वासनिक सारी चुनौतियां का सामना करने में सफल रहेंगे क्योंकि वे प्रदेश कांग्रेस के सभी छोटे-बड़े नेताओं को जानते-पहचानते हैं और सबकी बात सुनते व सबको साथ लेकर चलते हैं। मध्यप्रदेश की कांग्रेस की राजनीति से वे अनजान नहीं हैं और जितना वे जानते हैं उतना मौजूदा महासचिवों में से कोई नहीं जानता।

जैसी कि कांग्रेस की परम्परा रही है दीपक बाबरिया का त्यागपत्र स्वास्थगत कारणों से मंजूर किया गया है लेकिन सब भलीभांति जानते हैं कि उनकी विदाई के दो मुख्य कारण हैं उसमें पहला यह है कि वे प्रदेश कांग्रेस संगठन व सरकार के बीच समन्वय नहीं बना पाए जबकि दोनों के ही मुखिया कमलनाथ थे। प्रदेश कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता से न तो वे अपना तालमेल बिठा पाए और न ही उन नेताओं में सामंजस्य करा पाए। उनकी पटरी अनेक नेताओं से नहीं बैठ पाई और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनकी नजदीकी अंततः उनकी विदाई का कारण बनी। 15 साल बाद कांग्रेस सत्ता में लौटी थी लेकिन 15 माह के भीतर वे कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं को न तो सरकारी पद दिला पाए और ना ही उनकी कोई पूछपरख सत्ता के गलियारों में बढ़वा पाए। बाबरिया की दूसरी बड़ी चूक यह थी कि वे कांग्रेस जैसे संगठन को एनजीओ स्टाइल में चलाना चाहते थे जबकि इस प्रकार के लोग जमीनी वास्तविकताओं से कम सरोकार रखते हैं और अपने स्वयं की कल्पनाओं के अनुसार वे व्यवहारिक हैं या नहीं के स्थान पर कांग्रेस को अपनी स्वयं की कल्पनानुसार ढालने में लग जाते हैं।

● अरविंद नारद

कैसे होगी कोरोना से जंग...?

मप्र सहित देशभर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उधर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) और स्वास्थ्य मंत्रालय ने आकलन के बाद संकेत दिया है कि जून-जुलाई में कोरोना का संक्रमण चरम पर होगा। उस समय तक प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 84 हजार पहुंच जाएगी। ऐसे में प्रदेश सरकार को स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करने को कहा गया है। इसके लिए प्रदेशभर में 1975 वेंटिलेटर का इंतजाम करना होगा।

सूत्र बताते हैं कि आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय की इस रिपोर्ट के बाद मप्र सरकार सजग हो गई है। हालांकि सरकार का दावा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की गति कम हो गई है। यहां संक्रमित मरीज तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। फिर भी सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिया है। आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद प्रदेश सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। आकलन रिपोर्ट आने के बाद इतने बड़े पैमाने पर मरीजों को इलाज उपलब्ध कराने के लिए प्रदेशभर के 2621 निजी अस्पतालों की सूची तैयार कर ली गई है। लेकिन चिंता की बात है कि प्रदेश के अस्पतालों में पर्याप्त वेंटिलेटर नहीं हैं।

जून-जुलाई में 1975 वेंटिलेटर की जरूरत बताई गई है, जबकि प्रदेशभर के निजी अस्पतालों के पास मिलाकर भी 1000 (993) वेंटिलेटर तक नहीं है। ज्यादातर निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं है। कुछ जिले तो ऐसे भी हैं जहां एक भी वेंटिलेटर नहीं है। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में मरीजों को उपचार उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती रहेगी। आईसीएमआर के अनुमान से जुलाई तक भोपाल में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 10658 तक पहुंच जाएगी। इनके इलाज के लिए 533 वेंटिलेटर भी लगेंगे। जबकि वर्तमान में भोपाल में 273 वेंटिलेटर हैं। इन अनुमानों को देखते हुए शासन ने अपने स्तर पर व्यवस्था शुरू भी कर दी है। भोपाल के निजी अस्पतालों की सूची तैयार की गई है। सूची में अस्पतालों के साथ वहां उपलब्ध पलंग और वेंटिलेटर का जिक्र भी है। भोपाल के अलावा जिन जिलों में सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीज मिलने की आशंका जताई जा रही है उनमें इंदौर (13438), जबलपुर (7081) शामिल हैं।

विभाग द्वारा तैयार आकलन में यह अनुमान भी लगाया गया है कि इतनी बड़ी संख्या में मरीजों का इलाज करने के लिए कितने डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत पड़ेगी।

विभाग अस्पतालों से उनके यहां काम कर रहे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ की विस्तृत जानकारी भी मांगेगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। कोरोना संक्रमण की तीव्रता और इसके प्रसार की वजह से हो रहे बदलावों को लेकर आईसीएमआर प्रदेश के तीन जिलों सहित देश के 69 जिलों में सर्वे कराएगी। इन जिलों का चयन कोरोना के संक्रमण की तीव्र, मध्यम और धीमी प्रसार गति के आधार पर किया गया है। कोरोना के हॉटस्पॉट होने के बावजूद इंदौर और भोपाल सर्वे के लिए चुने गए जिलों में शामिल नहीं हैं। प्रदेश के जिन जिलों में सर्वे होना है, उनमें देवास, उज्जैन और ग्वालियर शामिल हैं। आईसीएमआर से मिली जानकारी के अनुसार, यह सर्वेक्षण समुदाय आधारित होगा। 24 हजार वयस्कों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य कोरोना संक्रमण की व्यापकता का अनुमान लगाना है जिससे भविष्य की रणनीति तय की जा सके। इस शोध के साथ ही आईसीएमआर अस्पताल आधारित निगरानी भी शुरू कर रही है।

● विशाल गर्ग

यहां इतने मरीज होने का है अनुमान

शहर	मरीज होने का अनुमान	वेंटिलेटर लगेंगे
इंदौर	13438	672
भोपाल	10658	533
जबलपुर	7081	71
उज्जैन	4310	215
खंडवा	3198	32
धार	3369	34
देवास	2020	20
बड़वानी	1170	12
खरगोन	3461	35
मंदसौर	2546	25
आगर	882	09
बुरहानपुर	2179	22
झाबुआ	513	05

75,000 लोगों के लिए सिर्फ एक वेंटिलेटर

मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की पिछले कुछ दिनों से तेजी से बढ़ रही संख्या को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिन और भी चुनौतीपूर्ण होंगे। राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े आंकड़ों के अनुसार राज्य में वेंटिलेटर और आईसीयू में बिस्तरों की स्थिति भी विकट हो सकती है, यदि संक्रमितों के आंकड़ों में कमी लाने को लेकर गंभीर प्रयास नहीं किए गए। मध्य प्रदेश सरकार के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि मध्य प्रदेश में प्रति 75,000 लोगों के लिए केवल एक वेंटिलेटर है और प्रति 47,000 लोगों के लिए मात्र एक आईसीयू बेड उपलब्ध है। हालांकि, राज्य सरकार के लिए यह संतोष की बात है कि इस महामारी से लड़ने के लिए कारगर मानी जा रही हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन की गोलियां वर्तमान में प्रति व्यक्ति करीब 30 (गोलियां) उपलब्ध हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार साढ़े सात करोड़ से अधिक आबादी वाले मध्य प्रदेश में सरकारी एवं निजी अस्पतालों को मिलाकर कुल 993 वेंटिलेटर और गहन चिकित्सा विभाग (आईसीयू) के 1,598 आईसीयू बेड उपलब्ध हैं। प्रदेश की साढ़े सात करोड़ से अधिक आबादी के साथ इन वेंटिलेटरों और आईसीयू बेड की तुलना करने पर पता चलता है कि करीब प्रति 75,000 लोगों के लिए एक वेंटिलेटर है और प्रति 47,000 लोगों के लिए एक आईसीयू बेड है। लेकिन, इन वेंटिलेटरों एवं आईसीयू बेड में से अधिकांश पर पहले से ही अन्य बीमारियों से जूझ रहे अति गंभीर मरीज हैं, जिससे मुसीबत और बढ़ सकती है। आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के अस्पतालों में कुल 29,914 बेड हैं, जिनमें से 9,492 आइसोलेशन (पृथक) वार्ड हैं।

लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया है कि किसी आपदा को झेलने के लिए देश की माली हालत ठीक होना कितना जरूरी होती है। अर्थव्यवस्थाएं रातोंरात मजबूत नहीं बन सकतीं। यानी कोरोना के संकट के बीच दूर भविष्य की बात करना फिजूल है। कोरोना से भले न निपट पा रहे हों लेकिन कोरोना से उपजी तात्कालिक समस्याओं से निपटना भी उतना ही जरूरी है। ऐसी ही एक सबसे बड़ी समस्या भड़की है बेरोजगारी की। हाल ही में सीएमआईई की रिपोर्ट में बताया गया है कि आपदा से बचाव के लिए लगे लॉकडाउन से 11 करोड़ 40 लाख मजदूर और कामगार बेरोजगार हो गए। यह संख्या रोजगार पर लगे 40 करोड़ कामगारों की एक चौथाई है। यह भी याद रहना चाहिए कि कोरोना के पहले से ही बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई थी। यानी कोरोना ने बेरोजगारी की आग में तेल डाल दिया।

यह मान्यता नई नहीं है। जब कभी भी देश में जीडीपी के आंकड़े अच्छे आया करते थे तो उस समय की सरकार के आलोचक कहा करते थे कि यह जॉब लैस ग्रोथ है। यानी बेरोजगारी के साथ आर्थिक वृद्धि किस काम की। उधर सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता था कि आर्थिक वृद्धि ही रोजगार पैदा करेगी। अर्थशास्त्री बताते हैं कि होता भी यही है। सरकार के पास पैसे हों तो वह रोजगार पैदा करने वाली योजनाएं चलवा देती है। लेकिन मौजूदा हालात इसलिए विकट हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर हम पहले से ही मुश्किल में चल रहे थे। पिछले दो साल से लगभग हर तिमाही में जीडीपी का आंकड़ा नीचे ही आता जा रहा था। ऐसे में बेरोजगारी के अभूतपूर्व संकट की गंभीरता को, जितनी जल्दी हो, समझ जाना चाहिए। सीएमआईई की यह रिपोर्ट बस एक सर्वेक्षण भर है। यानी यह एक मोटा अंदाजाभर है। तथ्यों के अभाव में अभी बिल्कुल भी पता नहीं है कि पहले से बेरोजगारी का आकार या वजन क्या था। लेकिन लॉकडाउन से घबराए प्रवासी मजदूरों की जितनी बड़ी भीड़ शहरों से अपने घरगांव की तरफ भागती दिख रही है उससे बेरोजगारी की भयावहता का अंदाजा मुश्किल नहीं है। ये प्रवासी मजदूर अपने गांवों में बेरोजगारी के पुराने हालात पर क्या असर डालेंगे इसका अनुमान भी कठिन नहीं है। मोटा अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहले से छद्म बेरोजगारी से पीड़ित गांवों में बेरोजगारी अब दोगुनी-तिगुनी बढ़ने का अंदेशा सर पर आ खड़ा हुआ है। छद्म बेरोजगारी उसे कहते हैं जहां एक ही काम पर जरूरत से ज्यादा लोग लगे हों। अर्थव्यवस्था की पुख्ता नींव ने अब तक हालात भले ही संभाले रखे हों लेकिन इस समय अगर बेरोजगारी से नहीं निपटा गया तो अपनी 200 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था धरी रह जाएगी। बेशक किसी भी देश की

बेरोजगारी की आग

अर्थव्यवस्था उस देश में उत्पादित माल के सहारे चलती है। नियम है कि माल उत्पादित तभी होता है जब उसकी मांग हो। जबकि यह भारी मंदी का संकट काल है। संकट पहले से भी चला आ रहा था। कई तिमाहियों से अधिकांश उपभोक्ताओं की आमदनी घटने से माल की मांग घट रही थी। देश से माल का निर्यात का आंकड़ा बढ़ नहीं रहा था। हालांकि अपनी बड़ी भारी आबादी के कारण हम खुद में एक बड़ा और विश्वप्रसिद्ध बाजार हैं। लिहाजा पहले भी जरूरत थी और आज तो और ज्यादा जरूरी है कि हम घरेलू उपभोक्ता को मजबूत बनाएं और घरेलू बाजार में माल की मांग पैदा करने का मौका बनाएं।

यह बात तो शौकिया अर्थशास्त्री भी जानते हैं कि मांग तब बढ़ती है जब अधिकांश उपभोक्ताओं की जेब में पर्याप्त पैसा हो। अक्सर सरकारी अर्थशास्त्री अपनी इच्छापूर्ण सोच के चलते यह समझा देते हैं कि उत्पादन कम इसलिए हो रहा है क्योंकि उत्पादकों को पैसे की दिक्कत आ रही है और इसलिए वे माल नहीं बना पा रहे हैं। कोरोना के बहुत पहले से सरकारी अर्थशास्त्रियों ने उद्योग व्यापार जगत को तरह-तरह के राहत पैकेज और भारी भरकम कर्ज बंटवाने का इंतजाम करवा दिया था। बात चार-छह महीने पुरानी ही हुई है सो इस तरह की सोच के नतीजे अभी सामने आए नहीं हैं। लेकिन इतना तय है कि भारतीय उद्योग व्यापार अब इंतजार करेगा कि कोरोना के बाद बाजार से मांग आए तभी वह उत्पादन करने के बारे में सोचे। मांग पहले या उत्पादन पहले, इस फच्चर को अभी से समझ लेना ही समझदारी है।

● राजेश बोरकर

उद्योग जगत ने हाथ खड़े कर दिए

अर्थजगत की दीवार पर इबारत साफ लिखी है। उद्योग जगत ने प्रवासी मजदूरों को घर जाने से रोकने की कोई पहल नहीं की। कहते हैं कि बहुत से मजदूरों को पिछला बकाया भी नहीं मिला। फिर भी बेरोजगारी से घबराए मजदूर अपने गांव लौट पड़े। इससे उद्योग जगत के हालात और उसकी मंशा का अंदाजा लगता है। यानी दो-चार महीने उद्योग जगत का चक्का चल पड़ने के आसार नजर नहीं आते। उतने अर्से बाद उत्पादक इकाइयां अगर उत्पादन शुरू करने में लगेंगी तो सबसे पहले यही देखेंगी कि उनके बनाए माल के खपने की गुंजाइश बन गई है या नहीं। घरेलू उपभोक्ताओं की जेब में पैसा डालें या किसी तरह दूसरे देशों में माल के निर्यात के लिए ताबड़तोड़ ऑर्डर का जुगाड़ करें। सरकार के लिए पहला विकल्प खर्चीला है। इतने भारी भरकम सरकारी खर्च और उससे उपजी महंगाई का जाखिम उठाने का माद्दा चाहिए पड़ेगा। रही बात रातोंरात निर्यात बढ़ाने की तो यह कोई भी बता देगा कि कोरोना काल में या कोरोना बाद के काल में दूसरे देशों की हालत भी उतनी ही पतली होगी। वे तो खुद ही अपनी अर्थव्यवस्था संभालने के लिए गरीब और कमजोर देशों पर अपना माल खरीदने की दबिश बना रहे होंगे। चीन की तरह निर्यात का तंत्र विकसित करने में सालों साल लग जाते हैं। सो अपने पास एक ही विकल्प नजर आता है कि अपने घरेलू उपभोक्ताओं को ही अर्थव्यवस्था का संकट मोचक मान लें।

राशन तो मिला पीने को पानी नहीं

फूस की झोपड़ी के नीचे हल को कुल्हाड़ी से मरम्मत कर रहे है 55 साल के सुंदर धुर्वे की एक चिंता कई पीढ़ियों से चली आ रही है। चिंता का नाम जल है। दरअसल, मप्र के आदिवासी बहुल जिलों में पीने के पानी की समस्या सबसे बड़ी है। यहां के लोगों का कहना है कि राशन तो आसानी से मिल जाता है लेकिन पीने का पानी खोजना मुश्किल भरा होता है। आदिवासी टोलों के अधिकतर लोग नदी का पानी पीकर जिंदगी जी रहे हैं। उन्हीं में शामिल हैं सुंदर धुर्वे। वे कहते हैं, कई पीढ़ी से नदी का पानी पीकर जिंदगी गुजर कर रहे है। मजदूरी से राशन चलता था, लेकिन अब वो भी बंद है। सुंदर धुर्वे के परिवार में उनके बूढ़े मां-बाप के अलावा दो बच्चे भी हैं। कहते हैं कि इस बार सरकारी राशन टाइम पर मिल गया है, जिससे खाने की परेशानी तो थोड़ी कम हो गई है, लेकिन पानी की समस्या पहले की ही तरह है।

दरअसल, यह एक व्यक्ति या एक परिवार की समस्या नहीं है, बल्कि मप्र के आदिवासी बहुल जिलों मंडला, डिंडौरी, झाबुआ सहित कई जिलों में आदिवासी लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। आदिवासियों को पानी देना सरकार की प्राथमिकता ही नहीं है। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के सभी आदिम जनजातीय बहुल इलाके बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। सीधी में विलुप्त होती बैगा जनजाति के कल्याण के लिए उत्थान के लिए बना 'बैगा प्रोजेक्ट' फेल हो गया है। जिले के कुसुमी क्षेत्र के दूरदराज के इलाकों में पानी की बूंद-बूंद के लिए संघर्ष है। मनडोलिया में हैंडपंप लगे हैं, लेकिन दो साल से सब सूख गए हैं। रोजगार गारंटी के तहत बनाया कुआं भी काम नहीं कर रहा है। हैंडपंप और कुआं सूखने के बाद अब गंदे नाले पानी के 'स्त्रोत' के अलावा उनके पास कोई 'विकल्प' नहीं बचा है।

सीहोर में भी तीन दर्जन से अधिक आदिवासी परिवार गंदे नाले से पानी लाने को विवश हैं। गुना जिले के चांचौड़ा और बीनागंज में जलापूर्ति की लाइन पिछले पांच दशक से जंग खाकर खत्म होने के कगार पर हैं। एक स्थानीय बुजुर्ग कहते हैं कि खानपुरा तालाब से सत्तर के दशक में दो वाटर फिल्टर प्लांट बनाए गए थे जिनसे पानी फिल्टर करके सप्लाई किया जाता था। स्थानीय निवासी यह भी शिकायत कर रहे हैं कि वाटर फिल्टर प्लांट जाम हो चुके हैं। जिससे अब 10 इंची की जगह 3 इंची पाइप से पानी सप्लाई होता है। एक ही प्लांट होने के कारण प्लांट की सफाई करना ही संभव नहीं है। ऐसा करेंगे तो सफाई कार्य के चलते दो सप्ताह तक जलापूर्ति रुक जाएगी। चांचौड़ा एवं बीनागंज में चार-चार टैंकर जल आपूर्ति के लिए लगाए गए हैं लेकिन वो नाकाफी हैं।

नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है, 'गांवों में 84 प्रतिशत आबादी जलापूर्ति से वंचित है। जिन्हें पानी मिल रहा है, उसमें 70 प्रतिशत प्रदूषित है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 20 प्रतिशत भूजल के स्त्रोत का अति शोषण हो रहा है। बारिश के पानी को बचाने के लिए, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की जरूरत है। यहां खेती का 60 फीसदी से ज्यादा हिस्सा सिंचाई के लिए बारिश के पानी पर निर्भर है। हार्वेस्टिंग के लिए केवल 40 फीसदी हिस्से में काम हो पाया है। राज्य शहरों में गंदे पानी के ट्रीटमेंट में फिसड्डी है। यहां शहरों में केवल 3 प्रतिशत गंदे पानी का ट्रीटमेंट होता है। वैश्विक जल गुणवत्ता सूचकांक में 122 देशों में भारत 120वें स्थान पर है।

मध्य प्रदेश का श्योपुर आदिवासियों के साथ घोर अन्याय का प्रतीक है। यह अभावों की धरती है। लेकिन सियासी रोटी सेंकने के लिए माकूल जगह भी है। सारे ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्तर तेजी से गिर गया है। हैंडपंप पानी नहीं दे रहे। जंगल से लगे गांवों में पानी की समस्या और भी गंभीर है। पानी की समस्या को लेकर लोग प्रशासन की एक जनसुनवाई में पहुंचे तो हकीकत कैमरों में कैद हुई। चंद्रपुरा गांव की सुमिला अन्य 25 से अधिक महिलाओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचीं थीं। महिलाओं ने कहा कि हैंडपंप खराब हो गए हैं। दूर खेतों से पानी ढोकर लाना पड़ रहा है। बहरहाल पेयजल की इस हालत में खेती और सिंचाई की बात बेमानी है। आलम यह है कि चुनावों के दौरान नेता यहां पेयजल उपलब्ध कराने का वादा करते हैं लेकिन आज तक स्थिति जस की तस है।

● **विकास दुबे**

नीति आयोग की नीति कारगर नहीं

नीति आयोग देश के समाज और अर्थ-वैज्ञानियों की जिम्मेदार संस्था है। उसकी रिपोर्ट में गंभीर जल संकट की ओर इशारा किया गया है। एक लाइन में कहें तो देश में 60 करोड़ लोगों के सामने पानी का गंभीर संकट है। यह देश के इतिहास के सबसे गंभीर जल संकट का दौर है। पानी की कमी से लाखों लोगों की जान और उनकी आजीविका पर खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, कई राज्य, जिनमें मप्र का पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ भी है, में जल प्रबंधन की स्थिति बेहद खराब है। 75 प्रतिशत आबादी पीने के पानी के लिए दूर-दूर तक जाती है। इसके बावजूद जल प्रबंधन को लेकर कई राज्य गंभीर नहीं हैं। गौरतलब है कि आयोग ने जल प्रबंधन में गुजरात को सबसे अव्वल तो मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र को क्रम से दो से पांच तक के अंक दिए हैं। देश के 50 राज्य ऐसे हैं जहां पेयजल शुद्धता और गंदे पानी को ट्रीटमेंट के बाद उपयोगी बनाने की दिशा में काम करना अनिवार्य हो गया है। वॉटर हार्वेस्टिंग के बिना ऐसा संभव नहीं है। नीति आयोग ने सभी राज्यों के लिए नीति बनाकर जल शोधन का निर्देश दिया था, लेकिन अधिकांश राज्यों ने उसके निर्देशों का पालन नहीं किया। ऐसे राज्यों में मप्र भी शामिल है। अगर सरकार गंभीरता से इस दिशा में नीति बनाकर काम करती तो आज आदिवासियों के सामने विकट समस्या नहीं रहती।

कोरोना संकट के बीच मप्र की खाली पड़ी 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। चुनाव आयोग के साथ ही भाजपा और कांग्रेस ने भी अपने-अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने जहां प्रत्याशियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं भाजपा सभी सीटों को जिताने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दी है। भाजपा को उम्मीद है कि यह त्रिमूर्ति सभी सीटों को जीताकर कांग्रेस को करारा जवाब देंगे।

त्रिमूर्ति के भरोसे भाजपा

मप्र में 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव शिवराज सरकार का भविष्य तय करेंगे। 230 सदस्यीय मप्र विधानसभा में बहुमत के लिए 116 विधायक होने चाहिए। भाजपा के पास अभी 107 विधायक हैं। 22 विधायकों के इस्तीफे और दो विधायकों के निधन के कारण सदन की सदस्य संख्या 206 रह गई है। इस आधार पर शिवराज की सरकार ने सदन में विश्वास मत जीत लिया। उसे बसपा के दो, सपा के एक और दो निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन मिल गया। विधानसभा की खाली 24 सीटों के लिए उपचुनाव में कम से कम 10 सीटें जीतकर लाना होगा, तभी बहुमत के आंकड़े को वह छू सकेगी। लेकिन भाजपा ने सभी 24 सीटों का जीतने का टारगेट बनाया है और उसे 'मिशन 24' नाम दिया है। इस मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और नरेंद्र सिंह तोमर को दी है।

गौरतलब है कि उपचुनाव वाली 24 सीटों में से अधिकांश चंबल, मालवा और मध्य भारत क्षेत्र की हैं। ये सिंधिया, तोमर और शिवराज के प्रभाव वाली सीटें हैं। इसलिए भाजपा आलाकमान ने इन तीनों नेताओं को इन सीटों का जिताने की जिम्मेदारी दे दी है। दरअसल, ये उपचुनाव बागी विधायकों के लिए आसान नहीं होने वाले हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति वफादारी दिखाने वाले इन माननीयों की राह में कांग्रेसियों के अलावा पहले के प्रतिद्वंद्वी रहे भाजपाई भी कांटे बिछाने में सक्रिय हो गए हैं। इससे इनका सियासी कैरियर भी दांव पर लग गया है।

गौरतलब है कि मप्र के दो विधायकों के निधन और कांग्रेस के 22 बागी विधायकों के इस्तीफे से रिक्त विधानसभा की कुल 24 सीटों पर एक साथ उपचुनाव होने हैं। जिन सीटों पर चुनाव होने हैं वे हैं-जौरा, आगर (अजा), ग्वालियर, डबरा (अजा), बमोरी सुरखी, सांची (अजा), सांवेर (अजा), सुमावली, मुरैना, दिमनी, अंबाह (अजा), मेहगांव, गोहद (अजा), ग्वालियर (पूर्व), भांडेर (अजा), करैरा (अजा), पोहरी, अशोकनगर (अजा), मुंगावली, अनूपपुर (अजजा), हाटपिपल्या, बदनावर, सुवासरा। इनमें से 16 सीटें सिंधिया के गढ़ ग्वालियर-चंबल संभाग की हैं। जौरा सीट पर भाजपा को नए प्रत्याशी की खोज है। वहीं 15 अन्य सीटों पर वही प्रत्याशी उतारे जाएंगे, जो 2018 में कांग्रेस से चुनाव जीते थे। वहीं कांग्रेस को इन सभी सीटों पर नए प्रत्याशी की खोज है। 24 विधानसभा सीटों के उपचुनाव परिणाम पर भाजपा और कांग्रेस का भविष्य टिका है। अगर भाजपा करीब एक दर्जन सीटें जीत लेती है तो वह सत्ता में बनी रहेगी। वहीं अगर कांग्रेस अपनी कब्जे वाली सीटों को जीत लेती है तो वह सत्ता में आ जाएगी। ऐसे में ये उपचुनाव कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है। भाजपा के प्रत्याशियों के सामने दोहरी चुनौती है, वहीं कांग्रेस को अपने ही नेताओं और कार्यकर्ताओं से भितरघात का खतरा है। ऐसे में भाजपा की त्रिमूर्ति के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है।

मध्यप्रदेश के इतिहास में पहली मर्तबा 24 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की परिस्थितियां पैदा हो गई हैं और चुनाव परिणाम तक प्रदेश की सियासत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इर्द-गिर्द घूमती रहेगी। उपचुनाव परिणाम के नतीजे क्या होंगे उसके मुख्य किरदारों की भूमिका में शिवराज, ज्योतिरादित्य, तोमर और कमलनाथ ही होंगे, क्योंकि मतदाताओं के सामने ये चार चेहरे होंगे और 22 दलबदलू विधायकों की चुनावी वैतरणी पार लगेगी या नहीं यह इनके अपने-अपने करिश्मे पर निर्भर करेगी। जहां तक

तोमर का प्रभाव दांव पर

मध्यप्रदेश में भाजपा की सरकार वापस लाने में केंद्रीय मंत्री और पार्टी नेता नरेंद्र सिंह तोमर की बड़ी और निर्णायक भूमिका रही है। मिशन कमल को गुपचुप तरीके से चलाने और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा खेमे में लाने की व्यूह रचना में तोमर बड़े रणनीतिकार बनकर उभरे हैं। ये तब है कि जब नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों की राजनीति ही ग्वालियर संभाग में परस्पर विरोध के आधार पर ही चलती है। चंबल और ग्वालियर संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ कर दिया था और वर्चस्व की लड़ाई अपने नाम कर ली थी। दोनों ही नेताओं में राजनीतिक अदावत पुरानी रही है। बावजूद इसके शीर्ष नेतृत्व के कहने पर मिशन कमल को सफल बनाने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर ने ज्योतिरादित्य से गुपचुप दिल्ली में कई दौर की बातचीत की। अब तोमर के सामने उपचुनाव में सभी 24 विधानसभा सीटों को जिताने की जिम्मेदारी है। मप्र की राजनीति में तोमर और शिवराज की दोस्ती ख्यात है। तोमर हमेशा समन्वय की राजनीति करते आए हैं।

उपचुनावों में सिंधिया को सबक सिखाने की तैयारी

उधर, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अब बागी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और 22 पूर्व विधायकों को नाकों चने चबवाने की तैयारी कर रहे हैं। कमलनाथ को भरोसा है कि सिंधिया और भाजपा दोनों को मुंह की खानी पड़ेगी। ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के कद्दावर नेता गोविंद सिंह को भी लग रहा है कि उपचुनाव में भाजपा और सिंधिया दोनों को पता चल जाएगा कि उनकी क्या हैसियत है। गोविंद सिंह कहते हैं कि सिंधिया जानते हैं कि उपचुनाव आसान नहीं होगा। इसलिए वह शिवराज मंत्रिमंडल से लेकर केंद्र सरकार में अधिक से अधिक सत्ता पा लेना चाहते हैं। अभी जितना चाहें दबाव बनाकर भाजपा को पिघला लें, लेकिन बाद में मुश्किल होगी। ग्वालियर में लाखन सिंह, मुरैना में कांग्रेस जिलाध्यक्ष और रवींद्र सिंह तोमर जैसे कई नेताओं के बूते कांग्रेस बड़ी चुनौती देगी। बता दें ग्वालियर-चंबल संभाग में कांग्रेस के पास गोविंद सिंह और केपी सिंह, ये दो बड़े विधायक नेता हैं। सिंधिया से विरोध करके भी ये चुनाव नहीं हारे। गहरी पकड़ रखते हैं। इस समय कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के लिए न केवल भरोसेमंद हैं, बल्कि सिंधिया के खिलाफ मजबूत हथियार हैं। गोविंद सिंह का कहना है कि कांग्रेस में वे 'महाराज' ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। हाईकमान तक पहुंच थी और दबाव बनाकर 40-50 नेताओं को टिकट दिलवाते थे। इनमें से अधिकांश हार जाते थे। जिन्हें सिंधिया को नजरअंदाज करके टिकट मिलता था, खुल्लम-खुल्ला उन्हें हरवाने में लग जाते थे। कोई कुछ बोल नहीं पाता था। यहां जनता तो जनता, नेता से भी हाथ नहीं मिलाते थे। समय नहीं रहता था। वहां (भाजपा) नेताओं के चक्कर काट रहे हैं।

शिवराज का सवाल है चौथी बार प्रदेश की कमान संभालते ही उन्हें अकेले वन-मेन आर्मी की तरह चुस्ती-फुर्ती, मुस्तैदी तथा दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ विश्वव्यापी कोरोना महामारी की जंग में कूदना पड़ा। जब उन्होंने सत्ता की बागडोर संभाली तो उनके सामने केवल यही अकेली चुनौती नहीं थी बल्कि उनके सामने और भी अनेक चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। पहली चुनौती है 24 विधानसभा सीटों के उपचुनावों में से कम से कम आधे से अधिक सीटों पर भाजपा की विजय पताका लहराना। मप्र में शिवराज सिंह चौहान एकमात्र नेता हैं जिनका जादू गांव-कस्बों से लेकर शहर तक एक समान है। शिवराज आज भी लोगों के दिलों-दिमाग पर छाए हुए हैं। यही कारण है कि जब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ तो आलाकमान ने उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाने में तनिक भी झिझक नहीं दिखाई। शिवराज चौथी बार मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन उनके सामने कोरोना वायरस के संक्रमण के रूप में बड़ी चुनौती खड़ी है। इस चुनौती के खत्म होते ही उपचुनाव का पहाड़ सामने आ जाएगा। मुख्यमंत्री होने के नाते शिवराज पर सभी 24 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी है। एक तो उन्हें अपनी सरकार बचाना है, वहीं आलाकमान के टारगेट को भी पूरा करना है। इसलिए उनके सामने चुनौतियों की भरमार है। एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि सभी सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों से शिवराज सिंह चौहान के व्यक्तिगत संबंध और घनिष्ठता बहुत जबर्दस्त है। इस लिहाज से भी स्वाभाविक तौर पर उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। प्रदेश में उनकी लोकप्रियता ज्यादा है और प्रदेश में उनकी तरह का दूसरा कोई नेता नहीं है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि पार्टी ने उन पर उपचुनाव जिताने की जिम्मेदारी बड़ी सोच-समझकर सौंपी है। सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों के साथ उनके समीकरण भी अच्छे हैं। इसलिए शिवराज इन सीटों को जीतने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे।

गौरतलब है कि शिवराज की मध्य क्षेत्र के मतदाताओं में जितनी पकड़ है, उतनी ही प्रदेश के अन्य क्षेत्र के मतदाताओं में। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर-चंबल अंचल ने ही चौथी बार सरकार बनाने में बैरिकेड्स लगा दिया था। एक बार फिर ग्वालियर-चंबल अंचल को तय करना है कि भोपाल में शिवराज सरकार रहेगी या फिर कमलनाथ सरकार की वापसी होगी। क्योंकि उपचुनाव में अंचल की 16 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना हैं। इन 16 विधानसभा क्षेत्रों से चुने गए विधायकों के कारण ही कांग्रेस सरकार से बाहर हुई है। इन सभी पूर्व विधायकों ने शिवराज पर भरोसा जताया है। इसलिए उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है।

भाजपा आलाकमान ने उपचुनाव जीतने के लिए जो त्रिमूर्ति बनाई है, उसमें सबसे अधिक भार सिंधिया पर होगा। दरअसल, सिंधिया के सामने हिमालयीन चुनौती है सभी 22 दलबदलुओं को चुनावी वैतरणी पार कराना। क्योंकि उन्होंने अगाध श्रद्धा और एक सीमा तक स्वयं के हितों को साधने के लिए दलबदल किया एवं पिछले चुनाव में जो जनादेश कांग्रेस को मिला था उसे उलट दिया। ज्योतिरादित्य को सही मायनों में इन उपचुनावों में एक प्रकार की अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ेगा और उनके साथ गए अधिकांश विधायक दोबारा नहीं जीत पाए तो फिर उनका भी राजनीतिक कद और महत्ता उस अंचल में भाजपा की नजर में कम हो जाएगी जिसे वे अपना इलाका मानते हैं। जहां तक उनका स्वयं का सवाल है वे स्वयं अपने ही गृह निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार से 2019 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह पराजित हो गए थे इसलिए इन उपचुनावों में उनके सामने एक और मौका है कि वे यह साबित करें कि उनकी पकड़ अभी भी मजबूत है। लेकिन यह इलाका एक-दो अपवादों को छोड़कर भाजपा का मजबूत गढ़ रहा है और भाजपा के बड़े नेता नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, डॉ. नरोत्तम मिश्रा, प्रभात झा, अनूप मिश्रा, जयभान सिंह पवैया भी इसी क्षेत्र के हैं। इन सब लोगों ने लगातार संघर्ष कर भाजपा की जड़ें काफी गहरे तक जमा दी हैं। इन सबके चलते भी यहां की अधिकांश सीटें उपचुनाव में जीतने के बाद भी ज्योतिरादित्य उतना बड़ा श्रेय नहीं ले पाएंगे जितना वे कांग्रेस की जीत के लिए लेते रहे हैं।

दलबदलुओं को आसानी से चुनाव जिताना स्वयं सिंधिया के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि अब कांग्रेस जोरशोर से इस बात का प्रचार करेगी कि इन्होंने जनादेश के साथ छल किया है तो दूसरे सिंधिया ने भी किसी बड़े पद की आकांक्षा में कांग्रेस छोड़ी है। सिंधिया राजपरिवार की पुरानी पृष्ठभूमि को भी अब कांग्रेसजन जोरशोर से उठाने की कोशिश करेंगे। इन सबके बीच मतदाताओं के गले कौन-सी बात उतरती है यह उपचुनाव के नतीजों से ही पता चलेगा।

● **कुमार विनोद**

निर्मल हो गईं नदियां

जो काम बड़े अभियान नहीं कर पाए कोरोनाकाल में हो गया

लॉकडाउन ने नदियों को सांस लेने की स्थिति में ला दिया है जो अब से पहले वेंटिलेटर पर थीं। इंदौर की खान नदी की बात हो या फिर उज्जैन की क्षिप्रा की या फिर बात करें गंगा-यमुना, नर्मदा की। सभी की हालत लॉकडाउन से पहले बहुत खराब थी। केंद्रीय भू-जल बोर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन से पहले इनमें लैड, मैग्नीज और लोहे की मात्रा अत्यधिक थी। यह पानी किसी भी योग्य नहीं बचा था। कई नदियों के पानी में इतनी भी ऑक्सीजन नहीं बची थी कि इसमें जलीय जीव भी रह सकें। कहा तो यहां तक जाता है कि पहले इन नदियों के पानी में सिक्का डालने पर भी दिखाई देता था और हाथ में पानी लेने पर हाथ की रेखाएं भी नहीं दिखाई देती थीं। नदियों के जानकार कहते हैं कि हाल में नदियों की स्थिति 30 फीसदी तक सुधरी हैं। जो तमाम प्रयासों के बाद भी नहीं सुधर रही थी। नदियों की दशा सुधरने के पीछे लॉकडाउन में इंडस्ट्री का बंद होना बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि नदियों के किनारे लगे उद्योग अपना अपशिष्ट वहीं नदियों में गिरा रहे थे। जो अब बंद हो गया। यूं तो नदियों को ऑक्सीजन देने के लिए तमाम प्रयास किए गए, लेकिन नदियों को वेंटिलेटर से हटाने की स्थिति कभी नहीं बन पाई। वर्तमान सरकार ने भी गंगा को स्वच्छ करने के लिए नमामि गंगे योजना बनाई। इसके लिए 20 हजार करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, पर गंगा निर्मल नहीं हुई। यमुना की सफाई पर भी 25 वर्ष में 1514 करोड़ रुपया खर्चा किया गया, लेकिन उसका कोई अधिक असर नहीं दिखा। लेकिन कोरोना के कारण किए गए लॉकडाउन में नदियों को नया जीवन मिल गया है।

कोरोना संक्रमण भले ही मानव के लिए महामारी है, लेकिन प्रकृति के लिए यह वरदान साबित हुआ है। शहरों में अरसे बाद लोगों ने कोयल की मधुर आवाज सुनी। पेड़ों पर चिड़ियों के घोंसले बनने लगे हैं। सड़क से लेकर आसमान तक कहीं धुंआ नहीं। नदियों का पानी भी इतना साफ कि आप उसमें अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। डर के कारण नदी के बीच में रहने वाली मछलियां अब बेखौफ होकर किनारे तक आ रही हैं। पहले लोग ताजी हवा लेने के लिए घरों से निकलकर पार्कों में जाते थे, परंतु अब घर बैठे ही साफ व स्वच्छ हवा मिल रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) कम हो गया है।

देश की प्रसिद्ध नदियों गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी और नर्मदा का जल इतना स्वच्छ और निर्मल हो गया कि अब इसमें बेधड़क आचमन कर सकते हैं। लॉकडाउन के कारण पर्यावरण की शुद्धता का स्तर बढ़ गया है। हवा तो शुद्ध हुई ही है, नर्मदा नदी भी निर्मल हो रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अप्रैल में नर्मदा के जल की 13 स्थानों पर जांच की। इसके नतीजे बताते हैं कि नर्मदा 15-20 साल में इतनी शुद्ध और निर्मल हुई है। कई स्थानों पर नदी के जल में बीओडी (बॉयो केमिकल डिमांड) और टीडीएस (टोटल डिजॉल्व सॉलिड) का स्तर पहले की तुलना में काफी कम हुआ है और नदी के जल की गुणवत्ता पहले से काफी बेहतर हो गई है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने पिछले दिनों बरगी, जबलपुर, तिलवारा घाट, पंचवटीघाट समेत मंडला से नरसिंहपुर तक मां नर्मदा के 13 पॉइंट के जल के सैंपल लेकर जांच की। जांच में नर्मदा इतनी शुद्ध पाई गई कि आचमन करने से भी कतराने वाले लोग अब नर्मदा के शुद्ध जल से आचमन कर सकते हैं। लॉकडाउन मां नर्मदा के लिए वरदान साबित हुआ है। बंद कारखानों, फूल-माला, दीपदान, लोगों द्वारा किए जाने वाले स्नान, घाटों पर कपड़ों की धुलाई और गंदगी का स्तर एक महीने में जीरो हो गया है। इस वजह से नर्मदा का जल स्वच्छ और निर्मल होकर बिल्कुल मिनरल वाटर जैसा हो गया है। नर्मदा जल की शुद्धता का स्तर ए ग्रेड में पहुंच गया है। टीडीएस (टोटल डिजॉल्व सॉलिड) पानी में घुले ठोस पदार्थ इसमें खनिज, धातु, अनाज या अन्य पदार्थ शामिल होता है। सामान्यत: नर्मदा जल में इसकी मात्रा 200 से 350 मिलीग्राम प्रति लीटर मिलती थी। लॉकडाउन में अप्रैल 2020 में ये 150 से 200 मिलीग्राम प्रति लीटर मिली है। ये जितना कम होता है पानी उतना ही शुद्ध माना जाता है। इसी वजह से नर्मदा का पानी ए ग्रेड में आ गया है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जांच के नतीजे बताते हैं कि वर्तमान में नर्मदा में टीडीएस की मात्रा लॉकडाउन के पहले के मुकाबले 30 फीसदी तक घट गई है। मतलब साफ है कि अब नर्मदा का पानी मिनरल वाटर जैसा पीने योग्य हो गया है।

नदियों में आर्गेनिक वेस्ट, सीवेज मिलने से बीओडी (बायोकैमिकल ऑक्सीजन डिमांड) का स्तर बढ़ता है। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मंडला से जबलपुर के बीच 13 पॉइंट पर जांच की। मार्च 2020 तक इसका स्तर प्रति मिलीग्राम 1.8 या 1.9 प्रति मिलीग्राम प्रति लीटर तक रहा। वह अप्रैल 2020 की जांच में 0.7 से 1 प्रति मिलीग्राम तक आ गया। जैविक ऑक्सीजन की मांग की बात करें तो इसे पीने योग्य पानी में 3 मिलीलीटर प्रति ग्राम से कम होना चाहिए। वर्तमान में बीओडी कई स्थानों पर एक मिलीलीटर प्रति ग्राम से भी कम पाई गई है। इतने कम बीओडी ने नर्मदा जल में मछलियों की संख्या को भी अचानक से बढ़ा दिया है। इतने स्वच्छ पानी में मछलियां सहित मौजूद अन्य जलीय जंतु खुलकर सांस ले पा रहे हैं।

मध्यप्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकली सोन नदी लगभग डेढ़ हजार किमी की दूरी तयकर बिहार के कोइलवर के आगे पथार के पास गंगा में मिलती है। इस लंबी यात्रा के दौरान सैकड़ों सीवरेज के साथ ही औद्योगिक अवशिष्ट को भी सोन में बहाया जाता था। इससे सोन नदी में प्रदूषण काफी बढ़ गया था। मगर लॉकडाउन के दिनों में स्थिति आह्लादित करने वाली दिखने लगी है। पानी एकदम स्वच्छ नजर आ रहा है। ऐसा सोन तटीय इलाकों के कारखानों के बंद होने और औद्योगिक अपशिष्ट नहीं बहाए जाने से हुआ है। यही हाल इंदौर की खान नदी और उज्जैन की क्षिप्रा का भी है। यानि देश-प्रदेश की जो भी छोटी-बड़ी नदियां हैं, सब निर्मल हो गई हैं। प्रकृति ने कोरोना के रूप में हमें सबक दिया है कि अगर हम प्रकृति का रक्षण नहीं करेंगे तो ऐसी महामारी फिर आ सकती है।

● **नवीन रघुवंशी**

रसायनों के भंवर में मप्र

आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एलजी पॉलिमर्स से हुई गैस लीक ने भोपाल गैस त्रासदी के जख्मों को ताजा कर दिया है। यह बात भी फिर होने लगी है कि हम हादसों से सबक नहीं लेते हैं और न ही सामान्य स्थितियों में कुछ भी सोचते हैं। कानून और नियमों की अधिकता के बावजूद हमारे देश में रसायनिक हादसे न थम रहे हैं और न ही इन्हें रोकने का कोई कारगर उपाय हो रहा है। मप्र में केवल भोपाल ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश खतरनाक रसायनों के भंवर में फंसा हुआ है। मप्र की जमीन में जिंक स्लज, जिंक स्क्रैप, सल्फेट, क्लोराइड, एल्युमिनियम, आयरन, लेड, आर्सेनिक आदि रसायन खतरनाक स्तर पर बढ़ रहे हैं। ये जानलेवा भी साबित हो रहे हैं। लेकिन इनकी रोकथाम के लिए कोई पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं।

भोपाल गैस त्रासदी से काफी पहले दवाओं के निर्माण, आयात-निर्यात और वितरण पर नियंत्रण के लिए द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में बना था। फिर फैक्ट्री कानून 1948 में आया जिसे 1987 में संशोधित किया गया। 1955 में खाने में मिलावट रोकने के लिए द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट बना। 1962 में कस्टम एक्ट बना जो खतरनाक वस्तुओं के आयात-निर्यात के लिए था। 1968 में कीटनाशकों के नियंत्रित इस्तेमाल के लिए कानून आया। 1971 में कीटनाशक नियम बना। 1974 में जल प्रदूषण से बचाव व नियंत्रण कानून बना जबकि 1981 में वायु प्रदूषण से बचाव व नियंत्रण कानून आया। इतना कुछ होने के बाद भी 1984 में बड़ी भोपाल गैस त्रासदी हुई थी।

भारत में इस औद्योगिक हादसे के बाद पर्यावरण को ध्यान में रखकर बड़ा कानून बना। इसे हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तौर पर जानते हैं। इसके बाद केंद्रीय मोटर कानून, 1988 और 1989 में हजार्ड्स वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स बना। 1994 में औद्योगिक विस्तार पर नियंत्रण के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) कानून बना। 2000 में ओजोन डिपलेटिंग सब्सटेंसेज (रेग्यूलेशन एंड कंट्रोल) रूल बना। 2001 में बैटरी (मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स) बना। 2007 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी औद्योगिक दुर्घटनाओं के लिए एक विस्तृत गाइडलाइन लेकर आई। 2016 में हजार्ड्स वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स को संशोधित किया गया। इसके अलावा भारत कीटनाशक, मर्करी और खतरनाक कचरे के चार प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का हस्ताक्षरकर्ता है। इनमें बेसल कन्वेंशन, रॉटर्डम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, मिनिमाता कन्वेंशन शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून बहुत है। भारत इसका हिस्सा है। कुछ काम हुए हैं लेकिन वह काफी नहीं है। मिसाल के तौर पर चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषक (पीओपी) के लिए स्टॉकहोम सम्मेलन है। बहुत से पीओपी रसायन चरणबद्ध तरीके से हटाए गए हैं। हालांकि प्रतिबंध के बाद भी कुछ प्रतिबंधित पीओपी रसायनों की पुष्टि यहां-वहां होती रहती है। वहीं, रॉटर्डम सम्मेलन में यह तय हुआ था कि आयात-निर्यात के लिए देश एक-दूसरे को रसायनों के जोखिम और खतरे के बारे में पूर्व सूचना देकर अनुमति लेंगे, लेकिन यह भी पूरी तरह अमल में नहीं है। ऐसे प्रमुख कानून, नियम और गाइडलाइन बनते रहे लेकिन समस्या का निदान नहीं किया गया। उल्टे भारत खतरनाक कचरे का डंपिंग यार्ड बन गया है, जिसके कारण प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष खतरनाक रसायन यहां की हवा, मिट्टी, पानी को बर्बाद कर रहे हैं।

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग के मुताबिक बीते तीन वर्ष (2015 से 2017) के दौरान रसायनिक दुर्घटनाओं के कारण घायल होने वालों की संख्या में 279 फीसदी की वृद्धि हुई है। 2015-16 में 64 रासायनिक दुर्घटनाओं में 192 लोग घायल हुए थे। वहीं, 66 लोगों की मृत्यु हुई थी, जबकि 2017-18 में महज 31 दुर्घटनाओं में 728 लोग घायल हुए हैं और 39 लोगों की जान गई है। भोपाल त्रासदी के बाद भी छोटी और बड़ी दोनों तरह की रसायनिक दुर्घटनाएं इस देश में जारी हैं। दुनिया में एक भी रसायन ऐसा नहीं है जिसे मासूम कहा जाए। इस सच को हम अच्छे से जानते हैं और इसके भुगतभोगी भी हैं। दुनिया के सबसे बड़े रासायनिक हादसों में शामिल भोपाल गैस त्रासदी को 35 वर्ष हो चुके हैं और जानलेवा मिथाइल आइसोसाइनेट (एमआईसी) गैस का प्रयोग अभी तक देश में प्रतिबंधित नहीं है।

● रजनीकांत पारे

इन रसायनों की जद में जिंदगी

मप्र और उसके आसपास के राज्यों में कई तरह के रसायन खतरनाक स्तर पर बढ़ रहे हैं। इससे मप्र खतरे में है। मप्र में जहां जिंक स्लज, जिंक स्क्रैप, सल्फेट, क्लोराइड, एल्युमिनियम, आयरन, लेड, आर्सेनिक आदि रसायन बढ़ रहे हैं। वहीं, महाराष्ट्र में साइनाइड, लेड, जिंक, सल्फेड, कलर, सीओडी, एसओ4, क्लोराइड, वालेटाइल, फैटी एसिड, क्रोमियम-6, फैडमियम, गुजरात में टोटल क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम, लेड मर्करी, जिंक, वालेटाइल, ऑर्गेनिक कंपाउंड, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, बीटेक्ट, साइनाइड, फिनाइल्स, आर्गेनिक्स, राजस्थान में इनऑर्गेनिक साल्ड, आर्गेनिक, क्रोमियम-6, छत्तीसगढ़ मे लेड, आर्सेनिक, मर्करी, पॉलीक्लोरिनेटेड, बाईफेनिल्स, साइनाइड, फ्लोराइड, पभ्एएच, टीपीएच, वोओसी, पीसीबी, उत्तरप्रदेश में हेक्सावेलेंट, क्रोमियम, क्रोमियम-6, क्रोमियम टोटल, जिंक, भारी धातु, कीटनाशक (अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एचसीएच), कीटनाशक (आइसोमर्स ऑफ एचसीएच) लेड, कैडमियम, नाइट्रेट सल्फेड, फ्लोराइड आदि रसायन तेजी से बढ़ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि इन राज्यों के बीच में मप्र के होने के कारण यहां की जमीन, पानी और हवा में इन रसायनों का स्तर तेजी से बढ़ रहा है।इस कारण कई तरह की बीमारियां फैलने की आशंका बढ़ गई है। जबकि सरकारों द्वारा इन रसायनों को रोकने के कोई प्रयास नहीं किए गए हैं।

उधारी पर खरीदी

प्रदेश में 15 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू हो गई है। करीब 5 हजार से अधिक उपार्जन केंद्रों पर गेहूं की खरीदी की जा रही है। लेकिन इन केंद्रों पर यह भी देखने में आ रहा है कि बड़ी संख्या में किसान सहकारी समितियों को गेहूं बेचने की बजाय व्यापारियों को बेच रहे हैं, वह भी उधारी पर। किसानों का कहना है कि किसानों को गेहूं बेचने से उन्हें तत्काल जरूरत की राशि मिल जाती है। भले ही बाकी राशि के लिए उन्हें 15 से 20 दिन का इंतजार करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ स्थिति यह है कि व्यापारियों को जो किसान अपना गेहूं बेच रहे हैं व्यापारी उनकी फसल का रेट स्वयं तय कर रहे हैं। जबकि समर्थन मूल्य पर गेहूं की दर 1925 रुपए प्रति क्विंटल है।

किसानों से मिली जानकारी के अनुसार व्यापारी अनाज खरीदने के बाद किसान को कुछ राशि देकर एक पर्ची पर बकाया राशि लिखकर दे रहे हैं। व्यापारियों द्वारा बकाया राशि का भुगतान 10 से 20 दिन बाद करने को कहा जा रहा है, लेकिन सैकड़ों किसानों की शिकायत यह है कि नियत तिथि गुजर जाने के बाद भी उनकी बकाया राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। किसानों को यह डर सता रहा है कि लॉकडाउन के कारण आई आर्थिक मंदी के चलते उनका पैसा व्यापारियों के पास ही अटककर न रह जाए। अधिकारियों के अनुसार नियमानुसार खरीदी के बाद तत्काल किसान को भुगतान किया जाना चाहिए। इससे बचने के लिए अनाज व्यापारी किसानों के हस्ताक्षर वाले भुगतान दर्शाने वाले प्रपत्र रोजाना समर्थन मूल्य खरीदी कार्यालय में प्रतिदिन जमा करा देते हैं। इससे किसान को भुगतान किया जाना साबित हो जाता है। नियमों को ताक पर रखकर उधारी में खरीदी जा रही उपज को लेकर किसानों को अधिक परेशानी होती है। इससे उन्हें जरूरी काम होने पर ब्याज से राशि लेकर अपना काम चलाना होता है। इस प्रक्रिया में उधारी और देरी से भुगतान के साथ यह भी समस्या है कि किसान को कई दिनों तक व्यापारी द्वारा दी गई पर्ची तो संभालकर रखनी पड़ती है। वहीं वैधानिक तौर पर इस पर्ची की कोई मान्यता भी नहीं है। उसके बाद भी व्यापारियों पर भरोसा कर किसान उन्हें लाखों रुपए कीमत का अनाज उधारी में ही बेचकर चले जाते हैं। इससे पैसों की जरूरत होने के बाद भी किसान को समय पर अपनी उपज का पैसा नहीं मिल पाता।

कृषि उपज मंडी में अनाज खरीदने वाले व्यापारियों को आवश्यक है कि वे अनाज खरीदने वाले दिन ही मंडी प्रांगण में किसानों को उनकी उपज के मूल्य का भुगतान करें। यदि ऐसा नहीं करते तो प्रतिदिन एक फीसदी ब्याज के साथ पांच दिन के अंदर भुगतान कर देना चाहिए। यदि अनाज व्यापारी पांच दिन में भी किसान को भुगतान नहीं कर रहा तो कृषि उपज मंडी एक्ट के अधिनियम की धारा 37(2) के तहत सचिव छठवें दिन ही उनका लायसेंस निलंबित कर सकता है। कृषि उपज मंडी रायसेन में व्यापारियों ने अपने हितों के मुताबिक नियम बना लिए हैं। वे कागजों की औपचारिकता पूरी कर देते हैं। इसके लिए भुगतान की रसीद पर किसानों के दस्तखत तक करा लिए जाते हैं। भुगतान के प्रपत्र मंडी समिति में प्रतिदिन जमा करा दिए जाते हैं। किसान को रुपए बाद में मिलते हैं।

किसानों का कहना है कि उनके ऊपर कई तरह के कर्ज हैं। उन्हें चुकाने के लिए व्यापारियों को उपज बेचनी पड़ रही है। किसान कहते हैं कि अपनी फसल बेचकर हम व्यापारी से जरूरत की राशि तत्काल ले लेते हैं और बाकी बाद में। खरीफ फसलों के लिए लगभग 17 लाख किसानों ने साढ़े आठ हजार करोड़ रुपए कर्ज लिया था। इन किसानों में से अधिकांश ने अपनी उपज को व्यापारियों को बेचा है। ताकि व्यापारियों से मिली रकम से वे बैंक का कर्जा चुकता कर सकें। सहकारी बैंकों के अधिकारियों का कहना है कि यदि कर्ज चुकाने की अंतिम तारीख नहीं बढ़ाई जाती है तो किसान डिफाल्टर हो जाएंगे और उन्हें आगामी सीजन के लिए कर्ज नहीं मिलेगा। ऐसा पहले भी हो चुका है और इसके कारण 12 लाख से ज्यादा किसान डिफाल्टर की श्रेणी में आ गए थे।

उधर, आरोप यह भी लग रहे हैं कि समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में भेदभाव किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि जिन जिलों के जनप्रतिनिधियों का दबदबा है वहां के किसानों का हल्की क्वालिटी (चमक विहीन) का गेहूं भी खरीदा जा रहा है। विदिशा, बैतूल, सागर और छतरपुर जिले के किसानों का हर प्रकार का गेहूं खरीदा जा रहा है और श्योपुर जिले में गेहूं के सैंपल फेल होने का विरोध करने पर किसान को डंडे खाने पड़ रहे हैं। जिन जिलों में सरकार चमक विहीन गेहूं खरीद रही है वहां किसानों को मामूली से अंतर का कम भाव मिल रहा है। समर्थन मूल्य पर एक क्विंटल गेहूं 1925 रुपए में खरीदा जा रहा है। चमक विहीन गेहूं वाले किसानों को 1920 रुपए 10 पैसे क्विंटल के हिसाब से भुगतान दिया जा रहा है। यानी अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं की तुलना में मात्र 4 रुपए 90 पैसे प्रति क्विंटल कम मिलेगा पर, सरकार चाहे तो किसानों का गेहूं खरीद सकती है।

● श्यामसिंह सिकरवार

कम भाव में गेहूं बेचने को मजबूर किसान

लॉकडाउन की वजह से किसान अपने जिले से बाहर की मंडियों में गेहूं, चना और धनिया बेचने नहीं जा पा रहा है। मजबूरी में किसानों को गेहूं समर्थन मूल्य से 250-300 रुपए प्रति क्विंटल रुपए कम और चना 700 रुपए प्रति क्विंटल कम भाव पर मंडी में बेचना पड़ रहा है। जिस गेहूं का समर्थन मूल्य 1925 रुपए प्रति क्विंटल है वह 1625 से 1750 रुपए प्रति क्विंटल तक यानी 250 से 300 रुपए प्रति क्विंटल तक और जिस चने का समर्थन मूल्य 4400 रुपए प्रति क्विंटल है वह महज 3700 से 3800 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से ही खरीदा जा रहा है। उधर, अधिकारियों का कहना है कि व्यापारी सौदा पत्रक के आधार पर खरीदी करा रहे हैं। सौदा पत्रक में किसान की सहमति के बाद ही समर्थन मूल्य से कम दर पर खरीदी हो रही है, ताकि बाद में किसी तरह से विवाद की आशंका न रहे।

टाइमबम पर खड़ा है भारत

आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एलजी पॉलिमर्स से हुई गैस लीक ने भोपाल गैस त्रासदी के जख्मों को ताजा कर दिया है। यह बात भी फिर होने लगी है कि हम हादसों से सबक नहीं लेते हैं और न ही सामान्य स्थितियों में कुछ भी सोचते हैं। कानून और नियमों की अधिकता के बावजूद हमारे देश में रसायनिक हादसे न थम रहे हैं और न ही इन्हें रोकने का कोई कारगर उपाय हो रहा है। विशाखापट्टनम में यह पहली बार नहीं है, हर वर्ष यहां फैक्ट्रियों में हादसे होते हैं और लोगों की जाने जाती हैं। हालांकि इस बार रिहायश भी चपेट में है। देश में 329 ऐसी जगहें हैं जहां रसायनिक हादसों का जोखिम बहुत ज्यादा है।

भोपाल के बाद विशाखापट्टनम जैसा बड़ा हादसा हमने नहीं देखा है। रासायनिक हादसे हर वर्ष होते हैं, हम इसे स्वीकार करके आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे हादसों से दुनिया में भारत की बड़ी जगहंसाई होती है। यह बहुत दुखद है कि कोविड-19 के दौरान जारी लॉकडाउन में आखिर किस तरह से **रसायन को हैंडल किया गया** और जांच की गई? जब हम प्लास्टिक के खतरनाक रसायन की बात करते हैं तो प्लास्टिक उद्योग इसकी उपेक्षा करता है। आज यह सबके सामने है कि इसका रसायन कितना खतरनाक है। प्लास्टिक के केमिकल का लोगों के स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा प्रकोप है लेकिन इंडस्ट्री इसे हमेशा नकारती है। कोई नहीं समझ रहा है कि प्लास्टिक में कितने खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि कानून और नियमों का पालन सख्ती से न हो रहा है।

दुनिया में एक भी रसायन ऐसा नहीं है जिसे मासूम कहा जाए। इस सच को हम अच्छे से जानते हैं और इसके भुक्तभोगी भी हैं। दुनिया के सबसे बड़े रासायनिक हादसों में शामिल भोपाल गैस त्रासदी को 35 वर्ष हो चुके हैं और जानलेवा मिथाइल आइसोसाइनेट (एमआईसी) गैस का प्रयोग अभी तक देश में प्रतिबंधित नहीं है। 2 से 3 दिसंबर, 1984 की मध्य रात्रि को बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन (यूसीसी-अब डाउ केमिकल्स का स्वामित्व) के भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड प्लांट (यूसीआईएल) में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था और कुछ ही देर में पांच हजार से ज्यादा लोगों की जीवनलीला समाप्त हो गई। एमसीआई जैसे बेहद खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल करने वाले उद्योगों को अनिवार्य लायसेंस देने वाले उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीआईपीपी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि इसके विनियमन (रेग्युलेशन) को लेकर रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग काम कर रहा है। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का इस्तेमाल कार्बारिल कीटनाशक और पॉलीयूरेथेन्स (एक प्रकार का प्लास्टिक) बनाने के लिए किया जा सकता है। यूसीसी की औद्योगिक इकाई भोपाल में एमसीआई गैस का इस्तेमाल कर कार्बारिल सेविन नाम से कीटनाशक तैयार करती थी। इस कीटनाशक को 8 अगस्त, 2018 से प्रतिबंधित किया गया है।

भोपाल गैस त्रासदी के बाद से सक्रिय कार्यकर्ता सतीनाथ सारंगी ने बताया कि मिथाइल आइसोसाइनेट को कभी प्रतिबंधित नहीं किया गया। यहां तक कि उसके उत्पादन में वसूली जाने वाली लेवी को भी घटा दिया गया। उन्होंने बताया कि यूनियन कार्बाइड का स्वामित्व हासिल करने वाली डाउ केमिकल्स अभी पॉलीयूरेथेन को भारत में ला रही है। यह जलने के बाद मिथाइल आइसोसाइनेट पैदा करती है। इतने बड़े औद्योगिक हादसे के बाद भी सरकारें जाग नहीं पाई हैं। मिथाइल आइसोसाइनेट या अन्य समकक्ष खतरनाक रसायनों को लेकर तीन से अधिक केंद्रीय मंत्रालय की अलग-अलग भूमिकाएं हैं। इनमें केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय शामिल हैं। रसायन एवं पेट्रो विभाग में निदेशक धर्मेंद्र कुमार मदान ने बताया कि खतरनाक रसायनों के रेग्युलेशन को लेकर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं हालांकि जानकार अधिकारी के कथन से इत्तेफाक नहीं रखते।

टॉक्सिक लिंक के पीयूष मोहपात्रा इस बिंदु पर कहते हैं 'रसायनों के प्रबंधन को लेकर मंत्रालयों की अलग-अलग भूमिका तर्कपूर्ण नहीं है बल्कि यह चिंताजनक है। यूरोपियन यूनियन में रसायनों के नियंत्रण के लिए पंजीकरण, आकलन, वैधता और प्रतिबंध (आरईएसीएच) जैसा विनियमन है लेकिन भारत में रसायन एक व्यवसाय है और उस पर कोई विनियमन नहीं किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन इंटरनेशनल हेल्थ रेग्युलेशन एट प्वाइंट ऑफ इंट्रीज इंडिया के मुताबिक देश में 25 राज्यों और 3 संघ शासित प्रदेशों के 301 जिलों में 1,861 प्रमुख दुर्घटना वाली खतरनाक औद्योगिक ईकाइयां हैं। साथ ही असंगठित क्षेत्र में तीन हजार से ज्यादा खतरनाक फैक्ट्री मौजूद हैं। इनका कोई विनियमन नहीं है।

● अक्स ब्यूरो

उद्योगों को खुश करने पर जोर

इन चिंताओं से हटकर सुस्त अर्थव्यवस्था में भी भारतीय रसायन उद्योग काफी उत्साहित है। केंद्र सरकार मेक इन इंडिया के जाम पहिए में रसायन उद्योग से ही ग्रीस डलवाना चाहती है। दरअसल, भारत दुनिया में रसायन उत्पादन के मामले में छठवे स्थान पर और कृषि रसायनों के मामले में चौथे स्थान पर है। 2017-18 के दौरान देश में कुल 4.90 करोड़ टन रसायन और पेट्रोरसायन का उत्पादन किया गया है। एसोचैम इंडिया की रिपोर्ट रीसर्जेंट 2015 के मुताबिक भारत में कुल 70 हजार रसायन बनाने वाली छोटी-बड़ी औद्योगिक ईकाइयां हैं और 70 हजार से भी ज्यादा रसायन उत्पाद यहां बनाए जा रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा 69 फीसदी क्षारीय रसायन निर्मित किए जा रहे हैं जबकि पेट्रो रसायनों में 59 फीसदी बहुलक (पॉलीमर) का उत्पादन होता है।

वर्चस्व की जंग

देश में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या वाले मध्यप्रदेश में बाघों के बीच वर्चस्व की जंग जानलेवा साबित हो रही है। यह जंग किस कदर खतरनाक है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रदेश में 22 दिनों के अंदर 8 बाघों की मौत हो चुकी है। जानकारों का कहना है कि प्रदेश में बाघों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है और वनक्षेत्र सीमित है। इसलिए बाघों में वर्चस्व के लिए लड़ाई के मामले बढ़ रहे हैं।

गौरतलब है कि अखिल भारतीय बाघ आंकलन में मध्यप्रदेश 526 बाघों के साथ देश में पहले स्थान पर है। यही नहीं, तीन टाइगर रिजर्व पेंच, कान्हा और सतपुड़ा देश में प्रबंधकीय दक्षता में **प्रथम तीन स्थान पर** हैं। मप्र को स्टेट टाइगर का दर्जा मिलने के बाद भी बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। खासकर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 22 अप्रैल को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की खितौली रेंज में 10 साल के बाघ का शव मिला है, तो सतना की व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर चिड़ियाघर में बीमारी से 6 साल की बाघिन की मौत हो गई है। इन्हें मिलाकर प्रदेश में पिछले 22 दिनों में 8 बाघों की मौत हो चुकी है, जो देश में सबसे ज्यादा है।

प्रदेश में बाघों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। इसने वन अफसरों को चिंता में डाल दिया है, लेकिन वे इसका कारण नहीं तलाश पा रहे हैं। इन घटनाओं पर सरकार की भी अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है इसलिए मैदानी स्तर पर बाघों की सुरक्षा प्रबंधों में ढिलाई देखी जा रही है। घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन सख्ती नहीं दिखाई दे रही। बांधवगढ़ में 10 साल के बाघ की मौत का कारण दो बाघों के बीच आपसी लड़ाई बताया जा रहा है। वन अफसरों का अनुमान है कि रहवास क्षेत्र को लेकर दोनों में लड़ाई हुई होगी। जिसमें 10 साल के बाघ की मौत हुई है।

बांधवगढ़ में टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 1536 वर्ग किमी है, जिसमें बाघों के लिए सघन कोर जंगल महज 694 वर्ग किमी बताया जाता है। इसमें बाकी का हिस्सा बफर जोन का है जिसके कारण टैरोटिरि फाइट की घटनाएं बढ़ी हैं। इसके कारण दस वर्षों में 50 बाघों की मौत की पुष्टि भी हुई है। टाइगर स्टेट का दर्जा मिलने के बाद मध्यप्रदेश को यह तमगा बरकरार रखना चुनौतीपूर्ण बन गया है। 2014 के बाद देश में बाघों की सर्वाधिक 150 मौत मप्र में ही हुई हैं। इसमें 42 बाघों का शिकार हुआ। ऐसे में सरकार को जल्द ही टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स स्थापित करना होगा। पर्यावरणविदों का कहना है कि यहां के जंगलों पर विकास के नाम पर गतिविधियां बढ़ाने का दबाव है। इसे रोकना होगा। टाइगर रिजर्व में बढ़ते जा रहे मानवीय दखल को कम करने के लिए खास रणनीति बनानी होगी। बाघों के रहवास के विकास के लिए भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

उधर, मुकुंदपुर जू में बाघिन की मौत का कारण बीमारी बताया जा रहा है। चार साल पहले औरंगाबाद से लाई गई बाघिन करीब पांच दिन से बीमार थी। उसे रह-रहकर तेज बुखार आ रहा था। जू के डॉक्टर बीमारी का ठीक से अंदाज नहीं लगा पाए हैं। हालांकि जबलपुर वेटनरी कॉलेज के डॉक्टर बाघिन का इलाज कर रहे थे। वन अफसरों का कहना है कि बाघिन का पोस्टमार्टम कर सैंपल लिए गए हैं। उनके परीक्षण से ही बीमारी का सही पता चलेगा। देश में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या वाले मध्यप्रदेश में शिकारियों की भी नजरें हैं।

उधर, सीधी जिले के संजय टाइगर रिजर्व अंतर्गत कोर एवं बफर एरिया में शिकारियों द्वारा वन्य प्राणियों के शिकार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जबकि सरकार द्वारा वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए करोड़ों रुपए का बजट पानी की तरह बहाया जाता है। साथ ही विभाग द्वारा वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए सैकड़ों कर्मचारियों की तैनाती भी की गई है। इतना ही नहीं वन्य प्राणियों को सुरक्षा प्रदान करने में चूक न हो इसके लिए लाव लश्कर सहित अन्य जरूरी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती हैं। बावजूद इसके वन्य प्राणियों के शिकार का सिलसिला बदस्तूर जारी है।

ऐसा ही एक मामला संजय टाइगर रिजर्व कोर एरिया अंतर्गत वन परिक्षेत्र पोंड़ी के आमगांव बीट प्रकाश में आया है। जहां ग्रामीण अंचल के विश्वस्त सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक शिकारियों द्वारा जानवरों के शिकार की नियत से विगत दिनों बिजली का खुला तार का जाल जंगल में फैलाकर उसमें हाई वोल्टेज करंट दौड़ाया गया था। बताया गया कि शिकारियों द्वारा बिछाए गए इस जाल में फंसकर एक सियार की मौत हो गई थी। जिसकी सूचना विभागीय कर्मचारियों के द्वारा संजय टाइगर रिजर्व के आला अधिकारियों को दी गई थी।

● धर्मेन्द्र सिंह कथूरिया

लॉकडाउन में शिकारी भी हुए सक्रिय

कोरोना वायरस के कारण इस समय सबका ध्यान इस वायरस के संक्रमण को रोकने पर है। इसका फायदा उठाते हुए वन्यप्राणी तस्कर और शिकारी जंगलों में डेरा डाल चुके हैं। वन विभाग के सूत्रों का कहना है कि इसकी खबर मिलते ही अमला फिर से जंगल में उतर गया है। आए दिन बाघ और तेंदुए के शिकार की खबरें आ रही हैं। विगत दिनों एक बाघ का आधा कटा हुआ सिर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। वायरल तस्वीर के साथ लिखे मैसेज में यह शिकार पन्ना जिले में इटवा में महुलिया के जंगल में होना बताया जा रहा है। इसमें रैपुरा वन विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदार बताया जा रहा है और इस मामले को दबाने के प्रयास का भी आरोप लगाया गया है। हालांकि पन्ना जिले का वन विभाग इससे इनकार कर रहा है। उनका कहना है कि मैसेज में जो दावा किया गया है, वो क्षेत्र पन्ना जिले में ही नहीं है। हालांकि बाद में मामला दब गया। उधर, प्रदेश के अन्य वन्य क्षेत्रों से भी तस्करों की सक्रियता की खबरें आ रही हैं।

मनरेगा पर भार

कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन में मजदूरों की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। एक तो घर से बाहर दूसरे शहरों में फंसे, तो परिवार के पास पहुंचने की चिंता और परेशानी। दूसरे जैसे-तैसे घरों को लौट भी गए तो अब काम न मिलने की चिंता सता रही है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में करीब 68 लाख जॉब कार्डधारी परिवार हैं। जिसमें से 30 अप्रैल तक 10 लाख परिवारों ने ही काम मांगा था। हालांकि पंचायत विभाग ने इन मजदूरों को उनके घर के पास ही काम उपलब्ध करा दिया था।

दरअसल, कोरोना के कारण हो रही मजदूरों के घर वापसी से मनरेगा में काम की डिमांड बढ़ गई है। प्रदेश में हर दिन करीब 60 से 70 हजार मजदूर पंचायतों से काम मांग रहे हैं। काम मांगने वालों की संख्या 10 दिन के अंदर ही बढ़ी है। वहीं मजदूरों के काम की डिमांड के चलते निर्माण कार्य और विकास की गति बढ़ा दी गई है। क्योंकि इन मजदूरों को काम देने की जिम्मेदारी पंचायत एवं ग्राम सहायकों को दी गई है। 30 अप्रैल के बाद से काम की डिमांड एकदम बढ़ने लगी है। पिछले 10 दिन के अंदर करीब सात लाख मजदूरों ने काम की डिमांड की है। बताया गया है कि करीब 15 लाख मजदूरों को काम दे भी दिया गया है, और इनमें से 14 लाख मजदूरों ने काम करना भी शुरू कर दिया है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का मानना है कि अब गांव में काम की मांग पड़ेगी। पंचायतों में बड़े पैमाने पर रोजगार का लक्ष्य रखा है। गांव में सभी विभागों से जुड़े अधोसंरचना के काम तैयार किए जाएंगे। इससे जहां गांव का विकास होगा वही जॉब कार्डधारी परिवारों को काम भी मिलेगा। इसके अलावा पंचायतें खुद मजदूरों को काम देने के लिए गांव के विकास कार्यों को प्रारंभ करेंगे। इसके साथ ही केंद्र और राज्य के हितग्राही मूलक योजनाएं जैसे शौचालय, सड़क, नाली निर्माण, पुल-पुलिया प्रधानमंत्री आवास, सामुदायिक भवन, पंचायत भवन सहित अन्य कार्य भी प्रारंभ किए जाएंगे, जिससे मजदूरों को पर्याप्त काम मिल सके। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायतों के विकास और मजदूरी के लिए 20 हजार करोड़ का बजट रखा है। अधिकारियों का मानना है कि करीब 30 से 40 लाख मजदूर काम की डिमांड करेंगे। इसके लिए पंचायत स्तर पर विकास कार्यों के साथ मजदूरों को काम उपलब्ध कराने की रूपरेखा तैयार की है।

बाहरी राज्यों से मध्यप्रदेश में वापस लौटे साढ़े ग्यारह लाख से ज्यादा मेनपॉवर अब सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। अभी तक इन मजदूरों को काम देने को लेकर सरकार मनरेगा के अलावा दूसरे विकल्पों पर विचार नहीं कर पाई है, लेकिन यदि इस मेनपॉवर को मध्यप्रदेश सरकार रोक लेती है तो यह प्रदेश के विकास में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। दूसरी ओर यदि इस मेनपॉवर को काम नहीं मिल पाता तो यह उतनी ही ज्यादा समस्या भी साबित होंगे।

दरअसल, कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन के कारण पिछले कई दिनों से दूसरे राज्यों से मध्यप्रदेश के प्रवासी मजदूरों के लौटने का क्रम जारी है। अभी तक पहले दौर में करीब 9.88 लाख और सरकारी प्रयासों के तहत ट्रेन और बस से 1.90 लाख मजदूर मध्यप्रदेश में आ चुके हैं। इस तरह करीब 11.78 लाख मजदूर 10 मई तक की स्थिति में मध्यप्रदेश में आ चुके हैं। अब इतनी बड़ी संख्या में लौटे मजदूर मध्यप्रदेश के लिए बड़ी चुनौती हैं। हालांकि इसके लिए सरकार लोक निर्माण, जल संसाधन, पीएचई सहित अन्य विभागों में जल परियोजना और निर्माण काम शुरू कर रही है, लेकिन अभी इन मजदूरों को पंजीबद्ध करके काम नहीं दिया जा सका है। सरकार फिलहाल इन लौट रहे मजदूरों को कैटेग्राइज नहीं कर पाई है। कौन से मजदूर किस स्किल्स के हैं और किस प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों के लिए मुफीद रहेंगे, फिलहाल इसका डाटा तैयार नहीं किया गया है। लेकिन, सरकार ने अब इस डाटा फीडिंग की तैयारी शुरू की है। इसमें मजदूरों को उनके काम की श्रेणी के हिसाब से पंजीयत किया जाएगा। ताकि, बाद में उन्हें उनके हिसाब से रोजगार दिया जा सके।

● **सिद्धार्थ पांडे**

फिर पलायन रोकना बड़ी चुनौती

मध्यप्रदेश में आने के लिए 10 मई की स्थिति में 3.90 लाख मजदूरों ने पंजीयन कराया है, जिसमें से 1.90 लाख मजदूर आ चुके हैं। लेकिन, अभी दो लाख मजदूर और आने है। इससे प्रदेश में 13.78 लाख मजदूरों की मेनपॉवर तैयार हो जाएगी, जिसे काम मुहैया कराने की चुनौती होगी। फिलहाल कोरोना व लॉकडाउन के कारण ये मजदूर मध्यप्रदेश में लौट आए हैं, लेकिन इन्हें रोककर रखना बड़ी चुनौती है। पूर्व में रोजगार नहीं मिलने के कारण इन मजदूरों ने मध्यप्रदेश छोड़ा था। अब पिछले कुछ सालों में प्रदेश का काफी परिदृश्य बदला है। ऐसे में इनके लिए नए रोजगार के अवसर हो सकते हैं, लेकिन कोरोना संकट के कारण चरमराई अर्थव्यवस्था के बीच इनको रोजगार उपलब्ध कराकर वापस पलायन रोकने की चुनौती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि इन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाए, ताकि वापस पलायन न करें। यदि सरकार इन 13.78 लाख मजदूरों के लिए रोजगार का इंतजाम कर पाती है, तो यह सियासी तौर पर भी सरकार के लिए फायदेमंद रहेगा। वजह ये कि बड़ी संख्या में होने के कारण ये वर्ग वोट की दृष्टि से फायदेमंद रह सकता है। यह भाजपा का कमिटेट वोट बैंक बन सकता है। इनमें से अधिकतर मजदूर विंध्य, बुंदेलखंड, मालवा-निमाड़ और चंबल के पिछड़े इलाकों के हैं। इन इलाकों के वोट के गणित से भाजपा को फायदा मिल सकता है।

भारत में इस वक्त अभूतपूर्व आर्थिक मंदी छाई है, जिसे कुछ लोग आर्थिक आपात भी करार दे रहे हैं। मुख्य आर्थिक क्षेत्रों में विकास पूरी तरह सिकुड़ गया है, साथ में घरेलू और ग्रामीण खपत भी कम हो गई है। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी लगभग न के बराबर ही आ रहा है। इसका ग्रामीण गरीबों, शहरी अनौपचारिक क्षेत्र और मध्यम वर्ग पर बहुत बुरा असर पड़ा है। आलम यह है कि राज्यों के पास आय के लिए शराब और डीजल-पेट्रोल ही साधन बचे हैं।

● राजेंद्र आगाल

अपनी आर्थिक नीति की खामियों के कारण देश पहले से आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा था कि कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था की पूरी कमर तोड़ दी। किसी एक क्षेत्र का नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था का लकडाउन (भाग्य खराब) हो गया है। 30,42,230 करोड़ रुपए के बजट वाली केंद्र सरकार का खजाना खाली है। वहीं राज्यों की स्थिति बदहाल है। ऐसे में लॉकडाउन ने देश और प्रदेशों को ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उन्हें अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए **शराब और डीजल-पेट्रोल का सहारा लेना पड़ रहा है**। राज्यों की स्थिति इतनी खराब है कि वे केंद्र से आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे हैं और केंद्र की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वह आंकड़ों की बाजीगरी करने में जुटी हुई है। आलम यह है कि कोरोना के इस संक्रमणकाल में भी शराब की दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है। शराब दुकानों पर उमड़ती भीड़ को देखकर कई राज्यों

सरकार ने मदद नहीं की, बल्कि लोन मेला लगाया

कोरोना समय में लगातार लॉकडाउन से पैदा हुए संकटों का सामना करने के नाम पर एक बार फिर प्रधानमंत्री का भाषण हुआ। भाषण में कुछ नहीं था। बस एक बात थी कि सरकार 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देगी। अगले दिन सभी अखबारों की हेडलाइन 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज पर केंद्रित थी। इससे एक इशारा साफ तौर पर निकलता है कि प्रधानमंत्री के भाषण का मकसद केवल इतना था कि 20 लाख करोड़ रुपए की सरकारी मदद का ऐलान वे अपने मुंह से करें। अब एक-एक करके इसका ब्यौरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दे रही हैं और इसी के साथ इसकी हकीकत भी खुलती जा रही है। शुरुआती तीन दिन की घोषणाओं ने ही बता दिया है कि दरअसल इस 20 लाख करोड़ रुपए की सच्चाई क्या है? वाकई 20 लाख करोड़ रुपए बहुत अधिक होते हैं। एक आम इंसान जो सालभर में लाख रुपए की बचत नहीं कर पाता। वह इतनी बड़ी राशि सुनकर अंदाजा ही नहीं लगा पाता कि आखिरकार यह होता कितना है। इसलिए 20 लाख करोड़ रुपए को थोड़ा सरल अंदाज में समझते हैं ताकि बात समझी और समझायी जा सके। यह इतनी बड़ी राशि है कि अगर 130 करोड़ लोगों में बांटी जाए तो सबके जेब में तकरीबन 15 हजार रुपए आ जाएंगे। अगर सुपर अमीरों को छोड़कर बांटा जाए तो सबकी जेब में 20 हजार रुपए आ सकते हैं। यानी 5 लोगों के परिवार को तकरीबन 1 लाख रुपए मिल सकता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 20 लाख करोड़ रुपए का मतलब क्या है? होना तो यह चाहिए था कि 20 लाख करोड़ रुपए का बंटवारा कैसे होगा? सरकार इसके बारे में एक ही बार में बता दे लेकिन यह नहीं हुआ। पहले प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि इस 20 लाख करोड़ रुपए में रिजर्व बैंक द्वारा दी गई मदद और कोरोना के लिए घोषित किया गया पहला आर्थिक पैकेज भी शामिल है। इस वाक्य को थोड़ा सरल तरीके से समझा जाए तो बात यह है कि इससे पहले करीबन 9.74 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज जो पहले ही जारी किया गया है, वह भी इस 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज में शामिल है। इस 9.74 लाख करोड़ रुपए में पहले आर्थिक पैकज में ऐलान की गई 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपए की राशि शामिल है, साथ में आरबीआई द्वारा बैंकों को दिया गया तकरीबन 6 लाख करोड़ शामिल है।

की आंखों में चमक आई है और उन्होंने शराब पर कोरोना टैक्स जड़ दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी कंगाली में पहुंच गई है कि केंद्र सरकार के पास राज्यों को देने के लिए बजट भी नहीं है।

नीति साफ, नीयत खराब

अगर केंद्र सरकार की नीति और उसके क्रियान्वयन का आकलन करें तो यह साफ परिलक्षित होता है कि सरकार की नीति तो साफ है लेकिन नीयत खराब है। दरअसल, एक तरफ सरकार गांव, गरीब, मजदूर और जरूरतमंदों के लिए बनाई गई योजनाओं के फंड में कटौती करती रही है। वहीं दूसरी तरफ सांसदों और विधायकों को खुले हाथ से फंड, वेतन और सुविधाएं बांटती रहती है। कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद देश के सांसदों के वेतन में 30 फीसदी कटौती का प्रावधान किया गया है। वहीं **सांसद निधि भी दो साल के लिए सस्पेंड** कर दी गई है। लेकिन इससे न तो आर्थिक बदहाली दूर हो सकती है और न ही अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है। अगर सरकार शुरू से ही माननीयों पर किए जा रहे खर्च को सीमित रखती तो आज उक्त राशि से इस महामारी के कारण आई आर्थिक तंगी से निपटा जा सकता था। लेकिन सरकार ने कभी भी माननीयों की **सहूलियतों पर लगाम नहीं** लगाई है।

माननीयों पर 100 अरब खर्च

कोरोना संक्रमण सरकार के लिए एक सबक बनकर सामने आया है। सरकार को अपने खर्चे कम करने होंगे तथा माननीयों पर हर साल जो करीब 100 अरब रुपए खर्च किए जाते हैं, उसे भी संतुलित करना होगा। देश में कुल 4120 एमएलए और 462 एमएलसी हैं यानि कुल 4582 विधायक। एक विधायक पर वेतन भत्ता मिलाकर हर महीने 2 लाख का खर्चा होता है यानि 4582 विधायकों पर हर महीने 91 करोड़ 64 लाख का खर्चा और हर साल 1100 करोड़ का खर्चा। वहीं भारत में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को मिलाकर कुल 776 सांसद हैं। सांसदों को वेतन भत्ता मिलाकर हर महीने 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस हिसाब से 776 सांसदों के वेतन पर हर महीने 38 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च होते हैं और हर साल देश के 465 करोड़ 60 लाख रुपया खर्च होता है। ये तो सांसदों और विधायकों पर होने वाला सिर्फ मूल वेतन का खर्चा है। इनके आवास, रहने, खाने, यात्राओ, इलाज, विदेशी सैर सपाटा का खर्चा भी लगभग इतना ही है। दूसरे खर्चों को भी मूल वेतन के बराबर मानते हुए यानि 15 अरब मानते हुए यह पूरा खर्चा 30 अरब तक पहुंच जाता है।

अब गौर कीजिए विधायकों और सांसदों की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों के वेतन पर। एक विधायक की सुरक्षा में 7 पुलिसकर्मी तैनात होते हैं। एक पुलिसकर्मी का वेतन 25 हजार रुपए महीना। तो 7 पुलिसकर्मियों के वेतन पर हर महीने खर्चा 1 लाख 75 हजार रुपए। इस हिसाब से 4582 विधायकों की सुरक्षा का सालाना खर्चा मैसेज में 9 अरब 62 करोड़ 22 लाख है। वहीं सांसदों की सुरक्षा पर हर साल 164 करोड़ रुपए खर्चा होते हैं। जिन नेताओं को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली है यानि मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए लगभग 16000 जवान अलग से तैनात हैं। इस सुरक्षा पर हर साल करीब 776 करोड़ रुपए खर्चा होते हैं। हर साल नेताओं के वेतन सुरक्षा और भत्तों पर 50 अरब खर्च होते हैं लेकिन इन खर्चों में राज्यपाल, पूर्व नेताओं की पेंशन, पार्टी के नेता, पार्टी अध्यक्ष और उनकी सुरक्षा का खर्चा शामिल नहीं है। अगर उस खर्चा को भी इसमें जोड़ दिया जाए कुल खर्चा लगभग 100 अरब रुपया हो जाएगा। लेकिन देश में आजादी के बाद से लेकर अभी तक किसी भी सरकार ने माननीयों की सुविधाओं में कटौती करने की कोशिश नहीं की। देश में एक तबका जहां एक-एक रोटी के लिए तरस रहा है वहीं दूसरी तरफ माननीयों के वेतनभत्तों और सुख-सुविधाओं पर हर साल अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इससे देश में खुशहाली नहीं आने वाली।

कैसे होती है राज्यों की कमाई

देश पिछले दो साल से लगातार आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। इस कारण केंद्र सरकार राज्यों को उनके हिस्से का पर्याप्त फंड नहीं दे रही है। इससे राज्यों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। ऐसे दौर में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण किए गए लॉकडाउन ने राज्यों का भी लकडाउन कर दिया है। राज्यों की कमाई के भी स्रोत बंद हो गए हैं। असल में राज्यों की कमाई के मुख्य स्रोत हैं- राज्य जीएसटी, भू-राजस्व, पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले वैट या **सेल्स टैक्स,** शराब पर लगने वाला एक्साइज और गाड़ियों आदि पर लगने वाले कई अन्य टैक्स। शराब पर लगने वाला एक्साइज टैक्स यानि आबकारी शुल्क राज्यों के राजस्व में एक बड़ा योगदान करता है। शराब और पेट्रोल-डीजल को जीएसटी से बाहर रखा गया है।

इसलिए राज्य इन पर भारी टैक्स लगाकर अपना राजस्व बढ़ाते हैं। हाल में राजस्थान सरकार ने शराब पर एक्साइज टैक्स 10 फीसदी बढ़ा दिया। राज्य में अब देश में निर्मित विदेशी शराब पर टैक्स 35 से 45 फीसदी तक हो गया है। इसी तरह बीयर पर भी टैक्स बढ़ाकर 45 फीसदी कर दिया गया है। यानी 100 रुपये की बीयर में 45 रुपया तो ग्राहक सरकार को टैक्स ही दे देता है। इसके अलावा राज्यों को केंद्रीय जीएसटी से हिस्सा मिलता है। लेकिन केंद्र सरकार कई महीनों से राज्यों को जीएसटी का हिस्सा नहीं दे पा रही, जिसको लेकर राज्यों ने कई बार शिकायत भी की है। राज्यों के राजस्व का बड़ा हिस्सा शराब और पेट्रोल-डीजल की बिक्री से आता है। लॉकडाउन की वजह से इन दोनों की बिक्री ठप थी, इस वजह से राज्यों की वित्तीय हालत खराब हो गई थी। हालत यह हो गई थी कि कई राज्यों को 1.5 से 2 फीसदी ज्यादा ब्याज पर कर्ज लेना पड़ा था। इससे राज्यों पर आर्थिक बोझ और बढ़ा है। वहीं केंद्र सरकार अभी राज्यों को फंड देने की स्थिति में नहीं है।

हर दिन 700 करोड़ का नुकसान

देश में शराब का आर्थिक महत्व कितना है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लॉकडाउन के दौरान शराब नहीं बिकने से राज्यों को हर दिन 700 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो रहा था। जब शराब बिकती है तो सरकारें हर साल 24 प्रतिशत तक की कमाई कर लेती हैं। लेकिन, सवाल यह है कि जब 40 दिन से देश में टोटल लॉकडाउन था और 17 मई तक भी लॉकडाउन ही रहेगा, तो फिर शराब की दुकानें खोलने की क्या जल्दबाजी थी? जवाब है- राज्यों की अर्थव्यवस्था। दरअसल, शराब की बिक्री से राज्यों को सालाना 24 प्रतिशत तक की कमाई होती है। पिछले साल ही शराब बेचने से राज्य सरकारों को 2.5 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था। लेकिन, लॉकडाउन की वजह से देशभर में शराब बंदी भी लग गई थी। शराब पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी से सबसे कम सिर्फ 1 प्रतिशत कमाई मिजोरम और नागालैंड को होती है। जबकि, सबसे ज्यादा 24 प्रतिशत कमाई उत्तर प्रदेश और ओडिशा को होती है।

राज्यों को कितनी होती है शराब की बिक्री से कमाई

ज्यादातर राज्यों के कुल राजस्व का 15 से 30 फीसदी हिस्सा शराब से आता है। शराब की बिक्री से उप्र के कुल टैक्स राजस्व का करीब 20 फीसदी हिस्सा मिलता है। उत्तराखंड में भी शराब से मिलने वाला आबकारी शुल्क कुल राजस्व का करीब 20 फीसदी होता है। सभी राज्यों की बात की जाए तो पिछले वित्त वर्ष में उन्होंने कुल मिलाकर करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई यानि टैक्स राजस्व शराब बिक्री से हासिल की थी। शराब की बिक्री से वित्त वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश ने 26,000 करोड़, तेलंगाना ने 21,500 करोड़, कर्नाटक ने 20,948 करोड़, पश्चिम बंगाल ने 11,874 करोड़ रुपए, राजस्थान ने 7,800 करोड़ रुपए और पंजाब ने 5,600 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया था। दिल्ली ने इस दौरान करीब 5,500 करोड़ रुपए का आबकारी शुल्क हासिल किया था। राज्य के कुल राजस्व का यह करीब 14 फीसदी है।

बिहार और गुजरात दो ऐसे राज्य हैं, जहां पूरी तरह से शराबबंदी है। 1960 में जब महाराष्ट्र से अलग होकर गुजरात नया राज्य बना, तभी से वहां शराबबंदी लागू है। जबकि, **बिहार** में अप्रैल 2016 से शराबबंदी है। इसलिए, इन दोनों राज्यों को एक्साइज ड्यूटी से कोई कमाई नहीं होती।

शराब की बिक्री जरूरी क्यों?

25 मार्च को जब लॉकडाउन की घोषणा की गई थी तो उस समय देशभर में 605 कोरोना संक्रमित थे, जिनमें से 10 की मौत हुई थी। कोरोना का संक्रमण न फैले इसके लिए शराबबंदी भी की गई थी। लेकिन 4 मई को सरकार ने फिर से शराब की दुकानें खोलने की घोषणा कर दी। जबकि उस समय कोरोना का संक्रमण खतरनाक रूप ले चुका था। देशभर में 42,112 लोग संक्रमित थे और 1386 की मौत हो गई थी। इन आकड़ों के बीच सरकार के शराब के फैसले ने सबको हैरान कर दिया है। इस फैसले के बाद जब 4 मई को शराब की दुकानें खुली तो उन पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दिल्ली और मुंबई सहित वे इलाके जहां खतरा अभी भी बरकरार है, वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए हजारों लोगों की भीड़ दुकानों के बाहर नजर आई। इसके अगले दिन दिल्ली सहित कुछ राज्यों ने शराब पर कोरोना टैक्स भी लगा दिया, लेकिन इसके बाद भी ठेकों पर लोगों की भीड़ कम नहीं हुई है। इस हालत में रेड और ऑरेंज जोन वाले इलाकों में संक्रमण फैलने का खतरा पहले से कई गुना बढ़ गया है। लेकिन, इसके बावजूद किसी भी राज्य सरकार ने शराब की बिक्री का अपना फैसला वापस नहीं लिया है।

खतरे के बावजूद कमाई पर ध्यान

कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने के खतरे के बावजूद राज्यों द्वारा शराब की बिक्री पर रोक न लगाने का कारण इससे मिलने वाले राजस्व को माना जा रहा है। शराब से मिलने वाले टैक्स को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से बाहर रखा गया है जिसका लाभ सीधे तौर पर राज्य सरकारों को मिलता है। राज्यों को शराब के निर्माण और बिक्री पर लगाए गए उत्पाद शुल्क से सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। इसके अलावा विदेश से आने वाली शराब पर परिवहन शुल्क, लेबल शुल्क और ब्रांड पंजीकरण शुल्क भी लगाए जाते हैं। कुछ राज्य शराब पर अलग से वैट भी वसूलते हैं। उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्य बीते साल से आवारा पशुओं के रखरखाव के लिए भी शराब पर विशेष टैक्स लगाकर फंड जुटा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बीते साल जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश राज्यों को टैक्स से आने वाले अपने कुल राजस्व का लगभग 10-15 फीसदी हिस्सा अकेले शराब और एल्कोहल से बनने वाले अन्य उत्पादों से मिलता है। कुछ राज्य तो ऐसे भी हैं जिनके राजस्व का 30 से 50 फीसदी तक का हिस्सा शराब से मिलने वाले उत्पाद शुल्क से आता है। यही वजह है कि जब शराब को जीएसटी में शामिल किया जा रहा था तो ज्यादातर राज्य सरकारें केंद्र के इस फैसले के खिलाफ थी। उन्होंने जीएसटी का समर्थन तब किया जब केंद्र ने शराब को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का निर्णय लिया। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान दिल्ली और पुदुचेरी सहित देश के 29

रुक गया कर्मचारियों का 1500 करोड़ का ऐरियर्स

मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का एरियर्स तीन किश्तों में देने का निर्णय किया था। इसके तहत पहली और दूसरी किश्त का भुगतान किया जा चुका है। तीसरी और अंतिम किश्त मई में दी जानी थी लेकिन कोरोना संकट के कारण आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते यह किश्त नहीं दी गई है। वित्त विभाग ने यह निर्णय लिया है कि एरियर की तीसरी किश्त फिलहाल स्थगित रखी जाएगी, लेकिन ऐसे कर्मचारियों को एरियर की किश्त का भुगतान कर दिया जाएगा जो सेवानिवृत्त होंगे या फिर उन्होंने सेवा से इस्तीफा दे दिया हो या फिर संबंधित कर्मचारी की मृत्यु हो गई हो तो परिजनों को एरियर की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। दरअसल, एरियर्स के भुगतान में सरकार को 15 सौ करोड़ रुपए चाहिए। जानकारी के अनुसार इतनी बड़ी राशि फिलहाल सरकार देने की स्थिति में नहीं है। ऐरियर्स की किश्त न मिलने से कर्मचारियों को 15 हजार से 50 हजार रुपए तक का आर्थिक नुकसान होगा। प्रदेश में राज्य सरकार के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान के अंतर्गत पुनरीक्षित बढ़े हुए वेतन का लाभ एक जनवरी 2016 से दिया गया है और इसका नगद भुगतान एक जुलाई 2017 से किया गया। जनवरी 2016 से जून 2017 तक कुल 18 माह का ऐरियर्स कर्मचारियों को तीन समान वार्षिक किश्तों में जो मई 2018, मई 2019 एवं मई 2020 में देने का निर्णय लिया गया। प्रदेश के कर्मचारियों को मई 2018 की प्रथम किश्त एवं मई 2019 की दूसरी किश्त प्राप्त हो चुकी है। मई 2020 में ऐरियर्स की तीसरी किश्त मिलनी है। राज्य शासन ने तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ऐरियर्स का 50 प्रतिशत नकद एवं 50 प्रतिशत सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करने और प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों का 100 प्रतिशत ऐरियर्स की राशि सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करने का निर्णय लिया था।

राज्यों ने शराब पर उत्पाद शुल्क के जरिए संयुक्त रूप से एक लाख 50 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। 2019-20 के दौरान इसमें 16 फीसदी की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा एक लाख 75 हजार करोड़ रुपए को पार कर गया। वित्त वर्ष 2018-19 में सभी राज्यों ने संयुक्त रूप से हर महीने औसतन करीब 13 हजार करोड़ रुपए शराब से कमाए। जबकि 2019-20 में कमाई का यह आंकड़ा 15,000 करोड़ रुपए प्रति माह था। अधिकारियों की मानें तो वर्तमान वित्त वर्ष में राज्य सरकारों को शराब से और भी अधिक राजस्व मिलने की उम्मीद थी।

राज्यों ने लगाया कोरोना टैक्स

लॉकडाउन के बावजूद 4 मई को जब कई राज्यों में शराब की दुकानें खुलीं तो लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। इस सैलाब को देखकर सरकारों की आंखें चमक उठी और उन्होंने शराब पर कोरोना टैक्स लगा दिया। यहां तक कि जो आंध्र प्रदेश सरकार शराब बंदी की ओर कदम बढ़ा रही थी, उसने भी 25 फीसदी का 'मदिरा निषेध कर' लगाकर शराब की बिक्री शुरू कर दी है। तमिलनाडु सरकार ने दूसरी बार शराब के रेट में बढ़ोत्तरी की है। उसने 180 मिली लीटर शराब पर 20 रुपए बढ़ाए हैं। 750 मिलीलीटर शराब की बोतल पर 40 से 80 रुपए कीमत बढ़ जाएगी। इस वृद्धि से तमिलनाडु को 2500 करोड़ अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। लॉकडाउन में जबसे दुकानें बंद थी इससे तमिलनाडु सरकार को 3600 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो चुका है। आंध्र प्रदेश सरकार ने शराब की कीमतों में 50 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी। उसने एक दिन पहले ही कीमत 25 प्रतिशत बढ़ाई थी। शराब की कीमत 50 फीसदी बढ़ाने के बाद आंध्र प्रदेश को सालाना 9000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। इधर, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने शराब पर कोरोना स्पेशल टैक्स लगाते हुए 70 फीसदी की बढ़ोतरी की है। अप्रैल में जहां आमतौर पर दिल्ली में 3500 करोड़ का राजस्व आता था, वहीं अप्रैल माह का राजस्व घटकर 300 करोड़ पर आ गया था। अब दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक दुकानें खोलने की इजाजत दी है।

उधर, कोरोना संकट के बीच राजस्व वसूली में उत्तर प्रदेश सरकार भी पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इंपोर्टेट शराब पर शुल्क बढ़ा दिया है। 100-180 मिलीलीटर पर 100 रुपए और 180 से 500 मिली तक 200 रुपए और 500 से ज्यादा पर 400 रुपए का इजाफा किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए पेट्रोल-डीजल पर वैट बढ़ा दिया है। इस प्रकार वहां एक रुपए डीजल पर और दो रुपए पेट्रोल पर बढ़ गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में शराब पर राज्य सरकार ने कोरोना टैक्स लगा दिया है। राज्य में शराब तकरीबन 10 फीसदी महंगी हो गई है। वहीं कई अन्य राज्य भी कोरोना टैक्स लगाने की तैयारी कर रहे हैं।

मप्र में भी कोरोना टैक्स?

मध्यप्रदेश सरकार का भी खजाना खाली है। अतः यहां भी सरकार शराब पर कोरोना टैक्स लगा सकती है। गौरतलब है कि मार्च और अप्रैल मिलाकर सरकार का आबकारी के जरिए राजस्व संग्रह का कुल लक्ष्य 3263.69 करोड़ रुपए था, लेकिन प्राप्ति सिर्फ 1463 करोड़ रुपए की हुई। इस तरह राजस्व की कुल 1800. 69 करोड़ रुपए की क्षति हुई। इसमें अप्रैल में 1150 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष महज 121 करोड़ रुपए ही मिल सके। इस तरह अप्रैल में कुल 1029 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मार्च में 1995 करोड़ के सापेक्ष 1342 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। मार्च में भी 653 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 118 करोड़ रुपए वैट की क्षति हुई। अब इसकी **भरपाई के लिए सरकार शराब के रेट में वृद्धि** करने जा रही है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के चलते मध्यप्रदेश सरकार को 1800 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई है। इसकी रिकवरी सरकार सालभर में भी नहीं कर पाएगी। जबकि राज्य सरकार का 2020 का लक्ष्य 13,500 करोड़ रुपए है। इसलिए सरकार ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद शराब दुकानों को खोलने का निर्णय लिया। उसकी मंशा है कि वो इससे राजस्व वसूली कर कोरोना से लड़ाई के लिए राजस्व जुटा सके। गौरतलब है कि प्रदेश में 2544 देसी और 1061 विदेशी शराब की दुकानें हैं। यह दुकानें 25 मार्च से बंद हैं।

18 का पेट्रोल 71 रुपए में

शराब के बाद देश और राज्यों को पेट्रोल और डीजल से राजस्व मिलता है। पेट्रोल और डीजल पर एक बार फिर से एक्साइज ड्यूटी में इजाफा

होने के साथ ही भारत दुनिया में ईंधन पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाला देश बन गया है। विगत दिनों केंद्र सरकार ने डीजल पर 13 रुपए और पेट्रोल पर 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला लिया था। सरकार को इस कदम से 1.6 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है। इस कमाई के जरिए केंद्र सरकार कोरोना के संकट से निपटने पर खर्च होने वाली रकम का बड़ा हिस्सा निकालना चाहती है। इससे कुछ दिन पहले पेट्रोल और डीजल दोनों पर ही 8 रुपए प्रति लीटर का सेस जोड़ दिया गया था। इसके अलावा दिल्ली समेत कई राज्यों में भी पेट्रोल और डीजल पर वैट को बढ़ा दिया गया है। दरअसल डीलर तक पेट्रोल महज 18.28 रुपए प्रति लीटर की कीमत में आता है, लेकिन ग्राहकों को फिलहाल 71 रुपए से ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। पेट्रोल पर फिलहाल 32.98 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी वसूली जा रही है, जबकि डीजल पर यह दर 31.83 रुपए प्रति लीटर है। हर राज्य जो पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाता है, उसे वैट कहा जाता है। हालांकि राज्यों में इसकी दर अलग-अलग होती है। मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्यों में 30 फीसदी से ज्यादा तक वैट वसूला जा रहा है। उस पर डीलर कमीशन भी जोड़ा जाता है। डीलर कमीशन राज्यों के हिसाब से अलग है।

फिलहाल केंद्र सरकार को बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी के जरिए 1.6 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई का अनुमान है। हालांकि कई राज्य सरकारों को अप्रैल के महीने में जीएसटी से कमाई में 90 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल से सरकारों को बहुत ज्यादा कमाई होना मुश्किल है। इसकी वजह यह भी है कि फिलहाल देश में पेट्रोल और डीजल की मांग भी बहुत ज्यादा नहीं है।

कुछ और उपाय तलाशने होंगे

कोरोना महामारी ने निसंदेह अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुंचाई है। पूरी दुनिया की आर्थिकी पटरी से उतर चुकी है। देश-प्रदेश की सरकारों को यह नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे पुराने दिन वापस लाए जाएं। इस बीच शराब की बिक्री की इजाजत और पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतों में इजाफा होने से कई सवाल भी खड़े हुए हैं। गौरतलब है कि भारत सरकार अलग-अलग टैक्स और स्त्रोतों से कमाई करती है। ये पैसा वो कल्याणकारी योजनाओं और विकास के कामों में खर्च करती है। मगर जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान ही कई राज्य की सरकारों ने अपनी झोली भरने के लिए शराब की बिक्री शुरू की और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि की, वह चिंताजनक है।

राज्यों को कहां से कितनी होती है कमाई?

राज्य	स्टेट जीएसटी	सेल्स टैक्स	एक्साइज ड्यूटी	स्टॉप ड्यूटी	अन्य सोर्स
आंध्र प्रदेश	36	37	11	9	7
अरुणाचल प्रदेश	27	22	14	1	36
असम	52	27	8	2	11
बिहार	53	21	0	14	12
छत्तीसगढ़	36	17	22	7	19
दिल्ली	53	15	14	12	6
गोवा	48	24	8	11	8
गुजरात	45	27	0	10	18
हिमाचल प्रदेश	41	19	21	4	16
हरियाणा	45	21	14	13	8
झारखंड	54	24	8	3	11
जम्मू-कश्मीर	51	14	14	3	18
कर्नाटक	42	15	21	12	11
केरल	44	36	5	7	8
महाराष्ट्र	49	18	8	13	13
मध्यप्रदेश	37	18	20	10	15
मिजोरम	62	26	1	1	10
नागालैंड	44	32	1	0	23
ओडिशा	42	24	14	7	12
पंजाब	45	17	16	7	14
राजस्थान	39	27	14	7	12
सिक्किम	42	20	24	2	12
तमिलनाडु	39	38	6	11	7
त्रिपुरा	56	20	11	3	10
तेलंगाना	37	32	16	9	6
उत्तराखंड	42	16	21	9	12
उत्तर प्रदेश	35	18	24	14	9
प. बंगाल	46	11	18	10	15

देश में हर व्यक्ति सालाना 5.8 लीटर शराब पीता है

भारत में शराब पीने वाले भी हर साल बढ़ते जा रहे हैं। डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, देश में 2005 में हर व्यक्ति (15 साल से ऊपर) 2.4 लीटर शराब पीता था, लेकिन 2016 में ये खपत 5.7 लीटर हो गई। वहीं 2019 में 5.8 लीटर हो गई। हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि देश का हर व्यक्ति शराब पीता है। इसके साथ ही पुरुष और महिलाओं में भी हर साल शराब पीने की मात्रा भी 2010 की तुलना में 2016 में बढ़ गई। 2010 में पुरुष सालाना 7.1 लीटर शराब पीते थे, जिसकी मात्रा 2016 में बढ़कर 9.4 लीटर हो गई। जबकि, 2010 में महिलाएं 1.3 लीटर शराब पीती थीं। 2016 में यही मात्रा बढ़कर 1.7 लीटर हो गई।

साल	देश	पुरुष	महिला
2010	4.3	7.1	1.3
2016	5.7	9.4	1.7
2019	5.8	9.5	1.8

(आंकड़े लीटर में)

स्वाभाविक तौर पर आज देश के सामने दो समस्याएं ज्यादा विकराल हैं। पहला कोरोना महामारी से निजात दिलाना और दूसरा अर्थव्यवस्था जो औंधे मुंह पड़ी हुई है, उसे ऊपर उठाना। कोविड-19 ने दुनिया के कमोबेश हर देश को झकझोर कर रख दिया है और इससे उबरने का नुस्खा किसी के भी समझ से बाहर है। अर्थव्यवस्था को कैसे जीवंत बनाया जाए ज्यादा माथापच्ची इसी बात पर हो रही है। लेकिन जिस तरह से राजस्व बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों ने शराब बेचने का फैसला लिया, वह न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। पूरे देश ने देखा कि किस तरह कोरोना से लड़ी जा रही लड़ाई के बीच लोगों ने शराब खरीदने के दौरान नियम-कायदों की धज्जियां उड़ाई। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने सीधे तौर पर कहा कि शराब की दुकानों को खोलना राज्य सरकारों के मानसिक दिवालियापन और राजस्व प्राप्त करने के स्वार्थ का जीता जागता सबूत है। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी अहम मसला है। ऐसे में सवाल तो पूछना बनता है कि जब खतरा इतना बड़ा है, तो इस तरह की लापरवाही क्यों की गई?

राजस्व बढ़ाने का जरिया भले शराब और पेट्रोलियम पदार्थ हैं, लेकिन इस वक्त सरकार को **संयम और समझदारी** से काम लेना था। बीते वर्ष सितंबर में भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार अधिकतर राज्यों में कुल टैक्स राजस्व का लगभग 10-15 प्रतिशत हिस्सा शराब पर लगने वाले राज्य उत्पाद शुल्क से लिया जाता है, शायद इसी कारण से राज्यों ने शराब को वस्तु एवं सेवाकर के दायरे से बाहर रखा है। लॉकडाउन में शराब बिक्री पर आंध्र प्रदेश ने 75 फीसद, दिल्ली ने 70 फीसद और उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा ने शराब की बोतल के हिसाब से टैक्स लगाया है। जिससे राज्यों को राजस्व में काफी वृद्धि देखने को मिली है। शराब के साथ-साथ पेट्रोल के दामों में भी तेजी से टैक्स का बढ़ाया जाना वो भी ऐसे समय जब देश में लोगों के पास आमदनी नहीं है, हास्यास्पद ही कहा जाएगा।

कृषि ही उबारेगी मंदी से

महामारी की वजह से महामंदी की आशंका स्वाभाविक है। दुनिया की तकरीबन एक-तिहाई आबादी और आधा हिस्सा महाबंदी को मजबूर है। आम देशों की बात कौन कहे, आर्थिक गतिविधियां ठप होने की वजह से **महाशक्ति अमेरिका** की भी स्थिति डामाडोल नजर आ रही है। ऐसे में भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है। इसके बावजूद कुछ अर्थशास्त्री देश के आर्थिक भविष्य को लेकर आशान्वित भी हैं। उन्हें उम्मीद है कि अपनी विशाल ग्रामीण आबादी और खेती-बाड़ी के चलते देश इस आफत की स्थिति से भी निकल जाएगा। इस उम्मीद की वजह बना है वह तथ्य, जिसके मुताबिक देश के करीब दो-तिहाई जिले इस महामारी के विषाणु की चपेट में आने से बचे हुए हैं। इसके चलते महाबंदी के दिनों में भले ही इन इलाकों में तेज आर्थिक गतिविधियां नहीं चलीं, लेकिन दूसरे इलाकों की तरह एकदम ठप भी नहीं हुई।

भारत की अर्थव्यवस्था का कोई भी आकलन सिर्फ शहरी जनसंख्या को केंद्र में रखकर किया जाएगा तो सटीक नतीजों तक पहुंचना आसान नहीं होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में 68.84 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, जबकि शहरों में सिर्फ 31.16 प्रतिशत लोग ही रहते हैं। नीति आयोग के एक आंकड़े के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों का योगदान 46 प्रतिशत है। भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों की यह प्रत्यक्ष हिस्सेदारी है। इसी आर्थिक आधार पर एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी ने कहा है कि कोरोना से निपटने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को वैसा नुकसान नहीं होने वाला है, जैसी आशंका जताई जा रही है। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोरोना से खास प्रभावित नहीं है, लिहाजा वह मजबूती से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी।

भारत में आर्थिक गतिविधियां भले ही कुछ वक्त के लिए कमजोर रहें, लेकिन भारत के अन्न भंडार इतने भरे हैं कि अगर इनका समुचित तरीके से इंतजाम किया जाए तो भारत में भुखमरी हो ही नहीं सकती। कोरोना के उथल-पुथल भरे दौर में भी अपनी खेती एक बार फिर रिकॉर्ड बनाने जा रही है। स्थिति यह है कि भारत के पहले से **खाद्यान्न भंडार भरे हुए हैं।** रबी की फसल के रिकॉर्ड उत्पादन को ध्यान में रखते हुए खाद्य निगम के सामने चिंता हो गई है कि वह आगामी उपज को कहां रखे। महाबंदी के चलते केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत सभी राज्यों से लोगों को तीन महीने तक मुफ्त राशन मुहैया कराने को कहा है। लेकिन हालात यह है कि सिर्फ तीन केंद्रशासित प्रदेश ही अपने कोटे का पूरा अनाज उठा पाए हैं। बार-बार कहा जा रहा है कि भारत में भुखमरी की स्थिति हो सकती है। लेकिन देश का अन्न भंडार ऐसे ही अकेले वह पूरी दुनिया को छह महीने तक खिला सकता है। एक जनवरी, 2020 के आंकड़े के मुताबिक अनाज पूल में केंद्रीय एजेंसियों के पास 3.19 करोड़ टन और राज्य एजेंसियों के पास 2.45 करोड़ टन अनाज भरा पड़ा है। इनमें 2.37 करोड़ टन जहां चावल है, वहीं 3.27 करोड़ टन गेहूं है। इसके साथ ही इस साल करीब 29.2 करोड़ टन का अनाज पैदा होने का अनुमान है।

यद कीजिए, साल 2008 की वैश्विक मंदी को। संयुक्त राष्ट्रसंघ की एक रिपोर्ट ने भी स्वीकार किया था कि वैश्विक मंदी के दौर से भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया के दूसरे देशों की तरह असर नहीं पड़ा। इसकी वजह उसने भारत के संयुक्त परिवार, ग्रामीण संस्कृति और खेती को बताया था। बेशक भारतीय जीडीपी में इन दिनों खेती की हिस्सेदारी करीब 13 फीसद ही है, लेकिन हथकरघा और खेती आधारित उद्योगों के चलते जीडीपी में भारत की ग्रामीण हिस्सेदारी 30 फीसद तक हो जाती है। वर्ष 2008 में भारतीय अर्थव्यवस्था को उबारने में मनरेगा के जरिए गांवों तक पहुंचे पैसे के साथ ही उत्सवधर्मिता और मेले-ठेले वाली भारतीय संस्कृति ने अर्थव्यवस्था को बचा लिया था। भारत सरकार ने कोरोना राहत के लिए जो 1.70 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया है, उसमें से एक हिस्सा जहां मनरेगा को मिलना है, वहीं किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के तहत दो-दो हजार रुपए दिए जा चुके हैं। इसी तरह हर जनधन खाते में 3 महीने तक पांच-पांच सौ रुपए दिए जा रहे हैं। व्यक्तिगत लिहाज से देखें तो बेशक ये छोटी रकम है, लेकिन सामूहिक तौर पर देखें तो यह विशाल ग्रामीण बाजार को तरल बनाने में ही मदद करेगी।

● ऋतेन्द्र माथुर

गांव अपने पांव पर खड़ा होगा

कोरोना ने मौका दिया है कि स्वावलंबी गांव के गांधी के सपने को पूरा किया जा सके। एक जुलाई, 1947 के यंग इंडिया के अंक में गांधी जी ने लिखा था, 'आजादी नीचे से शुरू होनी चाहिए। हर एक गांव में जम्हूरी सल्तनत या पंचायत का राज होगा। उसके पास पूरी सत्ता और ताकत होगी। इसका यह अर्थ है कि हर एक गांव को अपने पांव पर खड़ा होना होगा, अपनी जरूरतें खुद पूरी कर लेनी होंगी, ताकि वह अपना सारा कारोबार खुद चला सके, यहां तक कि वह सारी दुनिया के खिलाफ अपनी रक्षा खुद कर सके।' लेकिन दुर्भाग्यवश आजाद भारत में शहर केंद्रित नीतियों पर जोर रहा। स्मार्ट-सिटी की अवधारणा पर काम हुआ, लेकिन स्मार्ट-गांव की ओर संजीदगी से ध्यान नहीं दिया गया। इसका असर यह हुआ कि गांव-गांव से पलायन बढ़ा। कोरोना संकट से अपने गांव लौटने के लिए मजदूरों द्वारा हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा की घटनाएं इस विभीषिका का ही प्रतिबिंब हैं। नीति-नियंताओं को ध्यान रखना होगा कि महाबंदी के दौर में जो लाखों मजदूर अपने गांवों को लौटे हैं, हालात सामान्य होने की स्थिति में भी इतनी जल्दी शहरों की ओर नहीं लौटेंगे। गांव वापसी की स्थिति को नीति-नियंताओं को अवसर की तरह देखना चाहिए। गांव लौटे इस कार्यबल के इस्तेमाल के लिए छोटी प्रोडक्शन ईकाइयां, उद्योगों के विकेंद्रीकरण जैसे उपाय अपनाने की दिशा में अगर वे काम करें, तो शहरों पर जहां बोझ कम होगा, वहीं जनसंख्या संतुलन की स्थिति भी बढ़ेगी। इस कार्यबल को उनके गांवों के पास ही काम मिलेगा तो कोई कारण नहीं कि वे शहरों का रुख करें।

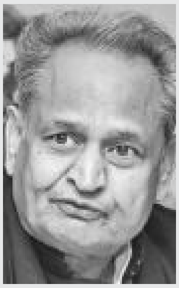

वैज्ञानिक पत्रकार और लेखिका लॉरा स्पीन्नी ने 2017 में प्रकाशित अपनी किताब 'पेल राइडर : द स्पैनिश फ्लू ऑफ 1918 एंड हाउ इट चेंज्ड द वर्ल्ड' में लिखा है- 'हम युद्धों को कुछ दिनों तक याद रखते हैं, फिर धीरे-धीरे उन्हें भूल जाते हैं; जबकि महामारियों को भूल जाते हैं और फिर धीरे-धीरे उन्हें याद रखने लगते हैं।' वैसे, भाजपा के नेतागण जनता की याद्दाश्त को लेकर चिंतित नहीं हैं। उन्हें भरोसा है कि मोदी अपनी पसंद का समय चुनकर एक नया आख्यान गढ़ देंगे, और जनता भी उसी तरह माफ कर देगी और सब कुछ भूल जाएगी जैसे उसने नोटबंदी के बाद किया था। आखिर, लोकसभा चुनाव चार साल दूर है।

भाजपाइयों की परफॉर्मेंस खराब

कोरोना की महामारी के बावजूद भाजपा के समर्थकों के लिए खुश होने के तीन-तीन कारण हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अपने चरम पर है, गृहमंत्री अमित शाह नेपथ्य से पार्टी को चला रहे हैं, और विपक्ष हमेशा की तरह बिखरा हुआ है। फिर भी भाजपा के समर्थक खुश नहीं दिख रहे। पार्टी के लिए चिंता की वजह यह है कि उसके मुख्यमंत्री वक्त की मांग के मुताबिक काम न कर पाए और संकट का कामयाबी से सामना करके मोदी के दूत न बन पाए। जो मुख्यमंत्री सचमुच कोरोना-योद्धा बनकर उभरे उनमें अधिक संख्या गैर-भाजपाई मुख्यमंत्रियों की ही है- केरल के पिनराई विजयन, ओडिशा के नवीन पटनायक, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, राजस्थान के अशोक गहलोत, पंजाब के अमरिंदर सिंह, छतीसगढ़ के भूपेश बघेल, तमिलनाडु के एडाप्पड़ी पालनीस्वामी। भाजपा के केवल सर्वानंद सोनोवाल (असम), मनोहरलाल खट्टर (हरियाणा) ही बेहतर काम करके दिखा पाए।

वैसे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'प्रदेश की 23 करोड़ जनता के प्रति कर्तव्यबोध के कारण' अपने पिता की अन्त्येष्टि में न जाने का जो फैसला किया उसकी काफी प्रशंसा हुई। उप्र में कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की संख्या भी अपेक्षाकृत कम है। लेकिन उनके कामकाज पर सबकी नजर बनी हुई है क्योंकि उनके प्रदेश में टेस्टिंग अभी कुछ दिनों पहले ही शुरू की गई है। 25 अप्रैल के आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में प्रति 10 लाख आबादी पर टेस्टिंग का औसत देश में सबसे नीचा था- (483 के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले मात्र 246)। 2 मई के आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में टेस्टिंग का औसत 425 था जबकि राष्ट्रीय औसत 758 था। कोविड-19 से लड़ने का बहुप्रचारित 'आगरा मॉडल' फिसड्डी साबित हुआ है। अब आदित्यनाथ पर इस संकट का 'संप्रदायीकरण' करने का आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि लखनऊ में कोरोना के हॉटस्पॉट की नाम उन इलाकों की मस्जिदों के नाम पर रखे गए हैं। इसके मुख्यमंत्रियों का कामकाज भाजपा के लिए चिंता का कारण होना चाहिए, क्योंकि मतदाता लोकसभा और विधानसभाओं में अलग-अलग तरीके से मतदान करने लगे हैं, नेता नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी में फर्क करने लगे हैं। राज्यों में भाजपा ने कोविड-19 का जिस तरह मुकाबला किया है उससे उसके गौरव में कोई इजाफा नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में उसका सामना इस आरोप से है और यह सही भी है कि उसने जनता के स्वास्थ्य की कीमत पर, जिससे कई जानें जा सकती हैं, सत्ता की राजनीति को तरजीह दी।

भाजपा-शासित गुजरात ने सबसे ज्यादा मौतों का संदिग्ध रिकॉर्ड बनाया है। वहां सरकार के प्रयास बेहद नाकाफी हैं। जब राज्य सरकार का पूरा ध्यान कोविड-19 से लड़ने पर होना चाहिए था, वह 'नमस्ते ट्रम्प' के आयोजन में व्यस्त थी और इसके बाद वह दलबदल करवाने में व्यस्त हो गई थी ताकि राज्यसभा की एक सीट कांग्रेस न झटक ले जाए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कोविड-19 से कुछ बेहतर मुकाबला किया लेकिन गलत कारणों से सुर्खियों में रहे उनके एक मंत्री बी. श्रीरामुलु ने अपनी बेटी की शादी पर शानदार आयोजन किया। मुख्यमंत्री भाजपा के एक विधायक के बेटे की शादी में जा पहुंचे, राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी को अपने बेटे की शादी का समारोह करने की इजाजत दे दी, राज्य के मंत्रियों के बीच कलह हुई, केरल के साथ सीमा विवाद हुआ, आदि-आदि। एनडीए-शासित राज्यों में सबसे बुरा हाल बिहार का रहा। गत दिनों केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ एक वीडियो कान्फ्रेंस में राज्य के भाजपा सांसदों ने कोविड-19 के मामले में राज्य सरकार के अनमने प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपना गुस्सा उतारा। इससे भी बुरा यह कि इन सांसदों ने शिकायत की कि लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे बिहारी मजदूरों और छात्रों को प्रदेश वापस न आने देकर मुख्यमंत्री ने आगामी

जोखिमों का पुनर्वितरण

यदि मोदी लॉकडाउन की शेष अवधि और पाबंदियों में फेरबदल संबंधी निर्णय मुख्यमंत्रियों पर छोड़ देते हैं, तो वह एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरकर सामने आएंगे जिसने समय रहते फैसले किए, स्थिति को काबू में किया और फिर, सच्ची संघीय भावना से, आगे के फैसले बाकियों पर छोड़ दिए। लॉकडाउन संबंधी शुरुआती भाषण के बाद मोदी आगे की घोषणाओं में अधिक संघीय और सलाहकारी नजर आए। जोखिमों को आगे बांटना, संकट से बाहर निकलने की उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। निश्चित रूप से मोदी समर्थक इस बात को उछालेंगे कि उनके आलोचकों को दोनों ही स्थितियों से समस्या होती है, जब फैसले केंद्रीय स्तर पर लिए जाते हों और जब वह इसे राज्यों पर छोड़ते हों। लेकिन यहां बात टाइमिंग की है। भारत को फिर से खोलने का निर्णय राजनीतिक जोखिमों से भरा हुआ है और इसलिए यह साझा निर्णय बन जाता है।

विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए की साख को भारी धक्का पहुंचाया है। जोशी के इस वीडियो कान्फ्रेंस में भाग लेने वाले एक वरिष्ठ भाजपा ने इस लेख के लेखक से कहा कि 'बिहारी लोग एक तरफ कुआं (जेडीयू) और दूसरी तरफ खाई (राजद) के बीच फंसे हैं। लेकिन आलाकमान ने फैसला कर दिया है (नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके), तो अब मोदी ही हमारे लिए उम्मीद की एकमात्र किरण हैं।'

जो हालात बने हैं उनके लिए मुख्यमंत्रियों को दोष देना बहुत आसान है लेकिन क्या वे सचमुच दोषी हैं? गुजरात को वहां के मुख्यमंत्री विजय रूपाणि के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के. कैलाशनाथन (जो मोदी के करीबी हैं) के जरिए दिल्ली से चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस सरकार का तख्ता पलटने में अगुवाई की, लेकिन कोविड-19 से लड़ाई में उनके हाथ बंधे नजर आते हैं। राज्य में कोविड-19 के कारण हालात बिगड़ते रहे लेकिन हफ्तों तक 'सुपर सीएम' की भूमिका में आने का फैसला उनका अपना नहीं था। वे दिल्ली की सत्ता मंडली में शामिल नहीं थे इसलिए जब कमलनाथ को हटाने का मकसद सध गया तो उन्हें अपने भरोसे छोड़ दिया गया।

काफी शोर-शराबे के बाद चौहान को एक छोटा-सा मंत्रिमंडल दिया गया, लेकिन इससे उनका काम आसान नहीं हुआ है। उन्हें गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय नरोत्तम मिश्र को देने पड़े, जो अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। भोपाल में जब भाजपा विधायक दल के नेता का चुनाव हो रहा था तब मिश्रा के समर्थक नारे लगा रहे थे- 'हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, नरोत्तम मिश्रा जैसा हो'। कर्नाटक में येदियुरप्पा को गद्दी से अलग नहीं रखा जा सकता था क्योंकि उनकी वजह से ही कुमारस्वामी सरकार का पत्ता साफ हुआ, फिर भी वे मोदी-शाह का भरोसा नहीं जीत पाए हैं। इसके चलते उनकी सरकार में हर कोई अपनी मर्जी चला रहा है। बिहार में, अमित शाह ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। राज्य के भाजपा नेता आज चाहे जितना गुस्सा जाहिर करें, उन्हें हालत को कबूल करना पड़ेगा और यह उम्मीद रखनी पड़ेगी कि लालू यादव के 'जंगल राज' का डर नीतीश कुमार की अक्षमता और बढ़ती आलोकप्रियता की भरपाई करेगा।

एनडीए के कुछ मुख्यमंत्री कोविड-19 से लड़ने में कमजोर साबित होते हैं तो क्या इससे फर्फ पड़ सकता है? ऊपर से लगता है कि नहीं पड़ेगा। कम से कम मोदी को तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोरोना संकट में उनकी लोकप्रियता बढ़ी ही है। वे मजबूती से डटे हुए हैं, उनका कोई विश्वसनीय प्रतिद्वंद्वी नजर नहीं आता। लेकिन यह संकट भाजपा के तेज पतन का कारण बन सकता है, जो दिसंबर 2018 में राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ में उसकी हार से शुरू हुआ था। अगला विधानसभा चुनाव बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में होना है। इसके बाद असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव होंगे। इनमें से अंतिम तीन राज्य भाजपा के लिए महत्व नहीं रखते क्योंकि उनमें उसका कोई दावा नहीं है। असम में उसकी स्थिति अच्छी है, जहां कोरोना अभी बड़े संकट के रूप में सामने नहीं आया है। लेकिन एनडीए-शासित बिहार और तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम बंगाल के चुनाव भाजपा के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। बिहार में विपक्ष जिस तरह बिखरा हुआ है और जातीय समीकरण भाजपा के काफी अनुकूल है, इसलिए वहां के चुनाव नतीजे यह पहला संकेत देंगे कि कोरोना संकट से निपटने में मोदी सरकार के प्रयासों पर किस तरह की चुनावी मुहर लगने वाली है। पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार और राज्यपाल जगदीप धनकड़ ने ममता बनर्जी सरकार की पोल अच्छी तरह खोली है कि वह कम टेस्टिंग, आंकड़ों में हेरफेर के जरिए कोरोना संकट किस तरह हल्के में ले रही थी। इसके बाद इस संकट के मामले में राज्य सरकार के प्रयासों में भारी बदलाव आया है।

● दिल्ली से रेणु आगाल

राज्यों के हाथ बंधे

कोरोना के इस संक्रमणकाल में केंद्र मॉनीटर की तरह कार्य कर रहा है। वहीं सभी राज्य केंद्र के दिशा-निर्देशों का बखूबी पालन कर रहे हैं। इसलिए इस संकट की स्थिति में कोई भी अपने हिसाब से कदम नहीं उठा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने राज्यों को फ्री हैंड कर दिया है कि वे अपने हिसाब से स्थिति को भांपते हुए राज्य में गतिविधियों को संचालित कर सकते हैं। लेकिन क्या मुख्यमंत्रियों के लिए सभी प्रतिबंधों को हटाना संभव होगा या वे अतिरिक्त सतर्कता बरतेंगे? जिस अधीरता के साथ वे प्रवासी श्रमिकों को अपनी सीमाओं से बाहर करना चाहते हैं (अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, के. चंद्रशेखर राव) और आवागमन रोकने के लिए जिस तरह सड़कों पर गड्ढे बनाए जा रहे हैं (मनोहरलाल खट्टर), उससे यही संकेत मिलता है कि वे सावधानी बरतेंगे और लॉकडाउन हटाने की जल्दी नहीं करेंगे। खासकर जब लौट रहे प्रवासी पॉजिटिव पाए जा रहे रहे हों और कई राज्यों में ग्रीन जोन कम हो रहे हों। भारत में कोविड-19 हॉटस्पॉट जिलों की संख्या एक पखवाड़े पूर्व के 170 से घटकर 129 हो गई है, लेकिन इसी अवधि में संक्रमण मुक्त जिलों या ग्रीन जोनों की संख्या भी 325 से घटकर 307 रह गई है।' मोदी सरकार ने भले ही लॉकडाउन को आसान बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हों। लेकिन उसका क्रियान्वयन राज्यों में रंगों वाले जोनों और मुख्यमंत्रियों के सतर्क फैसलों पर निर्भर करेगा। हालांकि राज्य इस संबंध में अपना हाथ बंधा हुआ पा सकते हैं। दरअसल, लॉकडाउन के कारण जो आर्थिक क्षति पहुंची है, राज्यों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार उसकी भरपाई करेगा। इसलिए कोई भी केंद्र के दिशा-निर्देश का उल्लंघन नहीं कर रहा है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के दबदबे का चाहे जो बखान किया जाता रहा हो, आज हकीकत यह है कि भाजपा का वैचारिक संरक्षक यह संगठन नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में हाशिए पर पड़ा दिख रहा है। इसकी वजह यह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघनिष्ठ भाजपाई संघ को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। भाजपा को खड़ा करने में जहां संघ का मुख्य योगदान है, वहीं भाजपा की सरकारें योजनाएं बनाने में संघ की न तो सलाह ले रही हैं और न ही उनके द्वारा दी जा रही सलाहों को महत्व दे रही हैं। ताजा मामला श्रम सुधारो को लेकर सामने आया है। जहां संघ ने उसका विरोध किया है।

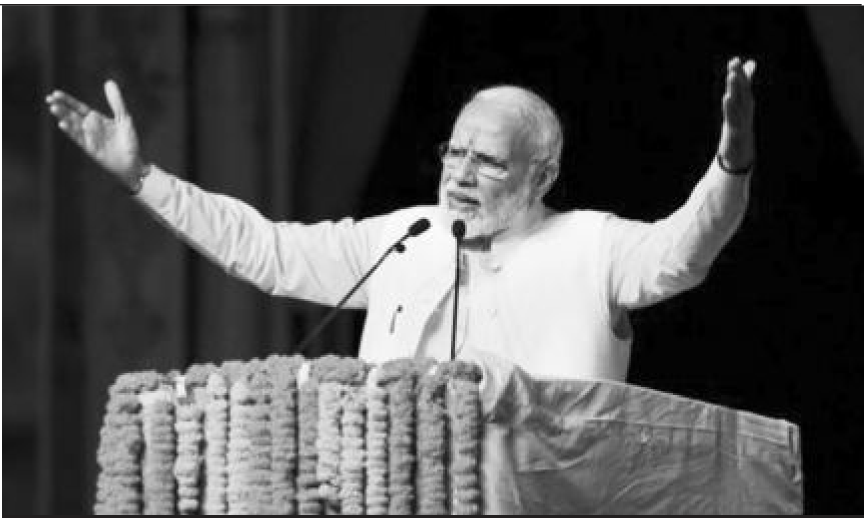

संघ की धमक हुई कम

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकारों ने पिछले सप्ताह जो महत्वपूर्ण श्रम सुधार किए उनका आरएसएस के मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने उम्मीद के मुताबिक विरोध किया। बीएमएस के अध्यक्ष साजी नारायणन ने कहा कि संघ 'जंगल राज' की इजाजत नहीं दे सकता और मजदूरों को 'कॉरपोरेट्स के हाथों का खिलौना नहीं बनने दे सकता।' लेकिन उप्र, मप्र और केंद्र की भाजपा सरकारों को इससे कोई फर्फ नहीं पड़ा है। बीएमएस के विरोध के दो दिनों बाद गुजरात में विजय रूपाणी के नेतृत्व वाली सरकार ने नए उद्योगों को 1200 दिनों के लिए श्रम कानूनों से मुक्त करने घोषणा कर दी। इसी नक्शेकदम पर चलते हुए गोवा की भाजपा सरकार ने फैक्टरीज एक्ट और काम के घंटों से संबंधित **कानूनों में ढील देने का ऐलान** कर दिया। अब आरएसएस को यह तो पता ही है कि राज्यों की भाजपा सरकारें केंद्र के समर्थन के बिना ऐसे साहसिक कदम नहीं उठा सकतीं, सो उसके लिए इस उपेक्षा को बर्दाश्त करने के सिवाय कोई उपाय नहीं है। अब आरएसएस अपने पूर्व प्रचारक नरेंद्र मोदी के लिए थाली और ताली बजाने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता, जिनका कद अब संघ के दायरे में समाने वाला नहीं रह गया है।

2014 का लोकसभा चुनाव जीतने के कुछ ही दिनों बाद मोदी ने एक ब्रिटिश लेखक को दिए इंटरव्यू में साफ कह दिया था कि लोगों ने उनकी पार्टी (या कहें आरएसएस) को नहीं बल्कि उनको वोट दिया है। आरएसएस व्यक्तिपूजा से परहेज करने के चाहे जो दावे करता रहा हो। मोदी के दूसरे कार्यकाल में आरएसएस-भाजपा तालमेल की अनौपचारिक व्यवस्था जरूर कायम है, मगर वह नाम का ही है। दोनों के नेताओं ने कभी साथ बैठकर कोरोना संकट तक पर विचार नहीं किया है। आरएसएस के एक पदाधिकारी ने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तक को अपने आंतरिक स्त्रोतों से विरोध की जितनी आवाजें सुननी पड़ती हैं, उतनी तो आज मोदी सरकार को न तो आरएसएस से सुननी पड़ रही हैं, न भाजपा से।

आरएसएस की वाजपेयी युग वाली अकड़ ढीली पड़ गई है। वाजपेयी सरकार ने जब भी बालको, हिंदुस्तान जिंक, या आईटीडीसी के होटलों जैसे सार्वजनिक उपक्रमों में रणनीतिक विनिवेश का कदम उठाया, आरएसएस उनका गला पकड़ने को कूद पड़ता था। उसने अपने ही एक पूर्व प्रचारक अटल बिहारी वाजपेयी से इस बात के लिए अपनी नाराजगी कभी नहीं छिपाई कि वे उसके हिंदुत्ववादी एजेंडे को आगे नहीं बढ़ाते थे। जब वक्त आया तो उसने 2002 के गुजरात दंगे में 'राजधर्म' का पालन न करने के लिए मोदी को मुख्यमंत्री पद से हटाने की वाजपेयी की कोशिश में अड़ंगा लगाने वाले लालकृष्ण आडवाणी का समर्थन किया।

अब 18 साल बाद आरएसएस खुद को प्रासंगिक बनाए रखने और अपना विस्तार करने की हताशा में मोदी का दामन थामे हुए है। 'ब्रांड मोदी' जबकि आरएसएस से बड़ा होता जा रहा है, आरएसएस भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की चेरी बनकर भी खुश होने को मजबूर है।

2014 में मोदी जब प्रधानमंत्री बन गए उसके करीब सात सप्ताह बाद आरएसएस नेताओं के एक दल ने संघ और सत्ता पक्ष के बीच तालमेल की व्यवस्था पर तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से चार घंटे विचार-विमर्श किया और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के निवास पर रात्रि भोज किया। इसके बाद आरएसएस-भाजपा अनौपचारिक कोर ग्रुप का गठन हुआ जिसमें आरएसएस के भैयाजी जोशी, दत्तात्रेय होसबले और कृष्ण गोपाल सरीखे वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बाद के महीनों और सालों में यह कोर ग्रुप नीतिगत मसलों पर विचार करने के लिए अमित शाह और मोदी के मंत्रियों के साथ

जमीनी सच्चाई से कटे

मोदी और शाह के इर्द-गिर्द सीमित हो चुकी भाजपा के कुल परिवेश पर आरएसएस की कमजोर पड़ती पकड़ इस बात से भी उजागर होती है कि मोदी अचानक जमीनी सच्चाई से कटे हुए दिखते हैं और मध्यवर्ग को खुश करने में जुटे दिखते हैं जबकि उससे कहीं ज्यादा बड़े लाखों प्रवासी मजदूरों के तबके से जुड़ा संकट तपती सड़कों और रेल पटरियों पर फैलता दिख रहा है। संघ की आर्थिक शाखा स्वदेशी जागरण मंच भी बीएमएस वाली नाव पर सवार दिखती है। वह भी श्रम कानूनों, सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश, फेसबुक-जियो सौदे और शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) जैसे मसलों पर भाजपा सरकार की नीतियों का भारी विरोध करता रहा है। लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का प्रतिनिधित्व करने वाले आरएसएस के संगठन 'लघु उद्योग भारती' के लगातार विरोधों का भी मोदी सरकार पर कोई असर नहीं होता दिख रहा है।

‘जंगलराज की अनुमति नहीं दे सकते’

आरएसएस के श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने भाजपा शासित मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश सरकारों द्वारा इस सप्ताह श्रम कानूनों में किए गए बदलावों का विरोध किया है। बीएमएस ने श्रम कानूनों में इन बदलावों को श्रम कानूनों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन बताते हुए कहा है कि इससे अराजकता की स्थिति बन जाएगी। बीएमएस के अध्यक्ष साजी नारायणन ने कहा– ‘यह कोरोनावायरस के मुकाबले कहीं बड़ी महामारी साबित होगी। बीएमएस इस मुद्दे पर एक आपात बैठक आयोजित करेगा और इन कदमों का विरोध करेगा।’ उन्होंने कहा, ‘ये समय श्रम सुधारों का नहीं है। हम जंगलराज की स्थिति नहीं बनने देंगे। हम मजदूरों को उद्योग जगत के रहमोकरम पर नहीं छोड़ सकते। विभिन्न राज्य ऐसी स्थिति निर्मित कर रहे हैं कि मानो कोई कानून है ही नहीं।’ नारायणन ने कहा कि मध्यप्रदेश ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधिकांश प्रावधानों को वापस ले लिया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधनों के बाद, नए उद्यमों को अगले 1,000 दिनों तक कई प्रावधानों से छूट मिल जाएगी, जिनमें मजदूरों को अपनी सुविधा के अनुसार नौकरी पर रखना भी शामिल है। संशोधनों के बाद अब श्रम विभाग के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं रह जाएगी।

बैठकें करता रहा। दोनों पक्ष हमेशा एकमत तो नहीं होते थे मगर इस व्यापक विचार-विमर्श से सरकार को निरंतर फीडबैक मिलता रहता था।

जून 2018 में बीएमएस के प्रतिनिधियों ने अमित शाह से मिलकर उन श्रम सुधारों का विरोध किया जिनके तहत 44 श्रम कानूनों को मिलाकर चार संहिताएं बनाने का प्रस्ताव किया गया था। आरएसएस के नेताओं ने एक बयान जारी करके कहा कि शाह ने आश्वासन दिया है कि मजदूर संघों से सलाह-मशविरा करने के बाद ही श्रम कानूनों में सुधार या बदलाव किए जाएंगे। लेकिन इस मसले पर वह बैठक आखिरी सलाह-मशविरा ही साबित हुआ। 14 महीने बाद, मोदी सरकार ने 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जो प्रारंभिक कानून बनाए उनमें एक था ‘कोड ऑन वेजेज-2019’।

बीएमएस रास्ते पर आ गया, उसने इसे ‘ऐतिहासिक कानून’ घोषित कर दिया, जबकि दूसरे मजदूर संघ उसकी आलोचना कर रहे थे। जुलाई 2019 में आरएसएस ने वैचारिक संरक्षक और राजनीतिक आश्रित के बीच समन्वय के लिए भाजपा के महासचिव (संगठन) पद पर बिठाए गए अपने नेता रामलाल को हटाकर बीएल संतोष को बैठा दिया। रामलाल इस पद पर 12 साल रहे और माना जाता है कि वे भाजपा के तंत्र में इतने समाहित हो गए थे कि आरएसएस ने उन्हें वहां से हटाकर किसी अधिक मुखर सिद्धांतकार को तैनात करना जरूरी समझा। लेकिन, संतोष भाजपा की जयकार करने वाले नेता ही साबित हुए हैं।

आरएसएस के पसंदीदा मुद्दे राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी पिछले 6 वर्षों में कुछ नहीं किया गया है। मानव संसाधन विकास और स्वास्थ्य मंत्रालय तो आरएसएस की संबंधित शाखाओं ‘भारतीय शिक्षण मंडल’ और ‘आरोग्य भारती’ से विचार-विमर्श तो करते रहे हैं लेकिन ये सब रस्मी ही रहे हैं, जिनका कोई ठोस नतीजा नहीं दिखा है। जैविक खेती और ई-कॉमर्स के नियमन जैसे और **कई मसलों को लाकर भी संघ मोदी सरकार से नाराज है।** अपनी कमजोर पड़ती पकड़ के एहसास के कारण आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अक्टूबर 2019 में विजयादशमी पर अपने उद्‌बोधन में एफडीआई और उपक्रमों के विनिवेश का समर्थन कर दिया। देखा जाए तो भाजपा के 52 केंद्रीय मंत्रियों में से 38 संघ की पृष्ठभूमि वाले हैं। भाजपा के अधिकतर मुख्यमंत्री भी ऐसे ही हैं। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रक्षामंत्री ही जब आरएसएस के हैं, तो विपक्ष अक्सर कहता रहता है कि यह सरकार नागपुर (आरएसएस मुख्यालय) के रिमोट कंट्रोल से चलती है। लेकिन ऊपर के उदाहरणों से लगता है कि सच कुछ ज्यादा ही उलझा हुआ है।

आरएसएस ने अगर यह कबूल कर लिया है कि सत्ता पक्ष से उसके संगठनों को जो रेवड़ी मिल जाए और उसके वफादारों को विभिन्न संस्थानों में जो जगह मिल जाए वही काफी है, तो इसकी दो वजहें हैं। पहली यह कि मोदी सरकार ने उसके बड़े वैचारिक एजेंडों को पूरा कर दिया है– अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया गया है, अनुच्छेद-370 को कमजोर करके जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया है, तीन तलाक को अपराध घोषित कर दिया गया है, जिसे समान नागरिक संहिता की ओर एक कदम माना जा रहा है। आरएसएस के नेतागण इस बात से प्रसन्न हैं कि ‘हिंदुत्ववादी राजनीति को लगभग व्यापक स्वीकृति’ मिल गई है और अधिकतर दल नहीं चाहते हैं कि उन्हें मुसलमानों के समर्थक के रूप में देखा जाए। संघ के स्वयंसेवक जब केंद्र और राज्यों में बड़े ओहदों पर बैठे हैं, संघ को लगने लगा है कि वह राष्ट्रीय राजनीति की ‘मुख्य धारा’ में आ गया है।

दूसरी वजह यह है कि आरएसएस के पास कोई विकल्प नहीं है। इसके संस्थापक केबी हेडगेवार कभी कांग्रेस में थे। संघ के वरिष्ठ विचारक एमजी वैद्य ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 1934 में महात्मा गांधी वर्धा में संघ के शिविर में आए थे। 1963 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने के लिए आरएसएस को निमंत्रित किया था। उनके उत्तराधिकारी लालबहादुर शास्त्री ने भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान तत्कालीन संघ प्रमुख एमएस गोलवलकर से सलाह-मशविरा किया था। वैद्य ने कहा था– ‘आरएसएस के लिए कोई भी अछूत नहीं है।’ संघ ने बांग्लादेश मुक्ति संघर्ष के दौरान इंदिरा गांधी सरकार का समर्थन किया था। कहा जाता है कि 1984 के लोकसभा चुनाव में संघ ने राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस का समर्थन किया था। लेकिन वे सब अलग दिन थे। भाजपा कोई बड़ी राजनीतिक ताकत नहीं थी, न ही कांग्रेस उस समय संघ की उतनी घोर विरोधी थी जितनी सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल के नेतृत्व में है। अपना विस्तार करने और भारत को ‘हिंदू राष्ट्र’ बनाने का अपना एजेंडा पूरा करने के लिए आरएसएस को राजनीतिक संरक्षण की जरूरत है। मोदी सरकार में बैठे अपने पूर्व प्रचारकों और स्वयंसेवकों के कारण वह खुद को भले उपेक्षित और आहत महसूस करे, लेकिन समीकरण बदल गए हैं। आज भाजपा को आरएसएस की जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा आरएसएस को मोदी की भाजपा की जरूरत है।

● **इन्द्र कुमार**

सपनों के सौदागर

छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत नाजुक बताई जा रही है और फिलहाल वह कोमा में हैं। गत दिनों उन्हें हार्टअटैक आया था, जिसके बाद वो कोमा में चले गए। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री तो रहे ही हैं, आज की तारीख में भी प्रदेश के सबसे कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती है। वह हमेशा से राजनीति में नहीं थे। उनका कैरियर इंजीनियरिंग से शुरू हुआ और फिर वो बड़े नौकरशाह बन गए। फिर अचानक एक दिन राजनीति में उनका सितारा बुलंदियों पर पहुंच गया। उनके सियासी और नौकरशाही कैरियर से कई विवाद भी जुड़े हुए हैं और ऐसे कई मौके आए हैं, जब वह मौत के मुंह से भी वापस आ चुके हैं।

छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी राजनीति के धुरंधरों में गिने जाते रहे हैं। अजीत जोगी को सपनों का सौदागर भी कहा जाता रहा है। अजीत जोगी ने खुद अपने आपको सपनों का सौदागार बताया था। साल 2000 में जब अजीत जोगी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने कहा था- 'हां, मैं सपनों का सौदागर हूं। मैं सपने बेचता हूं।' लेकिन 2003 में हुए विधानसभा चुनावों में अजीत जोगी को हार का सामना करना पड़ा। फिर 2008 में और 2013 में भी वो सपने नहीं बेच पाए। अजीत जोगी के राजनीतिक सफर की बात करें तो उन्होंने शुरुआती दिनों में काफी चुनौतियों का सामना किया।

अजीत जोगी 1986 से 1998 के बीच दो बार राज्यसभा के सांसद चुने गए। 1998 में वे रायगढ़ से सांसद चुने गए। 1998 से 2000 के बीच वे कांग्रेस के प्रवक्ता भी रहे। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद वे 2000 से 2003 के बीच राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे। 2004 से 2008 के बीच वे 14वीं लोकसभा के सांसद रहे। 2008 में वे मरवाही विधानसभा सीट से चुनकर विधानसभा पहुंचे और 2009 के लोकसभा चुनावों में चुने जाने के बाद जोगी ने लोकसभा सदस्य छत्तीसगढ़ के महासमुंद निर्वाचन क्षेत्र के रूप में काम किया। हालांकि जोगी 2014 के लोकसभा चुनावों में अपनी सीट बरकरार रखने में असफल रहे और भाजपा के चंदू लाल साहू से 133 मतों से हार गए।

2014 में छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ में उपचुनाव होना था। कांग्रेस की ओर से मंतूराम पंवार प्रत्याशी थे। उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। वापस लेने के आखिरी दिन मंतूराम ने पार्टी को बिना बताए नाम वापस ले लिया। 2015 के आखिर में एक ऑडियो टेप सामने आया जिसमें खरीद-फरोख्त की बातें थीं। आरोप लगे कि टेप में अजीत जोगी, उनके बेटे अमित जोगी और तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता की आवाज थी। ये बातचीत मंतूराम पंवार के नाम वापस लेने के बारे में थी। इस टेपकांड के सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ की प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को छह साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। इसके साथ ही अजीत जोगी को भी पार्टी से निकालने की सिफारिश कर दी गई।

फिर अजीत जोगी ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और साल 2016 में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के नाम से अपनी नई पार्टी बनाई। छत्तीसगढ़ की राजनीति में दो मुख्य खिलाड़ी ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। किसी मजबूत और जमीनी पकड़ रखने वाले क्षेत्रीय दल की कमी की वजह से प्रदेश के लोगों के पास बस ये दो ही विकल्प थे। अजीत जोगी ने जनता को वो विकल्प देने के लिए पार्टी का गठन किया। वो भी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले।

फिर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करते हुए खुद के बारे में कहा कि इन चुनावों में वो किंगमेकर की भूमिका निभाएंगे, यानी जिसे वो चाहेंगे उसके हाथों में छत्तीसगढ़ की सत्ता की बागडोर होगी। लेकिन उनका ये गठबंधन फ्लॉप साबित हुआ और कांग्रेस की आंधी में भारतीय जनता पार्टी के साथ-साथ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी का भी प्रदर्शन निराशाजनक रहा। अजीत जोगी की पार्टी को 5 सीटे ही उनकी पार्टी की झोली में आ पाई। फिलहाल अजीत जोगी मरवाही विधानसभा से विधायक हैं।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

विवादों से हमेशा जुड़ा रहा नाम

अजीत जोगी के नाम सबसे बड़ा विवाद उनके आदिवासी होने को लेकर रहा। हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर, 2018 में उनके आदिवासी होने के पक्ष में फैसला दिया। अजीत जोगी से एक विवाद उनकी बेटी की कथित खुदकुशी से भी जुड़ा है। घटना 12 मई, 2000 की है। अजीत जोगी इंदौर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के स्वागत में लगे हुए थे, उसी दौरान उनकी बेटे ने इंदौर स्थित उनके घर पर ही जान दे दी। जानकारी के मुताबिक वह जहां शादी करना चाहती थी, जोगी उसके लिए राजी नहीं थे। उसका शव उस समय इंदौर के ही कब्रिस्तान में दफनाया गया। लेकिन, अजीत जोगी ने बाद में कोशिश की थी कि शव को निकालकर अपने पैतृक गांव ले जाएं, लेकिन प्रशासन ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। लेकिन, जब वे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने तो एक दिन रातों-रात उन्होंने उस शव को निकालकर सरकारी विमान से बिलासपुर मंगवा लिया और फिर उसे वहां क्रिश्चियन रीति-रिवाज से दफना दिया। 2003 में अजीत जोगी पर भाजपा विधायकों को खरीदने की कोशिश के भी आरोप लगे थे, इसका एक स्टिंग ऑपरेशन भी आया था। 2004 में अजीत जोगी के साथ एक भीषण कार ऐक्सिडेंट हुआ था, जिसमें उनकी जान तो बच गई, लेकिन वे हमेशा के लिए लकवाग्रस्त होकर रह गए। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया था कि विरोधियों के जादू-टोने की वजह से वह हादसा हुआ था।

अगर यह कहा जाए कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे वाली महाआघाड़ी गठबंधन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की कृपा पर टिकी हुई है तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। इस बात का संकेत मोदी-शाह ने ठाकरे को राज्य विधानपरिषद में निर्विरोध जिताकर दे दिया है।

ठाकरे का भाग्य

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुन लिए गए। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे की मुश्किलें भी खत्म हो चुकी हैं। यह संभव हो पाया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कृपा के कारण। दरअसल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को 27 मई तक राज्य की विधायिका का सदस्य बनना था। लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण फिलहाल किसी चुनाव के आसार नहीं थे। ऐसे में ठाकरे की कुर्सी जानी तय थी और संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सरकार पर भी संकट गहरा जाता।

बताया जाता है कि इस स्थिति से परेशान होकर 30 अप्रैल को ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और उसके बाद राज्यपाल कोश्यारी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। राज्यपाल ने ठाकरे का नाम सदस्यता के लिए मनोनीत तो नहीं किया लेकिन चुनाव आयोग से विधान परिषद की 9 रिक्त सीटों पर जल्द से जल्द चुनाव कराने का अनुरोध किया। उसके बाद विधान परिषद की 9 सीटों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई और 14 मई को उद्धव ठाकरे के अलावा 8 अन्य उम्मीदवारों को भी राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के अलावा विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरे (शिवसेना), रणजीत सिंह मोहिते पाटिल, गोपीचंद पाडलकर, प्रवीण दटके और रमेश कराड (सभी भाजपा) को भी निर्वाचित घोषित किया गया है। निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों में राकांपा के शशिकांत शिंदे और अमोल मितकरी तथा कांग्रेस के राजेश राठौड़ शामिल हैं। ये सभी उम्मीदवार विधान परिषद की उन 9 सीटों के लिए मैदान में थे जो 24 अप्रैल को खाली हुई थीं।

भले ही ठाकरे चुनाव जीतने के बाद राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन वे मोदी और शाह की कृपा पर ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं। दरअसल, वर्तमान समय में राज्य की स्थिति ऐसी नहीं है कि भाजपा तख्ता पलटकर अपनी सरकार बनाती। दरअसल, महाराष्ट्र पूरी तरह कोरोना की चपेट में है। पूरे राज्य में 26 हजार से ऊपर कोरोना संक्रमित लोग हैं। वहीं एक हजार से अधिक की मौत हो चुकी है। अभी भी स्थिति ऐसी है कि राज्य में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में भाजपा कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती थी। अगर भाजपा तख्ता पलट कर देती तो उसके ऊपर यह आरोप लगते कि इस संकटकाल में भी उसने सत्ता के लालच में सरकार पलट दी। वहीं उस पर कोरोना को नियंत्रित करने का भार आ जाता। इसलिए मोदी-शाह ने राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न न हो इसके लिए विधान परिषद के चुनाव कराना ही उचित समझा।

गौरतलब है कि नवंबर 2019 में जब उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उस समय वो ना राज्य की विधानसभा के सदस्य थे और ना विधान परिषद के। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार उनके पास दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य चुने जाने के लिए छह महीनों का समय था। वो अवधि 28 मई को समाप्त हो रही थी और इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य के मंत्री-परिषद ने 9 अप्रैल को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से ठाकरे को विधान परिषद की सदस्यता के लिए मनोनीत करने की अनुशंसा की थी। अमूमन राज्यपाल मंत्री-परिषद की अनुशंसा नजरअंदाज नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोश्यारी ठाकरे को सदस्यता के लिए मनोनीत नहीं करते तो वो विधायिका के सदस्य नहीं बन पाते और 28 मई तक उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना पड़ता। ऐसे में मोदी-शाह ने ठाकरे की गुहार को गंभीरता से लिया और विधान परिषद का चुनाव कराकर उन्हें निर्विरोध जीतने का मौका दे दिया। इस चुनाव के साथ 59 वर्षीय ठाकरे पहली बार विधायक बने हैं।

महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को जीवनदान तो मिल गया है लेकिन उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। कोरोना का संक्रमण इस समय उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक कोरोना के मामले तो हैं ही, यहां सबसे अधिक मौतें भी हो रही हैं। इसलिए ठाकरे को अभी चुनौतियों से लगातार जूझना है। अब देखना यह है कि वे इन चुनौतियों से किस तरह निकल पाते हैं।

● **बिन्दु माथुर**

उद्धव पर कृपा क्यों...?

उद्धव ठाकरे के निर्विरोध चुनाव जीतने के बाद देश की राजनीति में यह सवाल उठने लगा है कि उद्धव ठाकरे पर मोदी-शाह ने इतनी कृपा क्यों की है। तो इसके पीछे एक सोची-समझी राजनीति है। दरअसल, भाजपा और शिवसेना एक ही विचारधारा की पार्टी हैं। दोनों में वर्षों पुराना गठबंधन रहा है। भले ही इस बार दोनों पार्टियां अलग-अलग हो गई हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से दोनों में अभी भी जुड़ाव है। अगर भाजपा महाराष्ट्र की सरकार गिराने की कोशिश करती तो शिवसेना के साथ उसकी खाई और बढ़ती जाती। इससे भविष्य में दोनों पार्टियों में गठबंधन की कोई भी संभावना खत्म हो सकती थी। अतः मौके की नजाकत को भांपते हुए मोदी-शाह ने उद्धव ठाकरे की गठबंधन वाली सरकार को बचाकर उन पर एक एहसान कर दिया है। साथ ही यह रास्ता भी खोल दिया है कि अगर भविष्य में ठाकरे चाहें तो भाजपा उनके साथ गठबंधन कर सकती है। बिहार में भाजपा ऐसा प्रयोग कर चुकी है। वहां नीतीश कुमार और राजद के गठबंधन की सरकार थी। राजद की मनमानी जब बढ़ने लगी तो मोदी-शाह ने नीतीश कुमार की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और नीतीश कुमार ने राजद के साथ गठबंधन तोड़कर भाजपा के साथ सरकार बना ली। भविष्य में कुछ ऐसा ही महाराष्ट्र में हो सकता है।

फिर सुलगने लगी आग

सचिन पायलट किसी बेहतर मौके की तलाश में

राजस्थान में कोरोना वायरस के संक्रमणकाल में सत्तारूढ़ कांग्रेस में वर्चस्व की आग सुलगने लगी है। जानकारों का कहना है कि कोरोना की स्थिति सुधरने के बाद पार्टी में एक बार फिर से विरोध प्रबल हो जाएगा। दरअसल, उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच की खाई दिन पर दिन गहरी होती जा रही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के दो खेमे हैं। यह लड़ाई कोई नई नहीं है। दिसंबर 2013 के चुनाव में जब कांग्रेस हारी तब मुख्यमंत्री पद से अशोक गहलोत हटाए गए और राज्य में युवा एवं नए नेतृत्व के नाम पर यूपीए-2 के केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट की राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर ताजपोशी हुई। उस वक्त से ही राज्य के सबसे कद्दावर नेता अशोक गहलोत और कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की पसंद युवा नेता सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस की दो धुरी बन गए। इनके चेलों ने भी अपने-अपने हिसाब से कांग्रेस में दो खेमे बना लिए।

अशोक गहलोत के बारे में कहा जाता है कि यह राजनीति के चतुर सुजान हैं। अशोक गहलोत किसी के जाप्ता करने का प्लान बना लेते हैं तो फिर वह उसे छोड़ते नहीं है। लोग उदाहरण देते हैं कि कैसे अशोक गहलोत ने परशुराम मदेरणा, शीशराम ओला और सीपी जोशी जैसे नेताओं को ठिकाने लगाया था। अशोक गहलोत के बारे में कहा जाता है कि वह चाल कहां चलते हैं और निशाना कहां रखते हैं यह किसी को पता नहीं चलता। जब सचिन पायलट अपनी ताजपोशी की तैयारी कर रहे थे उसी वक्त अशोक गहलोत राजस्थान की सभी विधानसभा सीटों पर अपनी गोटी सेट कर चुके थे, और जब मुख्यमंत्री बनने का मौका आया तो कह दिया लोकतांत्रिक तरीके से चयन होगा। जिसके पास ज्यादा विधायक हैं वही मुख्यमंत्री बनेगा। जाहिर सी बात है कि अशोक गहलोत के पास राजस्थान में 30 साल से ज्यादा का राजनीतिक कैरियर है जबकि सचिन पायलट के पास महज 10 साल का। ऐसे में अशोक गहलोत के साथी ज्यादा होना लाजमी था और राहुल गांधी के भरोसे बैठे रहे सचिन पायलट मौका गंवा बैठे।

जब भी पायलट समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री बनाने को लेकर नारे लगाते थे, चुपचाप बैठे गहलोत समर्थक कहते थे कि गांधी परिवार में राहुल गांधी का फैसला अंतिम फैसला नहीं होता है। परिवार में और लोग भी हैं जो चीजों को तय करते हैं। कहते हैं कि हुआ भी यही। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी अशोक गहलोत के पक्ष में हो गए और उनका पलड़ा भारी हो गया। पायलट खेमा कहता है कि यह तो फालतू की बातें हैं कि पायलट के पास विधायक का समर्थन नहीं था, जब मोदी ने हरियाणा में खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया तो कौन से विधायकों से वोटिंग करवाई थी। साफ है कि यहां जब पायलट और गहलोत खेमे की बात होती है तो बात सिर्फ इन दोनों नेताओं के खेमे भर की नहीं रह जाती है, बात दिल्ली तक जाती है और लोग कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर आलाकमान के घर भी कई खेमे हैं।

बाकी नेताओं में और सचिन पायलट में एक फर्क है। ये थोड़ी बहुत बगावत कर लेते हैं क्योंकि इन्होंने अपना ज्यादा जीवन राज्य के बाहर बिताया है। विदेशों में पढ़े हैं, युवा हैं, संघर्ष करने का माद्दा है, जाति का मजबूत आधार है और राहुल गांधी का साथ है। इसलिए लोगों को लग रहा है कि सचिन पायलट किसी बेहतर मौके की तलाश में बैठे हैं। उन्हें किसी दिन ऐसा लगेगा कि उनके साथ एक तिहाई विधायक आ सकते हैं तो उसी दिन बगावत कर देंगे। हालांकि सचिन पायलट ने आज तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला है। अपनी नाराजगी भी जताई है तो बेहद नपे तुले शब्दों में। सचिन पायलट जानते हैं कि अशोक गहलोत अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं, कांग्रेस में उनका भविष्य लंबा है। राहुल गांधी भले ही किनारे पड़ गए हो मगर वह गांधी परिवार के मजबूत स्तंभ है। पायलट को लगता है कि अगर मौका मिलेगा तो राहुल गांधी जरूर साथ देंगे। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को इस लड़ाई में अपने-अपने हिस्से का मजा मिल रहा है, मगर मर कांग्रेस रही है। आपको कहीं भी कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। या तो सचिन पायलट खेमे का कांग्रेसी मिलेगा या फिर अशोक गहलोत का समर्थक मिलेगा। हर कांग्रेसी आपको यही पूछते मिल जाएगा कि भाई साहब इन दोनों में से कौन रहेगा। गहलोत रहेगा या जाएगा या फिर पायलट की छुट्टी होगी या पायलट मुख्यमंत्री बनेगा। यह कोई नहीं सोचता है कि प्रदेश में कांग्रेस कैसे मजबूत होगी और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए। साफ है पायलट या गहलोत दोनों में से जीते कोई हारेगी तो कांग्रेस ही।

मगर इसका मतलब यह नहीं समझा जाएगा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार को कोई खतरा है। हालांकि राजस्थान में कभी अल्पमत की सरकारें गिरी भी नहीं हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत ने भानुमति का कुनबा जोड़कर चार बार सरकार बनाई मगर वह आसानी से अल्पमत की सरकार चलाते रहे। अशोक गहलोत को तीन में से दो बार अल्पमत की सरकार मिली मगर बहुमत जुटाने के लिए घर से बाहर नहीं निकलना पड़ा। दरअसल राजस्थान की तासीर ऐसी है कि यहां की आबोहवा में बगावत की बू नहीं आती। राज्य में जब पहली बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर सामने आया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पसंद पंडित जय नारायण व्यास तीन बार विधानसभा का चुनाव लड़कर तीनों बार हार गए हों, मगर कांग्रेस ने फिर भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। राजीव गांधी को अशोक गहलोत पसंद थे तो उन्होंने 1998 में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कांग्रेस के कद्दावर नेता परसराम मदेरणा समेत कांग्रेस के राजेश पायलट, शीशराम ओला और नवल किशोर शर्मा जैसे नेताओं को किनारे कर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसा लगा कि राज्य में बगावत हो जाएगी, मगर कानाफूसी के अलावा 5 साल में किसी ने भी आवाज नहीं उठाई।

● जयपुर से आर.के. बिन्नानी

श्रम कानूनों में बदलाव

कारखानों, मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को अहम श्रम कानूनों में तीन साल तक छूट देने पर योगी आदित्यनाथ की सरकार चौतरफा घिर चुकी है। पास अध्यादेश में तीन अधिनियम और एक प्रावधान के अलावा सभी श्रम अधिनियमों को निष्प्रभावी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लॉकडाउन के चलते उद्योगों के आगे आई समस्याओं को ध्यान में रखते हुए श्रम अधिनियमों से 1000 दिन (तीन साल) की छूट देने का फैसला किया है। इसके तहत सरकार द्वारा गत दिनों अध्यादेश भी पास किया गया जिसके **मुताबिक तीन अधिनियम** व एक प्रावधान के अलावा सभी श्रम अधिनियमों को निष्प्रभावी कर दिया गया है। इस पर विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए इसे मजदूर विरोधी अध्यादेश बताया है।

उप्र के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के मुताबिक, 'श्रमिकों के मूलभूत हितों की रक्षा के लिए श्रम कानूनों में जो उनको संरक्षण प्राप्त है, वह यथावत रहेंगे।' उन्होंने कहा- 'इनमें बंधुआ श्रम व उत्पादन अधिनियम, भवन सन्निर्माण अधिनियम (भवन निर्माण में जुटे मजदूरों का पंजीकरण), कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम (किसी आपात स्थिति में मजदूरों को मुआवजे से संबंधित) व बच्चों व महिलाओं के नियोजन संबंधित श्रम अधिनियम (गर्भावस्था और चाइल्ड लेबर लॉ) पूरे लागू रहेंगे। वेतन अधिनियम के तहत वेतन भुगतान की व्यवस्था यथावत रहेगी। वेतन संदाय अधिनियम 1936 की धारा -5 के तहत तय समय सीमा के अंदर वेतन भुगतान का प्रावधान भी लागू रहेगा।'

उप्र के श्रम मंत्री मौर्य की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जिन कारखानों व मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के कार्यालय बंद पड़े हैं उन्हें खोलने के लिए यह छूट दी गई है ताकि बाहर से जो प्रवासी श्रमिक प्रदेश में लाए जा रहे हैं उन्हें बड़े स्तर पर काम मिल सके। ये छूट अस्थाई है। श्रम मंत्री ने कहा, 'उप्र में 38 श्रम कानून लागू हैं लेकिन अध्यादेश के बाद किसी भी उद्योग के खिलाफ लेबर डिपार्टमेंट एनफोर्समेंट नियम के तहत कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस दौरान श्रम विभाग का प्रवर्तन दल श्रम कानून के अनुपालन के लिए अगले तीन साल तक कारखाने और फैक्ट्री में छापेमारी या जानकारी के लिए नहीं जाएगा।'

कांग्रेस के उप्र चीफ अजय कुमार लल्लू ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये मजदूरों के साथ विश्वासघात है। कोरोना की आड़ में तीन सालों के लिए श्रम कानून स्थगित करने का सरकार का फैसला पूंजीपतियों के आगे मजदूरों को 'बंधुआ' की तरह सौंप देना है। लल्लू आगे कहते हैं, 'ऐसे नाजुक वक्त में मजदूरों को राहत देने के बजाय सरकार ने उन पर अपना तानाशाही फैसला थोपा है।'

समाजवादी पार्टी के एमएलसी उदयवीर सिंह ने भी इसे सरकार की मनमानी बताते हुए इसे 'मजदूरों के अधिकारों का हनन' बताया है। उदयवीर सिंह के मुताबिक, 'श्रमिकों को लेकर योगी सरकार देर से जागी और उसके बाद उन्हें उप्र में ही रोजगार देने का बहकावा देकर श्रम कानून में उद्योगों को छूट दे दी।' उप्र के लेबर लॉ एडवोकेट काशीनाथ मिश्रा बदले हुए श्रमिक कानून पर कहते हैं, 'ये अध्यादेश श्रमिकों के हितों के खिलाफ हैं। इससे कई अहम श्रमिक कानून अब निष्प्रभावी हो गए हैं।' वह आगे कहते हैं, 'इनमें मिनिममवेज (न्यूनतम मजदूरी) एक्ट काफी अहम है जिसके मुताबिक एक तय अमाउंट मजदूरों को देना कंप्लसरी (आवश्यक) किया जाता है। सभी उद्योग इसी के तहत ही श्रमिक व मजदूरों का पेमेंट करते हैं लेकिन अब सब अपनी सुविधानुसार करेंगे।' इस कानून में किए गए बदलाव को लेकर लेबर लॉ एडवोकेट काशीनाथ कहते हैं, 'इसके अलावा ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इक्वल रिम्यूनिरेशन (समान पारिश्रमिक) एक्ट, जर्नलिस्ट एक्ट, बोनस एक्ट, प्रोविडेंट फंड से संबंधित एक्ट समेत तमाम अहम एक्ट अब निष्प्रभावी हो गए हैं जिससे मजदूरों के हितों की रक्षा कैसे होगी। उनके खान-पान, स्वास्थ्य से संबंधित कानून भी निष्प्रभावी कर दिए गए हैं। लेबर लॉ में लाए गए अध्यादेश को मंजूरी राष्ट्रपति की ओर से मिलती है। सरकार इसे अब राष्ट्रपति को भेजेगी।'

'श्रमिकों के हित के सारे अहम नियम तो निष्प्रभावी कर दिए गए। न तो पीएफ, न बोनस, न हेल्थ सिक्योरिटी।' अब किसी को उसके काम के बदले पहले जैसा पेमेंट नहीं दिया जाएगा।' वह आगे कहते हैं, 'श्रमिकों को समय से पैसा मिलेगा भी या नहीं इसकी भी अब गारंटी नहीं। उद्योग मालिक सरकार की नाक के नीचे जितनी चाहे उतनी मनमानी कर सकेंगे।' पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जो भी श्रमिक दूसरे प्रदेशों से वापस उप्र आ रहे हैं उनके लिए यहीं पर 'रोजगार की व्यवस्था' की जाए। इसके बाद सरकार की ओर से मनरेगा के तहत बाहर से आए श्रमिकों को रोजगार देने के लिए सभी डीएम व सीडीओ को सभी के जॉब कार्ड बनवाने का आदेश दिया गया था।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

अध्यादेश को हाइलाइट करने से बचती दिखी सरकार

इस अध्यादेश को पारित किए जाने के बीच खास बात ये रही कि गत दिनों ये पारित किया गया लेकिन सरकार की ओर से इसे '**हाइलाइट**' नहीं किया गया जिस तरह से महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश को किया गया था। यहां तक की सरकार के किसी प्रवक्ता की ओर से भी इस पर कोई बयान नहीं दिया गया, वहीं स्थानीय मीडिया में भी मजदूरों के अधिकारों के रक्षा के इतर चर्चा 'महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश' की ही रही। कांग्रेस व सपा नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया जिसके बाद ये चर्चा का विषय बना। सरकार से जुड़े सूत्रों की मानें तो लॉकडाउन के दौर में सरकार की इमेज श्रमिकों के हित में काम करने की बनाने का प्रयास है। ऐसे में इस अध्यादेश को अधिक **हाइलाइट** करने से सभी प्रवक्ताओं को रोका गया।

क्या बिहार में खत्म होगी शराबबंदी?

वर्ष 2016 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ-साफ कहा था कि शराब पीने का शौक रखने वाले बिहार न आएं। तब कई आर्थिक विशेषज्ञों ने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश बड़ी भूल कर रहे हैं। इससे 4000 करोड़ रुपए सालाना घाटा उठाना पड़ेगा। हालांकि मुख्यमंत्री अपने फैसले पर अडिग रहे, क्योंकि तब उन्हें कोरोना वायरस और लॉकडाउन जैसी स्थिति का आभास भी नहीं रहा होगा। अब जब लॉकडाउन से उत्पन्न आर्थिक तंगी से निपटने के लिए कई राज्यों ने शराब की बिक्री का सहारा लिया है। दिल्ली जैसे राज्य में तो 70 प्रतिशत तक वैट बढ़ा दिए हैं, तो क्या इस स्थिति में नीतीश को शराबबंदी हटाने या उसमें कुछ संशोधन के साथ लागू करने की पहल करनी चाहिए?

आर्थिक-सामाजिक मामलों के विशेषज्ञ प्रो. नवल किशोर चौधरी का कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अनप्रेडिक्टेबल व्यक्ति हैं। उन्हें समझना एक तरह से नामुमकिन है। वे कब क्या फैसला ले लेंगे इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। बकौल नवल किशोर चौधरी, ये इस बात से प्रमाणित होता है कि जब 2005 में नीतीश सत्ता में लौटे थे, तो उसके बाद उन्होंने गांव-गांव, गली-गली, शराब की दुकानें खुलवा दी थीं। ये फैसला भी बड़ा ही बेतुका था। पर तब उन्होंने राजस्व वृद्धि की दलील दी थी। तब वे भी सिर्फ पैसा-पैसा ही कर रहे थे और इसे बड़े पैमाने पर एक अभियान के तहत लागू किया गया था। प्रो. चौधरी कहते हैं कि वर्ष 2016 में जब प्रदेश में शराबबंदी कानून लाया गया तो उस समय नीतीश कुमार की सहयोगी रही आरजेडी के भीतरी विरोध के बावजूद उन्होंने इसे लागू कर दिया। हालांकि तब सामने से आकर आरजेडी ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले का समर्थन किया था। शायद वे सामाजिक सरोकार से पीछे नहीं हटना चाहते थे।

शराबबंदी वापस लेने के बारे में जब बिहार सरकार के एक मंत्री से पूछा गया कि जब अन्य राज्य सरकारें इसे लागू कर रही हैं और अच्छा-खासा राजस्व इकट्ठा कर रही हैं। क्या बिहार सरकार भी ऐसा सोच रही है कि शराबबंदी कानून में कुछ संशोधन किया जाए? मंत्री ने तो पहले कहा कि इस पर वे कुछ नहीं कह सकते हैं। बाद में उन्होंने साफ कह दिया कि इस पर अगर कोई बोलेंगे तो सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश ही बोलेंगे। हालांकि प्रो. नवल किशोर चौधरी कहते हैं कि शराबबंदी का कानून को सिर्फ इकोनॉमी के नजरिए से देखना उचित नहीं है। इसका सोशल आस्पेक्ट भी है। प्रो. चौधरी ने कहा कि इसे इस संदर्भ में भी देखने की जरूरत है कि आज कोरोना लॉकडाउन में सारी फैक्ट्रियां बंद हो गईं तो प्रदूषण स्तर में बड़ी कमी आई। यहां तक कि जालंधर से धौलागिरी की पहाड़ियां दिखने लगी हैं। यही बात बिहार में शराबबंदी कानून से जुड़ती है। बिहार में इस कारण क्राइम रेट कम हो गए। युवकों की आदतों में परिवर्तन आया और गरीब तबके की महिलाओं पर अत्याचार में कमी आई है। इसे सिर्फ रेवेन्यू गेन या रेवेन्यू लॉस से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।

वहीं, राजनीतिक विश्लेषक रवि उपाध्याय इस बारे में कहते हैं कि यह सही है कि शराबबंदी कानून के लागू होने से कोषागार पर बोझ बढ़ा है। लेकिन यह एक अच्छी पहल बिहार सरकार ने की थी। हालांकि कई संदर्भों में सोचा जाए तो इस कानून में थोड़ा संशोधन कर इसे लचीला बनाया जा सकता है। लेकिन यह सरकार को सोचना होगा कि इसके दूरगामी क्या परिणाम हो सकते हैं। रवि उपाध्याय कहते हैं कि अगर कानून थोड़ा लचीला होगा तो यह एक अच्छी पहल हो सकती है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। पर यह सरकार अपनी ओर से तय करेगी। जिस तरह से बिहार में संसाधन का अभाव है और अब बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है, ऐसे में केंद्र सरकार के भरोसे ही बैठना कहां तक उचित रहेगा। बकौल रवि उपाध्याय सरकार को अपना रेवेन्यू जनरेट करना ही पड़ेगा। अगर सरकार इस कानून को लचीला बनाती है तो आर्थिक बोझ कुछ हद तक कम हो सकता है। यह रकम बिहार की जनता की बेहतरी के लिए खर्च कर सकती है। हालांकि सिर्फ यही विकल्प नहीं है। साथ ही अन्य सेक्टर जो हैं, उस पर भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा।

● विनोद बक्सरी

जो समाज के हित में नहीं है वैसी इकोनॉमी का क्या

समाजशास्त्री अजय कुमार झा कहते हैं कि शराबबंदी का समाजिक संदर्भ में बेहतरीन इम्पैक्ट है। लंबे समय से ये झूठ फैलाया जाता है कि इससे इकोनॉमी को फायदा होता है। जो समाज के हित में नहीं है वैसी इकोनॉमी का क्या करना। बकौल अजय कुमार झा अगर ऐसा ही है तो वैश्यावृत्ति और अन्य बुराइयों को भी लागू किया जाना चाहिए क्या? अफीम और ड्रग्स को भी लीगेलाइज कर देना चाहिए क्या? ये भी तो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, लेकिन इसका सोशल कॉस्ट कितना पे करते हैं। अजय झा कहते हैं कि जब भी सरकार के पास पैसा आता है वह जनता से ही आता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। शराब का जो एक्सपेंडीचर है, वह तो काफी बड़ा है। इससे बीमारियां होती हैं, अपराध होते हैं, इसके भी तो कॉस्ट होते हैं। झा कहते हैं कि जब शराबबंदी लागू की गई थी तब इसका लॉस 3000 करोड़ से 4000 करोड़ रुपए कहा गया था। अब यह बढ़कर 8000 करोड़ हुआ होगा। लेकिन इसकी भरपाई हमें दूसरे विकल्पों के जरिए करनी चाहिए, न कि शराबबंदी कानून खत्म करके। मेरा तो मानना है कि इसे और भी सख्त किया जाना चाहिए और अभी जो चोरी-छिपे शराब मिल जाती है, वह भी बैन हो।

नापाक कदम

भारत-पाकिस्तान की सीमा पर तनाव बढ़ गया है। सीमा पार कुछ ऐसी गतिविधियां शुरू हो गई हैं, जिनसे भारत नाराज हुआ है और सीमा के अंदर घुसपैठ भी बढ़ गई है, जिससे सुरक्षा बलों की चिंता बढ़ी है।

आमतौर पर कोरोना वायरस की महामारी के समय में इस बात का अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान की ओर से कुछ ऐसा किया जाएगा, जिससे एक नया मोर्चा खुले। हो सकता है कि सुरक्षा बलों को इसका अंदाजा हो क्योंकि यह सालाना परिघटना भी है। मई में पहाडों पर बर्फ पिघलनी शुरू होती है तो सीमा पार से घुसपैठ तेज होती है। सुरक्षा बल हर साल इसका मुकाबला करते हैं। घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान की फौजें संघर्षविराम का उल्लंघन करके फायरिंग भी करती हैं ताकि उनकी आड़ में घुसपैठिए अंदर आ सकें। पर इस बार भी ऐसा होगा इसका अंदाजा नहीं था।

कोरोना की वजह से जितनी परेशानी भारत में है उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल पाकिस्तान में है। भारत में तो फिर भी जांच हो रही हैं और मामले को रोकने का प्रयास हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में न तो जांच की सुविधा है और न मरीजों के इलाज की। मामूली जांच के बावजूद पाकिस्तान में 24 हजार से ज्यादा संक्रमण के मामले हैं और करीब 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद पाकिस्तान अपने इस संकट पर ध्यान देने की बजाय भारत को उलझाने में ज्यादा व्यस्त है। उसने अपने कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित-बाल्टिस्तान इलाके में चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इसका आदेश दिया है। यह भारत को उकसाने वाली कार्रवाई है। पर कूटनीति के जानकार यह भी मान रहे हैं कि ये पाकिस्तानी आवाम का ध्यान कोरोना वायरस और दूसरे अंदरूनी संकट से भटकाने की चाल भी हो सकती है। पर भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता है। तभी विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से इस पर तीखी आपत्ति की है।

दूसरा घटनाक्रम घुसपैठ और सुरक्षा बलों पर हमले का है। गत दिनों 8 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं। भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज सूद के साथ पांच सुरक्षाकर्मी शहीद हुए और उसके एक दिन बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकवादियों के हमले में तीन जवान शहीद हुए। तीन दिन में आठ जवानों का शहीद होना मामूली बात नहीं है। तभी सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा कि पाकिस्तान को आनुपातिक प्रतिक्रिया दी जाएगी यानी पाकिस्तान जिस तरह के काम कर रहा है उसी तरह का जवाब उसे मिलेगा। पर असल में यह मामला आनुपातिक प्रतिक्रिया से काफी आगे निकल गया है। हालांकि उससे ज्यादा प्रतिक्रिया देने का समय अभी नहीं है।

वैसे भारत में भी कारोना वायरस का संकट संभल नहीं रहा है और ऐसे में पाकिस्तान की ओर से हो रही कार्रवाई भारत के लोगों का भी ध्यान भटका सकती है। संभवत: तभी प्रधानमंत्री ने भी गुटनिरपेक्ष देशों के नेताओं की एक वीडियो कांफ्रेंसिंग में गत दिनों परोक्ष रूप से पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने उसका नाम लिए बगैर कहा कि कोरोना वायरस के इस संकट के दौर में भी पाकिस्तान ज्यादा खतरनाक वायरस फैला रहा है। उन्होंने कहा कि वह आतंकवाद फैला रहा है और साथ ही अफवाहें भी फैला रहा है। प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख दोनों के बयान से लग रहा है कि अब पाकिस्तान फिर से फोकस में आया हुआ है।

बहरहाल, यह बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ पाकिस्तान कोरोना वायरस से लड़ने में विफल होने की वजह से अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भारत में घुसपैठ बढ़ा रहा है या आतंकवादियों को प्रोत्साहन दे रहा है या गिलगित-बाल्टिस्तान का मुद्दा उछाल रहा है? ऐसा लग रहा है कि पिछले साल जम्मू-कश्मीर में हुए राजनीतिक बदलाव की वजह से भी पाकिस्तान की मजबूरी है कि वह भारत विरोधी गतिविधियां तेज कराए। गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त में भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद-370 की कई धाराओं को खत्म कर दिया और साथ ही अनुच्छेद 35 ए भी खत्म कर दिया। इसके अलावा राज्य को दो हिस्सों में बांट कर इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। चूंकि यह भारत का घरेलू मसला है और इस वजह से दुनिया के किसी देश से पाकिस्तान को समर्थन नहीं मिला। तभी उसकी मजबूरी है कि वह अपने लोगों को दिखाने के लिए भारत विरोधी कार्रवाई करे।

● बिन्दु माथुर

भारत को उठाने होंगे कारगर कदम

ऐसे समय में भारत सरकार को भी पहल करनी चाहिए और पिछले साल अगस्त में किए गए वादे को जितनी जल्दी हो पूरा करना चाहिए। सरकार ने कहा था कि वह जल्दी से जल्दी जम्मू-कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कराएगी। यह काम जितनी जल्दी होगा उतना अच्छा होगा। इसके साथ ही सरकार को लोकतंत्र की बहाली का काम भी पूरा करना चाहिए। राज्य की विधानसभा नवंबर 2018 से भंग हुई है। चुने हुए प्रतिनिधियों की बजाय सरकारी अधिकारी राज्य चला रहे हैं। इससे भी अंदर ही अंदर लोगों में नाराजगी या कम से कम निराशा होगी, जिसका फायदा पाकिस्तान उठाने का प्रयास कर रहा है। सरकार को चाहिए कि वह जल्दी से परिसीमन का काम पूरा कराए, जेल में बंद नेताओं को रिहा करे और चुनाव कराए। राज्य में चुनी हुई सरकार बन जाने के बाद हालात बदल जाएंगे। लोगों का भरोसा बढ़ेगा और पाकिस्तान के अवसर घटेंगे। अगर केंद्र सरकार का लक्ष्य जम्मू-कश्मीर को मुख्यधारा में लाने का है और असल में जम्मू-कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने का है तो वह राज्य में राजनीतिक गतिविधियां शुरू कराने और लोकतंत्र की बहाली से ही संभव हो पाएगा।

चीन बेचैन

दुनियाभर में कोरोना वायरस फैलाने के संदेह से घिरे चीन को विकसित देश अब घेरने लगे हैं। क्योंकि इस जानलेवा वायरस की वजह से पूरी दनिया में करीब दो लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लाखों लोग इसकी चपेट में अब भी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पक्के तौर पर कमर कसे बैठे हैं और माना जा रहा है कि मौका आते ही वह चीन को सबक सिखाएंगे। वहीं जापान और जर्मनी भी चीन से खार खाए बैठे हैं। इन दिनों चीन जितने आराम से पूरी दुनिया को आफत में डालकर व्यावसायिक गतिविधियां चला रहा है, उसे पूरी दुनिया देख रही है। संभव है कि हालात सामान्य होने तक ये देश चीन पर दबाव कम बनाएं, पर यह तय है कि ये देश चीन को अब चैन नहीं लेने देंगे।

डोनाल्ड ट्रम्प पहले ही कोरोना वायरस को चीनी वायरस बोल चुके हैं। अब जर्मनी, इटली, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत चीन के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। जर्मनी तो चीन को 149 बिलियन यूरो का बिल भी भेज चुका है। जर्मनी ने चीन को यह बिल अपने यहां कोरोना पीड़ितों के इलाज में खर्च और हुए नुकसान की भरपाई के आधार पर भेजा है। यही नहीं जर्मनी ने चीन को जल्द से जल्द इस बिल का भुगतान करने को कहा है। वहीं, इटली भी चीन की तरफ आंखे तरेर रहा है। अमेरिका भी चीन को परिणाम भुगतने की चेतावनी दे ही चुका है। इसके अलावा ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान भी चीन से बदला लेने की फिराक में हैं। कई यूरोपीय देश भी चीन को ही कोरोना वायरस फैलाने के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। इधर, जर्मनी ने चीन को भेजे 149 बिलियन यूरो के बिल में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के इलाज के खर्च के अलावा 27 बिलियन यूरो टूरिज्म, 7.2 बिलियन यूरो फिल्म इंडस्ट्री और जर्मन एयरलाइंस तथा 50 बिलियन यूरो छोटे व्यावसायिक नुकसान की भरपाई को शामिल किया है।

तमाम आरोपों-प्रत्यारोपों के बाद अब यह बात सामने आ रही है कि चीन के वुहान शहर में सेना के लिए काम कर रही एक गोपनीय लैबोरेटरी में एक शोध छात्र की गलती से कोरोना वायरस लीक हुआ था। हालांकि इस बात को चीन अभी तक छिपा रहा है। लेकिन दुनिया के सामने अब चीन की हरकतें सामने आने लगी हैं। क्योंकि चीन की ही कई रिपोर्टों से जाहिर होने लगा है कि हो न हो यह जानलेवा वायरस चीन की ही साजिश का नतीजा है। यही वजह है कि अमेरिका के अलावा दुनिया के कई ताकतवर देश अब चीन से निपटने की भूमिका में दिखने लगे हैं। इसका कारण कोरोना वायरस की वजह से इन सभी देशों के नागरिकों की जान जाना और हर तरह से बेइंतिहा नुकसान होना है।

कोरोना वायरस से दुनियाभर में फैली तबाही से जहां पूरी दुनिया चीन पर नजर रखे हुए है, वहीं यूरोप और अमेरिका चीन से आर-पार के मूड में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कह चुके हैं कि अगर कोरोना वायरस के लिए चीन जिम्मेदार निकला, तो इसके परिणाम उसके लिए ठीक नहीं होंगे। इतना ही नहीं, वे चीन के वुहान शहर में जांच टीम भेजने की पूरी तैयारी किए बैठे हैं। वहीं, ब्रिटेन और दुनिया के करीब डेढ़ दर्जन शक्तिशाली देश चीन की ओर संदेह की नजरों से देख रहे हैं। पिछले एक महीने से अमेरिकी खुफिया एजेंसियां यह जानने की कोशिश कर रही हैं कि क्या चीन ने कोरोना वायरस जानबूझकर फैलाया है? अगर यह बात साबित हो जाती है, तो ट्रम्प की धमकी को हकीकत में बदलते देर नहीं लगेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति कह चुके हैं कि उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर चीनी अधिकारियों से बहुत पहले बात की थी कि अमेरिकी जांच टीम अंदर (वुहान शहर में बनी लैबोरेटरी तक) जाना चाहती है, ताकि पता लगा सके कि वुहान में क्या हो रहा है? लेकिन वे (चीनी सुरक्षा अधिकारी) हमारा स्वागत करने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि चीन यह ठीक नहीं कर रहा है। अगर वह इसका जिम्मेदार निकलता है, तो इसके नतीजे उसे भुगतने ही होंगे। यही नहीं, ट्रम्प डब्ल्यूएचओ और चीन पर मिलीभगत का आरोप तक लगा चुके हैं और उन्होंने डब्ल्यूएचओ को दिए जाने वाले फंड पर रोक लगा दी है।

अगर यह साबित हो गया कि कोरोना वायरस फैलने के पीछे चीन की साजिश है, तो अमेरिका उसके विरूद्ध युद्ध नीति अपना सकता है। अगर ऐसा होता है, तो अमेरिका का साथ कई देश देंगे और हो सकता है कि चीन को इसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ें। शायद यही वजह है कि चीन कोरोना वायरस के फैलने वाले स्थान वुहान शहर में जांच टीमों को आने की अनुमति नहीं दे रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ही नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने भी चीन पर ही संदेह जताया है। इससे तमाम पीड़ित देशों की शंकालु नजरें चीन की तरफ और उठने लगी हैं। अमेरिका के बार-बार कहने पर भी चीन अपने को निर्दोष साबित करने की भरसक कोशिश कर रहा है। यूरोपीय संघ द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियम कड़े किए जाने के बाद यूरोपीय संघ के कई सदस्य देशों ने इन नियमों का कड़ाई से पालन शुरू कर दिया है। नियम कड़े करने से पहले ही यूरोपीय संघ अपने सदस्य देशों को चेतावनी दे चुका था कि वे अपने यहां एफडीआई नियमों को सख्त बनाएं, अन्यथा उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह नियम चीन व्यापारिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और उसके बारगेन हंटिंग को रोकने के लिए लागू किए जा रहे हैं। फिलहाल जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, भारत समेत अनेक देश एफडीआई नियमों को सख्त कर रहे हैं। इटली पहले ही गोल्डन पॉवर लॉ पेश कर चुका है, जिसके अनुसार संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी निवेश पर अंकुश लगाने की बात की गई है। इसके अलावा विदेशी व्यापार, मुख्य रूप से चीन के व्यापार को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी अस्थायी रूप से विदेशी अधिग्रहण के नियमों को कड़ा कर दिया है।

● **अक्स ब्यूरो**

चीन के पास कौन-सा रास्ता?

अगर चीन अमेरिका के साथ-साथ यूरोपीय और एशियाई देशों के कोप से बचना चाहता है, तो उसे सभी देशों से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही जांच में जिद्दी अमेरिका का सहयोग करना चाहिए। यदि चीन ऐसा नहीं करता है, तो उसकी तरफ दुनिया का संदेह और बढ़ता जाएगा। हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन पर सलाह दी थी कि वह कोरोना वायरस को लेकर जानकारी छिपाने की बजाय दुनिया के सभी देशों से बातचीत करे। उन्होंने कहा कि अगर चीन अपने वादे के मुताबिक, वास्तव में कोरोना वायरस की जांच में सहयोग करना चाहता है, तो उसे सभी देशों और उनके वैज्ञानिकों को यह जानने का मौका देना चाहिए कि संक्रमण कैसे शुरू हुआ और यह किस तरह दुनिया में फैला?

तालाबंद घरेलू हिंसा

लॉकडाउन का मूल मकसद सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंस) की अनिवार्यता है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए फिलहाल इसका पूरे जोर-शोर से पालन हो रहा है। ऐसे में इस लॉकडाउन के दौरान परिवार के सभी सदस्य लगभग एक महीने से कमोबेश साथ-साथ ही हैं। बिना किसी काम या अनुमति के चूंकि घर से बाहर निकलना कानूनन गलत है और पुलिसिया कार्रवाई भी हो रही है। अक्सर देखा जाता है कि जब आदमी के पास काम न हो और रोजगार आदि पर भी संकट मंडरा रहा हो, तब घरेलू कलह और हिंसा में बढ़ोतरी हो जाती है। तो क्या लॉकडाउन के समय में भी सामान्य दिनों के मुकाबले घरेलू हिंसा की घटनाएं घट रही हैं या फिर इनका विस्तार हो रहा है?

लॉकडाउन अवधि के दौरान पंजाब, हरियाणा और पड़ोसी राज्य राजस्थान में मिली शिकायतों के आधार पर कहा जा सकता है कि शिकायतों की संख्या कम हुई है, लेकिन घटनाएं कम हुई हैं, इस बारे में नहीं कहा जा सकता। ये शिकायतें ईमेल, फोन या अन्य माध्यमों से आयोग तक पहुंच रही हैं। सामान्य दिनों में पीड़ित पक्ष सीधे तौर पर आयोग तक पहुंच करता है।

अभी शिकायतों की स्थिति जस-की-तस है, क्योंकि मौजूदा हालात में कार्रवाई संभव नहीं है। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष प्रतिभा सुमन के मुताबिक, सामान्य दिनों में राज्य में औसत तौर पर 200 से 250 शिकायतें आती हैं। मौजूदा स्थिति में संख्या में कमी हुई है, लेकिन इसकी वजह घटनाओं में कमी को नहीं, बल्कि पहुंच न सकने की विवशता हो सकती है। गंभीर तरह के मामलों को संबंधित उच्चाधिकारियों के पास भेजा जाता है और ऐसा हो भी रहा है। बाकी शिकायतों के बारे में कामकाज की स्थिति सामान्य होने पर संज्ञान लिया जाएगा।

पंजाब में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है, लेकिन वहां संख्या हरियाणा की अपेक्षाकृत कुछ ज्यादा है। पंजाब महिला आयोग की अध्यक्ष मनीषा गुलाटी की राय में शिकायतों का सिलसिला अनवरत चलता रहता है। स्थिति के मुताबिक संख्या में कमी आ सकती है, लेकिन हालात तो वही हैं। वैसे चौबीसों घंटे साथ रहने की स्थिति बिल्कुल अलग है। ऐसा कभी हुआ नहीं था और न ही इसके बारे में किसी ने कल्पना की होगी। जहां पहले से ही घरेलू हिंसा की जमीन तैयार थी, वहां स्थिति अब भी कमोबेश वैसी ही होगी। मजबूरी के चलते साथ-साथ, लेकिन अलग की मनोवृत्ति कहीं न कहीं खुन्नस के रूप में उभरती है।

देश में घरेलू हिंसा की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इसकी वजह महिला आयोगों की स्थापना और सशक्तिकरण होना है। जागरूकता की कमी और मामले सार्वजनिक होने के डर से कई शिकायतें बाहर नहीं आती। ऐसे मामलों का नतीजा घुट-घुटकर किसी तरह जिंदगी बिता देना या फिर कोई आत्मघाती कदम उठाने तक रह जाता है। दहेज प्रताड़ना से लेकर यौन उत्पीड़न या फिर छिटपुट विवाद का बड़ा मसला बन जाने जैसे कई कारक हैं।

मनोविज्ञान कहता है कि लंबे समय तक साथ रहने से छोटे-मोटे विवाद दूर होने की ज्यादा संभावना है। इस दौरान संवाद की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है। पूरा समय रहता है, जिससे मुद्दे की तह तक पहुंचना ज्यादा आसान होता है। सामान्य दिनों में ऐसा नहीं हो पाता। जरा सी बात पर छोटा विवाद बड़ा हो जाता है और एक पक्ष घर से बाहर चले जाने पर विवश हो जाएगा। लॉकडाउन में ऐसा संभव नहीं है। लिहाजा हल की उम्मीद कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। इसके दूसरे पहलू पर विचार करना भी जरूरी होगा। अगर विवाद ज्यादा बढ़ गया तो क्या हो? चूंकि अब बाहर जाना संभव नहीं, फिर लंबे समय तक के लिए तो सोचा भी नहीं जा सकता। सामान्य दिनों में परिवार के सभी सदस्य हर समय साथ नहीं होते लिहाजा कोई मध्यस्थता नहीं करता। मौजूदा स्थिति में यह संभव है। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि लॉकडाउन की विशेष अवधि में मामलों में कमी आने का यह भी एक कारण हो सकता है। इसे स्थायी हल नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हालातों को देखते हुए यह राहत भरा कदम तो है। वैसे इस समस्या का स्थायी हल भी नहीं है। आपसी विवादों को मिल बैठकर बिना किसी पूर्वाग्रह के दूर किया जा सकता है। लॉकडाउन ने शायद इसकी भूमिका तैयार कर दी है।

● ज्योत्सना अनूप यादव

संयुक्त परिवार में स्थिति बेहतर

लॉकडाउन की अवधि में घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में कमी आनी चाहिए। इसके लिए बहुत से कारण हैं। इस दौरान परिवार के सभी सदस्य साथ हैं। अगर बात करें संयुक्त परिवार की तो फिर स्थिति में सुधार की गुंजाइश और भी ज्यादा है। बड़े बुजुर्ग किसी भी छोटे-मोटे विवाद को दूर करने में अहम भूमिका निभा सकता हैं। सामान्य दिनों के मुकाबले अब स्थिति कुछ अलग है। हर व्यक्ति कोरोना वायरस से भयभीत है। अन्य देशों से मौत के भयावह आंकड़ों से सिहरन-सी दौड़ जाती है। जिंदगी बहुत ही छोटी-सी लगने लगती है। वायरस के डर से मौत के बाद शव न लेने जैसी घटनाओं ने एक वर्ग को जिंदगी के प्रति नजरिया बदलने पर विवश-सा कर दिया है। यह सब स्थायी तो नहीं है। संभव है महामारी निकलने के बाद फिर से वैसे ही हालात होने लगें। लेकिन यह तय है कि इसने बहुसंख्यक वर्ग की सोच को बदल दिया है। ऐसे में घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों की संख्या बढ़ने के मुकाबले उनमें कमी आने की संभावना ज्यादा प्रतीत होती है। हरियाणा में लगभग एक माह के दौरान 100 से भी कम शिकायतें आई हैं। यह संख्या सामान्य के मुकाबले आधे से भी कम है। इनमें भी ज्यादातर मामले गंभीर प्रवृत्ति के नहीं है। इसलिए उन्हें हल करना आसान माना जा सकता है। राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा की घटनाओं के कम या ज्यादा होने का अभी कोई पैमाना नहीं है।

मित्रक दुःख राज मेरु समाना

जीवन एक तरह से युद्ध के समान होता है इस जीवनरूपी नैया में समय-समय पर परेशानियां भी आती रहती हैं। समय-समय पर विभिन्न विपत्तियां आती हैं। इन विपत्तियों में हमें अपनों की पहचान हो पाती है। दुख, मुसीबत में ही परम मित्र की सत्यता का प्रमाण मिलता है। किसी ने यहां तक कहा है कि सच्चा प्यार तो मिल भी जाता है लेकिन सच्चा मित्र मिलना बहुत मुश्किल है। कौन हमारा अच्छा मित्र है जो सदैव हमारे हित के बारे में ही सोचता है और कौन हमारा बुरा मित्र है, इसकी पहचान होना अति आवश्यक है। अच्छे मित्र के बारे में श्रीरामचरितमानस में जिक्र किया है। आइए आज हम आपको श्रीरामचरितमानस की मित्र की पहचान आधारित कुछ बेहतरीन सूक्तियों के बारे में बताएंगे जिनसे हमें सच्चे मित्र के लक्षण के बारे में पता चलेगा।

जे ना मित्र दुःख होहिं।
बिलोकत पातक भारी॥
निज दुःख गिरी संक राज करी जाना।
मित्रक दुःख राज मेरु समाना॥

रामचरितमानस की यह चौपाई कहती है कि जो मनुष्य अपने मित्र के कष्ट को अपना कष्ट या दुख नहीं समझता है, ऐसे लोगों को देखने मात्र से पाप लगता है। कहने का अर्थ है कि ऐसे लोगों से सदैव दूरी बनाए रखनी चाहिए। इसके साथ ही जो व्यक्ति अपने बड़े से बड़े दुख को धूल की तरह मानता है वहीं मित्र के धूल के जैसे कष्ट को किसी पहाड़ की तरह मानता है, असल में वही सच्चा मित्र है।

जिन्ह के असी मति सहज ना आई।
ते सठ कत हठी करत मिताई॥
कुपथ निवारी सुपंथ चलावा।
गुण प्रगटे अव्गुनन्ही दुरावा॥

रामचरितमानस के अनुसार, जो लोग स्वाभाव से कम बुद्धि के होते हैं, मूर्ख होते हैं ऐसे लोगों को आगे बढ़कर कभी किसी के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। एक अच्छा मित्र बनने के लिए एक समझदार इंसान होना भी आवश्यक है क्योंकि ऐसा कहने के पीछे आशय है कि एक सच्चे मित्र का धर्म होता है कि वह अपने मित्र को गलत और अनैतिक कार्य करने से रोके। साथ ही उसे सही रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित करे और उसके गुणों को निखार कर सामने लाने में मदद करे और बुरी आदतों पर विराम लगाते हुए उसे सबके सामने आने से रोकने में भी साथ दे।

देत लेत मन संक न धरई।
बल अनुमान सदा हित कराई॥
विपत्ति काल कर सतगुन नेहा।
श्रुति का संत मित्र गुण एहा॥

रामचरितमानस की इस चौपाई के अनुसार, किसी मनुष्य के पास चाहे कितनी भी धन-दौलत हो लेकिन अगर वह जरूरत के समय उसके मित्र के काम न आए तो व्यर्थ है। इसलिए हर मनुष्य को अपनी क्षमता अनुसार, अपने मित्र की सहायता बुरे समय में अवश्य करनी चाहिए। एक अच्छे और सच्चे मित्र की पहचान यही है कि वह दुख मुसीबत में जो भी बन पड़े अपने दोस्त की मदद के समय तत्पर रहे। वेदों और शास्त्रों में भी कहा गया है कि विपत्ति के और अधिक स्नेह करने वाला ही सच्चा मित्र होता है।

आगे कह मृदु वचन बनाई।
पाछे अनहित मन कुटिलाई॥
जाकर चित अहि गति सम भाई।
अस कुमित्र परिहरेहीं भलाई॥

इस चौपाई के अनुसार, ऐसा मनुष्य जो सामने पड़ने पर तो मीठी-मीठी बात करे, हमारी भलाई की बात कहे लेकिन पीठ पीछे भर-भर कर बुराई करे तो ऐसे मित्र का साथ छोड़ना ही बेहतर है। एक सच्चा दोस्त वही होता है जो जैसा हमारे पीठ पीछे व्यवहार करे वैसा ही हमारे सामने मुंहदेखा व्यवहार करे। ऐसे लोगों से दोस्ती करना घाटे का सौदा नहीं होता है। इसी तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा प्रतीत हो यानी जो मन में आपके प्रति कुटिल विचार, बुरा विचार रखता है हो वह दोस्त नहीं कुमित्र होता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन से निकालने में ही भलाई है।

सेवक सठ नृप कृपन कुनारी।
कपटी मित्र सूल सम चारी॥
सखा सोच त्यागहु बल मोरें।
सब बिधि घटब काज मैं तोरें॥

यह चौपाई कहती है कि जिस तरह एक इंसान को मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुलटा स्त्री से खतरा होता है वैसे ही एक कपटी मित्र भी जीवन में किसी खतरे से कम नहीं होता है। ये चारों ही शूल (कांटे) के सामान होते हैं, इनसे बचना चाहिए। जिस तरह कपटी मनुष्य धोखा देकर ह्रदय को दुखी करता है उसी तरह कपटी मित्र भी हमारे साथ छलावा कर सकता है। जिससे हमें नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हमें सतर्क रहते हुए इन सभी प्रकृति के लोगों से दूर रहना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए मित्र के साथ सदैव विश्वासपूर्ण रिश्ते का निर्वाहन करें ऐसा कोई कृत्य न करें जिससे हमारे दोस्त को दुख या ठेस पहुंचे।

अच्छा मित्र जीवन में बड़ी उपलब्धि है। आजकल लोगों को सिर्फ संबंधों में रुचि है। मित्रता का दायित्व कोई नहीं लेना चाहता। किष्किंधा कांड में श्रीराम मित्रों के लक्षण बता चुके थे। फिर उन्हें स्मरण आया कि कुमित्रों-मित्रों की परिभाषा भी बता दी जाए। वे कहते हैं कि कुमित्र कैसे होते हैं। तुलसीदासजी ने चौपाई लिखी है-

'आगें कह मृदु बचन बनाई।
पाछें अनहित मन कुटिलाई।।
जाकर चित अहि गति सम भाई।
अस कुमित्र परिहरेहिं भलाई।।'

जो सामने तो बना-बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ-पीछे बुराई करता है। हे भाई, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सावधान रहिए। यदि व्यक्ति बहुत कोमल वचन बोल रहा है। सच्चा मित्र स्पष्ट बात करता है। तीसरी बुराई है मन में कुटिलता रखना। कुटिलता तो मित्रता में विष है। एक-दूसरे के प्रति खुला ह्रदय होना चाहिए।

● ओम

गीत

गिरी हूं तो उठूंगी
यह ठान रखा है,
हारी हूं तो जीतूंगी
यह मान रखा है।
परवाह नहीं करती
इस दुनिया की,
इसे बड़े ही करीब से
जान रखा है।
कोई किसी का नहीं
सब स्वार्थी हैं,
किसने रिश्तों का
ध्यान रखा है।
धन दौलत ही सब
कुछ हो गई है,
अमीर ने कब
गरीब मेहमान रखा है।
होशियारी नहीं
आती थी मुझको,
व्यवहार से लोगों ने
दे ज्ञान रखा है।
कमजोर समझते हैं
जमाने वाले,
क्योंकि बचाकर
स्वाभिमान रखा है।
'सुलक्षणा' भरती है
उड़ान गगन में,
पर उसने त्याग
अभिमान रखा है।
भूली नहीं अपना
अतीत कभी भी,
बरकरार खुद का
सम्मान रखा है।

— डॉ. सुलक्षणा

वादा

तुम्हें गिरते देख मैंने पकड़ लिया है, हाथ मत छोड़ना! कसकर पकड़ के रखो वरना तुम गिरे तो मैं भी नष्ट हो जाऊंगी। तुम्हारे सहारे ही तो मैं जमा हूं, नदियों में, तालाबों में, नलों से होते हुए तुम्हारे घरों में।

फिसलती चट्टानों से संभलकर वह उठ ही रहा था कि उसके कान फुसफुसाहट सुनकर खड़े हो गए।

'अरे! अरे! देखना छोड़ना नहीं, किसी भी हाल में नहीं। पीने-नहाने के लिए मैं चाहिए तुम्हें कि नहीं! यदि चाहिए तो फिर कसकर पकड़े ही रहना, वरना उंगली भर रह जाऊंगी मैं।'

झरने के नीचे खड़े होकर पानी से खेलते हुए कानों में कोई आवाज दोबारा से गूंजी तो वह चारों तरफ चकरबकर देखने लगा। अपने कल-कल को पीछे छोड़ती हुई वही आवाज फिर आई तो वह पानी की ओर हाथ बढ़ाए हुए स्टेच्यु की स्थिति में आ गया।

'भरा-पूरा शरीर था कभी मेरा लेकिन तुम्हारे दादा-परदादा ने कीमत नहीं समझी मेरी। तुम भी उन्हीं के नक्शे-कदम पर चलने लगे हो। अब हाथ भर रह गई हूं, हो सके तो मेरी कीमत समझो और कसकर थामे रहो मुझे। जैसे तुम्हारे बाद भी तुम्हारे बच्चे मेरी उंगलियों को छू सकें, क्यों थामे रहोगे न!'

मूर्तिवत उसने हां में अपनी मुंडी हिला दी।

'यदि तुमने भी छोड़ दिया न तो तुम अपने आंसुओं में ही पाओगे मुझे।'

झरने के नीचे खड़ा वह झरने से आते छटांग भर पानी को देख सोच में डूब गया।

'सुनो, तुम मुझे जीवन दो बदले में मैं तुम्हें जीवित रखूंगी, वादा है ये मेरा।'

— सविता मिश्रा 'अक्षजा'

अंधविश्वास

प्रत्येक दिन किसी न किसी व्यक्ति की मौत हो रही थी। पिछले दस दिनों में 15 लोगों की जानें जा चुकी थीं। पूरे गांव में दहशत का माहौल था।

'कोई नहीं बचेगा इस गांव में। अगले महीने तक सब मर जाएंगे। इस गांव को उस फकीर की बद्दुआ लग गई है, जिसके साथ दीपक ने गाली-गलौज और हाथापाई किया था। अगर उस दिन दीपक उस फकीर के मांगने पर बिना हुज्जत किए उसे 500 रुपए दे देता तो आज दीपक हमारे बीच जिंदा होता। खुद तो मरा ही, पूरे गांव के सर्वनाश का आगाज भी कर गया। मैं तो कहता हूं उस फकीर को ढूंढो और सारे गांव वाले मिलकर उससे माफी मांग लो। वह फकीर ही हमें इस कहर से बचा सकता है।' बबलू ने अपना डर प्रकट करते हुए गांव वालों से कहा।

'पागल मत बनो बबलू! गांव वालों की मौत किसी फकीर की बद्दुआ के कारण नहीं बल्कि विषाणु जनित वैश्विक महामारी कोरोना के कारण हो रही है। मैंने पहले भी समझाया था, एक बार फिर समझा रहा हूं अगर जिंदा रहना है तो अपने-अपने घरों में रहो। जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक घर से मत निकलो। हमेशा मास्क लगाकर रखो। सैनिटाइजर का प्रयोग करो। साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दो। सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन करो। फिर देखना किसी को कुछ नहीं होगा।' मास्टर दीनानाथ ने बबलू को समझाते हुए गांव वालों से कहा।

बबलू और उसके कुछ दोस्तों को छोड़कर बाकी गांव वाले मास्टर दीनानाथ की बातों से सहमत थे। बबलू और उसके दोस्त पहले की भांति इधर-उधर घूमते रहे, जबकि बाकी गांव वालों ने मास्टर दीनानाथ की बातों पर अमल करते हुए बबलू और उसके दोस्तों से दूरी बना ली।

तीन महीने पश्चात, बबलू और उसके दोस्तों को छोड़कर बाकी सभी गांव वाले जीवित और स्वस्थ थे।

- आलोक कौशिक

सुपर मॉम

अलग-अलग क्षेत्रों में, विशेष रूप से खेलों में महिलाएं अपनी विशेष पहचान बनाती हैं और देश और दुनिया को गौरवान्वित करती हैं, तो यह किसी सपने को आकार देने जैसा ही होता है। देश-विदेश की ऐसी अनेक महिलाएं हैं जिन्होंने मातृत्व की जिम्मेदारियों को निभाते, घर और खेल के मध्य की कशमकश से महफूज निकलकर कुछ समय के ब्रेक के बाद फिर अपने खेल को न केवल आगे बढ़ाया, अपितु उसे नए मुकाम पर पहुंचा दिया। अपनी प्रतिभा का दमन न करके उससे न्याय किया।

ऐसा ही एक नाम है एमसी मैरीकॉम। विदेश में जहां भारतीय महिला मुक्केबाजों की पहचान उन्हीं से है, वहां देश में महिला मुक्केबाजी के प्रचार-प्रसार की पूरी जिम्मेदारी आज 37 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने संभाल रखी है। विश्वकप मुक्केबाजी इतिहास में वह एकमात्र महिला हैं, जो 6 बार खिताब जीत चुकी हैं। मणिपुर की इस सुपर मॉम को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक के लिए सम्मान स्वरूप महिला मुक्केबाज अंबेसडर नामांकित किया है। राष्ट्रपति पहले ही उन्हें 2016 में राज्यसभा में सदस्य नामांकित कर चुके हैं। इसी साल उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया है। अधिकांश पदक मैरीकॉम ने 2 बच्चों को जन्म देने के बाद जीते हैं। थकान या 'बहुत हो गया' जैसे भाव तो उनसे कोसों दूर हैं।

टेबल टेनिस की लंबी-ऊंची खिलाड़ी मणिका बतरा भी एक ऐसा ही नाम है, जिन्होंने विश्व स्तर पर भारतीय महिला टेबल टेनिस को पहचान दी है। दिल्ली की यह 25 वर्षीय खिलाड़ी लाइम लाइट में तब आई जब 2018 के गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेल में उन्होंने देश को 4 पदक दिला दिए। इनमें एकल स्वर्ण, महिला टीम स्वर्ण, महिला युगल रजत और मिश्रित युगल कांस्य पदक शामिल थे। हालांकि इससे पूर्व 2016 के दक्षिण एशियाई खेल में 4 स्वर्ण जीतकर वह अपनी पहचान बना चुकी थीं। 2018 के एशियाई खेल में भी वह अत्यधिक कड़ी स्पर्धा के बीच मिश्रित युगल में देश के नाम कांस्य पदक कर चुकी हैं। वर्तमान में वह भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी हैं और भविष्य में उनसे और पदकों की आशा की जा सकती है।

विश्व स्तर पर भी कई महिलाओं ने खेल जगत में धूम मचा रखी है। ऐसा ही एक नाम जमैका की फर्राटा चैंपियन शैली एनफ्रेजर का है, जिन्होंने फर्राटा के इतिहास में सर्वाधिक खिताब (महिला) जीते हैं। मात्र 5 फुट कद की होने के कारण 'पॉकेट राकेट' या 'छुटकी' के नाम से ख्यात शैली वास्तव में किसी अजूबे से कम नहीं हैं। 2019 विश्व एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उन्होंने बच्चे को जन्म देने के बाद 32 वर्ष की उम्र में 100 मीटर दौड़ जीतने का कारनामा कर दिखाया। वह अब तक सौ मीटर रेस में 2 ओलंपिक गोल्ड, 4 विश्व चैंपियनशिप गोल्ड जीतकर पूरी दुनिया को चकाचौंध कर चुकी हैं। विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं में वह अब तक सौ, दो सौ और 4×100 रिले रेसों में कुल 17 स्वर्ण पदक, 6 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर जमैका की ओर से सर्वाधिक पदक जीतने वाली खिलाड़ी बन चुकी हैं और उनका यह सफर अभी जारी है। महान ओलंपिक धावक माइकल जॉनसन ने उन्हें सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ महिला फर्राटा चैंपियन का दर्जा दिया है।

उज्बेकिस्तान की जिम्नास्ट ओकसाना चुसोवितना (44) जैसी साहसी मां की बराबरी भला कौन कर सकता है। वह 1992 से लेकर लगातार 7 ओलंपिक में भागीदारी कर चुकी हैं और इस साल टोक्यो ओलंपिक की वॉल्ट स्पर्धा के लिए फिर क्वालीफाई कर चुकी हैं। वह ऐसे खेल में उम्र को मात दे रही हैं, जहां लचीलापन सर्वाधिक आवश्यक है और जहां उनकी प्रतियोगिता अधिकांशत: टीनएजर्स से होती है। मां बनने के बाद वह 2008 ओलंपिक में एकल वॉल्ट में रजत जीत चुकी हैं, जबकि उन्होंने अपना पहला टीम स्वर्ण तत्कालीन सोवियत संघ की टीम की ओर से खेलते हुए 1992 में जीता था। है न दंत कथाओं-सी दास्तान।

महान माताओं की श्रेणी में एक और नाम अमेरिका की सेरेना विलियम्स का है, जिन्होंने पदार्पण के साथ ही टेनिस खेल का तरीका ही बदल दिया और इसे पॉवर टेनिस का रूप दिया। 1999 में पहले ग्रैंड स्लैम से लेकर वह आज तक 23 एकल, 14 युगल और 2 मिश्रित युगल ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। सभी युगल खिताब उन्होंने बड़ी बहन वीनस विलियम्स के साथ जोड़ी बनाकर जीते हैं और यह जोड़ी आज तक फाइनल में अविजित है। इसके अतिरिक्त वह विश्व स्तर पर 73 डब्ल्यूटीए एकल खिताब अलग से जीत चुकी हैं। 2017 में बच्चे को जन्म देने के बाद उन्होंने टेनिस में वापसी की है और 39 की उम्र में भी वह टीनएजर को मात दे रही हैं।

● **आशीष नेमा**

सानिया की सनसनी

सानिया मिर्जा भी ऐसा ही नाम हैं, जो टेनिस में मातृशक्ति का झंडा उठाए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके नाम से ही भारतीय महिला टेनिस की पहचान है। 2003 में प्रोफेशनल बनने के बाद से वह अपने खेल कौशल से धूम मचा चुकी हैं और आज तक भारत की नंबर एक खिलाड़ी के रूप में जानी जाती हैं। भारतीय टेनिस की 'उड़गण' सानिया की अपार क्षमताओं का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वह अब तक एक डब्ल्यूटीए टाइटल और 14 आईटीएफ खिताब (एकल) भी जीत चुकी हैं, हालांकि वह 2013 में एकल टेनिस को अलविदा कह चुकी हैं। इन्हीं उपलब्धियों के कारण उन्हें अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार और पद्मभूषण पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। दो साल के मातृत्व अवकाश से लौटकर इसी साल जनवरी में वह होबार्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट का महिला युगल खिताब नादिया के साथ जोड़ी बनाकर जीती हैं। टेनिस जगत में ही एक और मां बेल्जियम की किम क्लिस्टर्स ने जीवट का परिचय देते हुए 2009 में न केवल अमेरिका ओपन का एकल खिताब जीता, बल्कि अगले साल इस कारनामे को दोहराया। 2011 में ऑस्ट्रेलिया ओपन ग्रैंड स्लैम जीतने के बाद तो उन्होंने खेल प्रशंसकों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया।

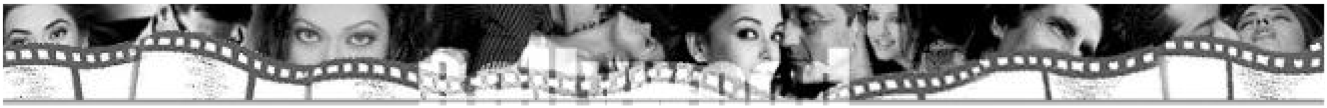

राम-लीला को लेकर कॉपीराइट के झमेले में फंसे भंसाली

फिल्म राम लीला को लेकर कॉपीराइट के झमेले में

डायरेक्टर संजय लीला भंसाली फंसते दिख रहे हैं। दरअसल, पिछले दिनों बॉम्बे हाईकोर्ट ने इरोस इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड को निर्देश दिया था कि इस फिल्म के अधिकार को लेकर जो विवाद है, उस मामले में कंपनी संजय लीला भंसाली प्रोडक्शन को 19.39 लाख रुपए दे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यह रकम 3 हफ्ते के अंदर भंसाली प्रोडक्शन को मिल जाए। अब इरोस ने भंसाली के ऊपर कानूनी कार्रवाई का मन बना लिया है। इरोस ने अपने आधिकारिक बयान में दावा किया है कि वह संजय लीला भंसाली की कंपनी के खिलाफ जल्द उचित कानूनी कार्रवाई करेगी।

'...तो हमें पद्म सम्मान से सम्मानित करे मोदी सरकार'

रामायण की सीता यानी दीपिका चिखलिया ने एक इंटरव्यू में कहा कि दर्शकों का प्यार तो उन्हें खूब मिला, इतना प्यार कि लोगों ने उन्हें असल जिंदगी में भी साक्षात देवी और माता सीता बना दिया, लेकिन उस समय की मौजूदा सरकार (कांग्रेस) ने उनके साथ बेरुखी दिखाई। न तो कभी कोई नैशनल अवॉर्ड मिला, न ही कोई पद्म सम्मान। रामायण में काम करने का मेहनताना भी इतना मामूली था कि तब भी बताने में शर्म आती थी और आज भी शर्म आती है।

30 साल बाद भी रामायण ने कई मामलों में नए कीर्तिमान बना लिए

दीपिका बताती हैं, आज जब रामायण सीरियल को देश-दुनिया में बहुत प्यार मिल रहा है, आज 30 साल बाद भी रामायण ने कई मामलों में नए कीर्तिमान बना लिए हैं। लॉकडाउन के दौरान दूरदर्शन में शुरू हुआ रामायण, हर दिन सोशल मीडिया में ट्रेंड हुआ।

मोदी सरकार से पद्म सम्मान की उम्मीद

हम आपके साथ यह बातचीत कर अवॉर्ड मांग नहीं रहे हैं, लेकिन पॉइंट आउट जरूर कर रहे हैं। अब मोदी सरकार ने जिस तरह रामायण सीरियल को एक बार फिर से दुनिया के सामने लाने का काम किया है, दुनिया ने प्यार भी दिया है। अब आगे मोदीजी को लगे की रामायण की टीम ने कल्चर और लिट्रेचर में कुछ काम किया है तो वह हमें पद्म सम्मानों से सम्मानित करने के बारे में सोचें।

मेहनत की थी, इसलिए आज भी मिल रहा है दर्शकों का प्यार... आज पूरी दुनिया में सबसे यादा संख्या में देखा जाने वाला शो रामायण बन गया है। आखिर रामायण को दर्शकों का इतना प्यार क्यों मिल रहा है। क्योंकि रामायण की पूरी टीम ने जी जान से मेहनत की थी।

ऐसी हॉलीवुड फिल्म नहीं करनी

जिसमें देश का मजाक उड़ेः रणदीप हुड्डा

बॉलीवुड में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनकी पहचान केवल हिंदी फिल्मों और ऑडियंस तक सीमित नहीं रहती है बल्कि सात-समुंदर पार तक जाती है। अब इस लिस्ट में रणदीप हुड्डा का नाम भी जुड़ गया है। बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स ने हॉलीवुड फिल्मों में छोटे-छोटे रोल किए हैं, क्या रणदीप ऐसे रोल को लेकर कंफर्टेबल नहीं हैं? इस पर वह कहते हैं, 'यार, हम लोग थिएटर करके फिल्मों में आए हैं, तो हममें ऐसी ईगो थोड़ी कम होती है। मेरी तो शुरुआत ही मॉनसून वेडिंग से हुई थी, जिसमें मेरे दो-चार सीन ही थे। फिर,

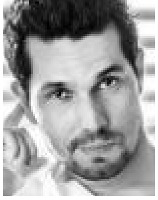

मैंने दीपा मेहता की पिक्चर में भी लीड रोल किया है, जो कनैडियन प्रॉडक्शन थी, तो मैं वेस्टर्न प्रॉडक्शन में काम कर चुका हूं। मुझे मेनस्ट्रीम कमर्शल हॉलीवुड फिल्मों में भी पहले रोल मिले हैं, लेकिन उसमें मजाक उड़ाया जा रहा है या कुछ ऐसा ही था, जो करने को मेरा बिलकुल मन नहीं किया, इसलिए नहीं कि रोल छोटा है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारी छवि अच्छी तरह से नहीं दिखाई जा रही थी।'

3 साल से ट्विटर पर नहीं हूं

विवादों में मत घसीटोः सोनू निगम

पिछले दिनों बॉलीवुड के मशहूर सिंगर सोनू निगम काफी विवादों में रहे हैं। दरअसल उनके कुछ पुराने ट्वीट्स पर लोग उनकी आलोचना कर रहे थे जो उन्होंने मस्जिद से आती अजान की आवाज पर आपत्ति जताते हुए किए थे। सोनू के ट्वीट साल 2017 के थे और इनके कारण लोग उनकी काफी आलोचना कर रहे थे। इस मुद्दे पर सोनू ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया है। सोनू निगम इस समय लॉकडाउन के कारण अपने परिवार के साथ दुबई में हैं। सोनू ने एक मीडिया ग्रुप को दिए स्टेटमेंट में कहा कि यह समय कोरोना जैसे अदृश्य

दुश्मन से साथ रहकर लड़ने का है और इससे ज्यादा प्राथमिकता का कोई काम नहीं है। उन्होंने कहा कि वह पिछले 3 साल से ट्विटर पर नहीं हैं और नहीं चाहते कि किसी भी विवाद में उनका नाम घसीटा जाए। पिछले हफ्ते सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर अदनान सामी भी सोनू के सपॉर्ट में आगे आए थे। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जहां तक वह सोनू निगम को जानते हैं, वह एक बेहतरीन इंसान हैं।

आदमी की देह

बाहर से देखने पर तो वह आदमी ही दिखाई पड़ता है। लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत ही नजर आती है। उसकी देह तो प्रकृति ने आदमी की ही बनाई है, पर उसकी देह में ही संदेह है। निसंदेह संदेह है। कुछ जीवों की प्रजातियां पशु-पक्षी की देह में भी मानव हैं। उसी प्रकार यहां सभी मानव मानव नहीं हैं। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि इस तथ्य की पहचान कैसे की गई है?

जहां तक मैंने समझा सोचा है, यह कोरोना नामक महामारी इस चराचर जगत के लिए एक व्यापक संदेश लेकर आई है। वह प्रत्यक्ष रूप में चर्म चक्षुओं द्वारा दृश्य न भी हो। अन्य अनेक न दिखाई देने वाली चीजों की तरह वह भी दिखाई नहीं देती। लक्षणों के आधार पर उसकी उपस्थिति का विश्वसनीय अनुमान लगा लिया जाता है। जैसे पवन भी दृश्य नहीं है। लेकिन उसका अस्तित्व भी ऐसा है कि उसके बिना मनुष्य तो क्या कोई भी जीवधारी एक निश्चित अवधि के बाद जीवित नहीं रह सकता।

पवन को दिखाई नहीं देने के बावजूद सारा संसार उसके अस्तित्व को प्रणाम करता है। पवन की ही तरह ईश्वर, परमात्मा, गॉड भी दिखाई नहीं देता तो लक्षणों के आधार पर मानव अथवा अन्य जीवों में उसकी परिकल्पना करके उसके अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है। इसी प्रकार से इस विराट ब्रह्माण्ड में अनेक वस्तुएं अस्तित्व में हैं। कृपा, आशीष, वरदान, शाप ये प्रत्यक्षत: दिखाई नहीं देते, किन्तु यथासमय अपना कार्य करते हैं।

चिकित्सकों, पुलिस प्रशासन आदि पर ईंट, पत्थर बरसाने वालों, थूकने वालों, पॉलीथिन की थैलियों में मूत्र भरकर फेंकने वालों, अपने ही शुभचिंतकों को मारने-पीटने वालों को मानव-देह मिलने पर भी वे मानव तो हैं ही नहीं। वे हिंसक पशु, राक्षस, दो मुंहे सर्प, बिच्छु, नरभक्षी आदि कुछ भी हो सकते हैं, किन्तु उन्हें मानव कहलाने का अधिकार तो दिया ही नहीं जा सकता। अब यदि देश के नेता अपने वोटों की तिजोरी भरने की खातिर अपने सिर पर कालीन बिछाकर उन्हें बिठाएं तो कोई क्या कर सकता है। क्योंकि मानव की देह में वे सभी मानव नहीं हैं। इसलिए उनका मौन धारण करना, उनकी लल्लो-चप्पो करना, तेल मालिश करना ये सब यही सिद्ध करते हैं कि ये भी किसी स्तर पर, उनके किसी पूर्व जन्म के रिश्तेदार ही होंगे।

अरे भई! जब उन्हें मनुष्य का चोला मिला है, तो उन्हें अपनी 'अतिमानवता' तो दिखानी ही होगी। इसलिए ऐसे मानव देहधारी अमानवों को सहलाना, फुसलाना बहुत जरूरी हो जाता है। और वे ऐसा कर रहे हैं। उनकी छत्रछाया में पल रहे हैं। फल-फूल रहे हैं। उन्हें मानव कैसे माना जा सकता है जो दूसरों के हकों पर डाका डालकर अपने घरों में आटा, दाल, सब्जी, नमक दैनिक प्रयोग की चीजों को एकत्र करके दुकानों पर बेच रहे हैं और बदले में शैम्पू, क्रीम, पाउडर, लिपिस्टिक खरीद रहे हैं। यह महामारी ऐसे राक्षसों को पहचान कराने के लिए आई है। उन्हें उनके आंगनों में नंगा किया जा रहा है। लेकिन शर्म वह शै है, जो मानवों के लिए है, पशु या राक्षसों के लिए नहीं। उन्हें आए तो कैसे और क्यों?

कोरोना महामारी मानव, अतिमानव और अमानव की पहचान करने के लिए आई है कि कौन-कौन हैं ऐसे जो मानव देह में मानव नहीं हैं। वे उसी कोरोना के रिश्तेदार, भाई, बन्धु, इष्ट, मित्र कुछ भी हो सकते हैं। वह तो एक निश्चित अवधि के बाद चली ही जाएगी, किन्तु आदमी की देह में कौन सा राक्षस, देवता, अतिमानव छिपा बैठा है, इसकी बहुत अच्छी पहचान कराने आई है। वायरस कोरोना कम है, उससे बड़ा वायरस तो ये मानव देहधारी छद्म मानव है, जिसका नंग नाच कभी इंदौर, कभी दिल्ली, कभी निजामुद्दीन, कभी मुरादाबाद कभी देश के अन्य स्थानों में देखने, सुनने और पढ़ने को मिल रहा है। यह मानव की परीक्षा की घड़ी है, जो यह सिद्ध कर चुकी है कि सबसे घातक वायरस यह मानव देह में छिपा हुआ राक्षस ही है।

● डॉ. भगवत स्वरूप 'शुभम'

विश्वसनीय खबरों के लिए पढ़ते रहिए

In Pursuit of Truth

पाक्षिक
अक्स

www.akshnews.com

वार्षिक सदस्यता के लिए संपर्क करें, 150, जोन-1, एम.पी.नगर भोपाल
फोन:0755-4017788,2575777

D-17008

राष्ट्रीय पाक्षिक पत्रिका
अक्स
कोरोना के इस संक्रमण काल में भी
आपके साथ, आपके लिए
राज्य सरकारों द्वारा बताए अनुसार लॉकडाउन/दिशा-निर्देशों का पालन अवश्य करें